LKS

RNI NO.: DELHIN / 2008 / 23928
www.loktantrakishaan.com

दैनिक लोकतंत्र की शान

लोकतंत्र का स्तंभ

दिल्ली से प्रकाशित

शुक्रवार 17 अप्रैल 2026

भारत–ऑस्ट्रिया पश्चिम एशिया में दीर्घकालिक शांति के पक्षधरः मोदी

एजेंसी। नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को दिल्ली में ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर के साथ व्यापक द्विपक्षीय वार्ता की, जिसमें दोनों देशों ने अपने संबंधों को और मजबूत करने के लिए कई अहम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। इस उच्चस्तरीय बैठक में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित एवं स्वच्छ तकनीक, शिक्षा, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, मोबिलिटी और लोगों के बीच संबंधों सहित द्विपक्षीय रिश्तों के पूरे दायरे की समीक्षा की गई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के अनुसार, इस बैठक में रक्षा, तकनीक, व्यापार, नवाचार, कौशल विकास और काउंटर-टेररिज्म जैसे क्षेत्रों में कुल 15 ठोस परिणाम सामने आए। दोनों नेताओं ने विशेष रूप से हाई-टेक्नोलॉजी सहयोग को भारत-ऑस्ट्रिया साझेदारी का केंद्रीय स्तंभ माना। प्रधानमंत्री ने चांसलर के सम्मान में एक लंच होस्ट किया। ऑस्ट्रियाई चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर के दौरे पर खास ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज ने कहा कि आज हैदराबाद हाउस में उन्होंने आपसी रिश्तों के सभी पहलुओं पर बात की और साझा हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। बैठक के बाद दोनों देशों के बीच छह महत्वपूर्ण समझौते, एमओयू और लेटर ऑफ इंटेंट का आदान-प्रदान किया गया। इनमें ऑडियो-विजुअल को-प्रोडक्शन, फूड सेफ्टी एवं मानकों पर सहयोग, निवेश को बढ़ावा देने के लिए फास्ट-ट्रैक मैकेनिज्म की स्थापना और रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट शामिल हैं। इसके अलावा, भारत के यूनाइटेड नेशंस पीसकीपिंग सेंटर और ऑस्ट्रियन आर्म्ड फोर्सेज इंटरनेशनल सेंटर के बीच साझेदारी की घोषणा भी की गई। दोनों पक्षों ने साल 2026 में वियना में संयुक्त स्पेस इंडस्ट्री सेमिनार आयोजित करने और वर्किंग हॉलिडे प्रोग्राम शुरू करने की भी घोषणा की। यह कदम युवाओं और पेशेवरों के बीच संपर्क बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा। सचिव (पश्चिम) ने कहा कि वार्ता के दौरान क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्रॉस-बॉर्डर टेररिज्म सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की कड़ी निंदा की और इसके खिलाफ मिलकर लड़ने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने हाल के आतंकी हमलों की भी निंदा करते हुए आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक अंतरराष्ट्रीय प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि काउंटर-टेररिज्म सहयोग को मजबूत करने के लिए दोनों देशों ने एक संयुक्त कार्य समूह बनाने पर सहमति जताई। यह समूह सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण और उभरती तकनीकों के दुरुपयोग को रोकने में सहयोग करेगा। नेताओं ने आतंकवाद की फंडिंग रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों को लागू करने और यूनाइटेड नेशंस तथा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसे मंचों पर सक्रिय सहयोग जारी रखने का संकल्प दोहराया।

भारत-ऑस्ट्रिया के बीच खाद्य सुरक्षा सहित कई समझौते

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर के बीच गुरुवार को यहां हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल स्तर की महत्वपूर्ण वार्ता हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की गई। दोनों देशों के बीच खाद्य सुरक्षा सहित कई समझौते हुए। बैठक में विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। वार्ता में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने के उपायों पर विचार-विमर्श किया गया। इससे पहले चांसलर स्टॉकर ने नई दिल्ली स्थित राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने वहां पुष्पांजलि अर्पित करते हुए गांधीजी के शांति, अहिंसा और वैश्विक सद्भाव के संदेश को याद किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि ऑस्ट्रिया के चांसलर ने बापू और उनके आदर्शों को याद करते हुए राजघाट पर श्रद्धांजलि दी और उनके सार्वकालिक संदेश पर चिंतन किया।

ज्वलंत मुद्दा | संपादकीय

जांच पर जांच, न्याय अधूरा, जवाबदेही कब तय होगी?

देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती के दावे सरकारें करती है। नियम एवं कानून भी बना दिये जाते है। भ्रष्ट्राचार और गबन जैसे मामलों में अक्सर जांच एजेंसियों की कार्यशैली के सामने आरोपियों पर कोई कार्यवाही नहीं हो पाती है। केंद्र की सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन और राज्य स्तर पर लोकायुक्त आर्थिक अपराध अनुसंस्थान और पुलिस जैसी संस्थाएं मौजूद होने के बावजूद, बड़ी संख्या में मामलों का अंत "खत्मा" या सबूतों के अभाव में आरोपियों के बरी होने से होता है। हाल ही में भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा लोकायुक्त की जांच पर सवाल उठाते हुए 35 मामलों में खात्मा आवेदन को अस्वीकार कर दिया है, जो जांच और न्याय व्यवस्था की खामियों को उजागर करता है। ऐसे उदाहरण नए नहीं हैं। हजारों मामलों में यहीं देखने को मिलता है।

वर्षों पहले उजागर हुआ व्यापम स्कैम हो या राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित 2जी स्पेक्ट्रम केस लंबी जांच, भारी खर्च होने के बाद भी अंततः अदालत में कमजोर साक्ष्य के आधार पर आरोपी बरी हो जाते है। जनता के भरोसे को गहरा आघात पहुंचता है। यह प्रवृत्ति संकेत देती है, जांच की गुणवत्ता, साक्ष्य संकलन और अभियोजन की तैयारी में गंभीर कमियां हैं। यहां एक सवाल यह भी उठता है। राजनैतिक दलों द्वारा एक दूसरे के ऊपर गंभीर आरोप लगाये जाते है। राजनैतिक लाभ-हानि के आधार पर झूठे मुकदमें भी दर्ज हो जाते है। जाँच में पर्याप्त सबूत नहीं होने तथा काल्पनिक आरोप होने से त्वरित रूप से राजनैतिक लाभ लेने के लिये सरकारी खजाने से अरबों रूपया इस खेल में सरकारों द्वारा खर्च कर दिये जाते है। सवाल यह है कि जब जांच एजेंसियां लापरवाही या अक्षमता दिखाती हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? इसका एक कारण संस्थागत एवं व्यक्तिगत जवाबदेही का अभाव है। जांच अधिकारी अक्सर राजनीतिक दबाव, संसाधनों की कमी या कानूनी जटिलताओं का हवाला देते हैं।

सरकारें इन विफलताओं को "प्रक्रियागत" कहकर टाल देती हैं। दूसरी ओर, न्यायालय का दायरा मुख्यतः प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर निर्णय देना होता है। फैसले में अदालतें जांच की गुणवत्ता पर टिप्पणी तो कर देती हैं, फैसलों में जाँच एजेंसी के अधिकारी को दंडित करना सीमित परिस्थितियों में ही संभव हो पाता है। फिर भी, यह तर्क व्यवस्था की खामियों को ढंक नहीं सकता है। हर साल अरबों रुपये जांच के नाम पर सरकारी खजाने से खर्च होते हैं। लेकिन यदि परिणाम "ढाक के तीन पात" ही रहे, तो यह न केवल आर्थिक बल्कि नैतिक नुकसान भी है। जरूरत है, जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता के साथ-साथ उनकी सख्त जवाबदेही तय करने की। फेल हुई जांचों की अनिवार्य समीक्षा, दोषी अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई, और अभियोजन तंत्र को मजबूत करना वर्तमान समय की मांग है।

सैयद जकी हैदर | सम्पदक/प्रकाशक
MOBE NO.9911371802
EMAIL. SYEDZAKIHAIDER786@GMAIL.COM

संक्षिप्त समाचार

हरिवंश फिर होंगे राज्यसभा के उपसभापति, विपक्ष निर्वाचन से बनाएगा दूरी

नई दिल्ली। राष्ट्रपति की ओर से नामित हरिवंश ने गुरुवार को राज्यसभा सचिवालय में उपसभापति पद के लिए नामांकन किया।

वे जनता दल(यू) से सदन में दो बार निर्वाचित एवं दोनों बार राज्यसभा के उपसभापति रहे हैं। राज्यसभा में कल उपसभापति का निर्वाचन होगा। विपक्ष ने कुछ मुद्दों पर आपत्ति जाहिर करते हुए निर्वाचन प्रक्रिया से दूरी बनाने का फैसला किया है। इसका अर्थ है कि बिना विरोध हरिवंश फिर से उपसभापति बन जायेंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पोस्ट में कहा कि विपक्ष ने कल निर्वाचन प्रक्रिया से दूर रहने का फैसला किया है। हालांकि इसके पीछे हरिवंश का निरादर करने का कोई ईरादा नहीं है। विपक्ष को उम्मीद है कि हरिवंश अपने तीसरे कार्यकाल में विपक्ष के अनुरोधों के प्रति अधिक सहिष्णु और ग्रहणशील होंगे। जयराम रमेश ने तीन आपत्तियां जताई है। उनका कहना है कि 7 सालों से लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद खाली है। राज्यसभा में राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किसी व्यक्ति को इससे पहले कभी भी उपसभापति पद के लिए विचार नहीं किया गया है। वहीं, उन्हें तीसरी बार मौका देते समय विपक्ष से विचार भी नहीं किया गया। पिछले माह राष्ट्रपति ने हरिवंश को राज्यसभा का सदस्य नामित किया था। हरिवंश नारायण सिंह का 9 अप्रैल को उपसभापति के तौर पर कार्यकाल समाप्त हो गया।

झारखंड में एसआईआर शुरू करने की प्रक्रिया तेज, घर-घर जाएंगे बीएलओ लगाएं स्टीकर

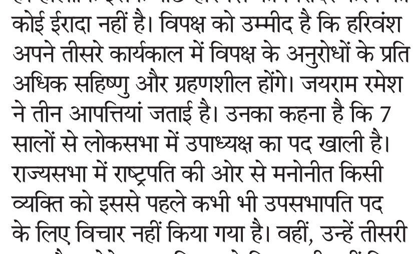

रांची। झारखंड में मतदाता सूची के एसआइआर शुरू होने से पहले प्रशासनिक स्तर पर तैयारियों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। अब तक इन तैयारियों की समीक्षा वर्चुअल बैठकों के जरिए से की जा रही थी, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद अब जिलों में जाकर भौतिक निरीक्षण शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति का आकलन करना और संभावित कमियों को दूर करना है। राज्य के मुख्य चुनाव पदाधिकारी ने जमशेदपुर का दौरा कर जमशेदपुर पूर्वी और जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्रों में तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि पुनरीक्षण प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, सटीक और समावेशी होनी चाहिए। वे आगामी दिनों में अन्य जिलों का भी दौरा कर तैयारियों का जायजा लेंगे। एसआइआर की तिथि को लेकर फिलहाल आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, हालांकि निर्वाचन विभाग के अधिकारियों को अप्रैल के पहले या दूसरे सप्ताह में इसकी घोषणा की उम्मीद थी। अब तक तिथि घोषित नहीं होने से प्रशासनिक स्तर पर थोड़ी अनिश्चितता बनी हुई है।

आरक्षण को महिलाओं का हक बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा

इसे लटकाए रखने के पाप से मुक्ति पाने का अवसर

एजेंसी। नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को लोकसभा में सभी दलों से सरकार की ओर से लाए गए तीन विधेयकों को सर्वसम्मति से पारित कराने का अनुरोध किया ताकि इससे महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का मार्ग प्रशस्त हो सके। उन्होंने कहा कि दशकों से महिला आरक्षण को रोका जाता रहा है। अब इसका प्रायश्चित करने का समय है। वे मानते हैं कि देश की प्रगति में महिलाओं का योगदान है और इस ऋण को हमें स्वीकार करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को लोकसभा में परिसीमन और उसके बाद महिला आरक्षण को लागू करने से जुड़े तीन विधायकों पर एक साथ जारी चर्चा में भाग लिया। चर्चा कल तक चलेगी और अंत में गृह मंत्री इसका जवाब देंगे। विधेयकों में एक संविधान संशोधन विधेयक है, जिसे पारित कराने के लिए सरकार को दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता है। चर्चा में भाग लेते हुए एक तरफ प्रधानमंत्री ने विधेयकों को राजनीतिक बताने के विपक्ष के आरोपों का खंडन किया तो दूसरी ओर स्पष्टीकरण भी दिया कि परिसीमन में किसी भी राज्य के साथ भेदभाव या अन्याय नहीं होगा। साथ ही लोकसभा की सीटों में इजाफा समय की मांग है। इसी को ध्यान में रखते हुए नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद और विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से विधायिका का सामर्थ्य बढ़ेगा। इसे राजनीति के तराजू से नहीं तोलना चाहिए। ये राष्ट्रहित का निर्णय है। उन्होंने कहा, "हम उस अहंकार में न रहें कि हम देश की नारी शक्ति को कुछ दे रहे हैं... जी नहीं! उसका हक है। हमने कई दशकों से रोका हुआ है। आज उसका प्रायश्चित कर उस पाप से मुक्ति पाने का अवसर है। मोदी ने आश्वस्त करते हुए कहा कि सरकार की नीयत साफ है और हमें शब्दों से खेलने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, "मैं आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस सदन से कहना चाहता हूं कि चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूरब हो, पश्चिम हो, छोटे राज्य हों या बड़े राज्य हो... ये निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव या अन्याय नहीं करेगी।

इंडी गठबंधन की बैठक में महिला आरक्षण पर समर्थन, परिसीमन का विरोध

नई दिल्ली। संसद के तीन दिवसीय विशेष सत्र के शुरू होने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अध्यक्षता में विपक्षी इंडी गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई। विपक्षी दलों के सदन के नेताओं ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता खरगे के कार्यालय में मुलाकात कर रणनीति बनाई। इस विशेष बैठक में तीन अहम विधेयक, जिनमें 2029 के लोकसभा चुनावों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने और चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण से जुड़े बिल शामिल हैं पर चर्चा की गई। विपक्ष ने सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 करने और परिसीमन के प्रावधानों पर चिंता जताई है। बैठक में राहुल गांधी, जयराम रमेश, सैयद नसीर हुसैन, प्रमोद तिवारी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) से सुप्रिया सुले, शिवसेना यूबीटी से संजय राउत, तृणमूल कांग्रेस से सागरिका घोष समेत तमाम नेता मौजूद रहे।

राज्यसभा में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित नए सदस्यों ने ली शपथ, कार्यवाही शुक्रवार तक के लिए स्थगित

एजेंसी। नई दिल्ली

संसद की विशेष तीन दिवसीय बैठक के पहले दिन गुरुवार को राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष नितिन नवीन सहित अन्य नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली। राज्यसभा ने सदन की पूर्व सदस्य मोहसिना किदवई और पार्श्व गायिका आशा भोसले को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही 17 अप्रैल को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। तीन दिवसीय बैठक में कल राज्यसभा में महिला आरक्षण की राह प्रशस्त करने वाले संविधान संशोधन विधेयक और दो अन्य विधेयकों पर चर्चा शुरु होगी। आज लोकसभा में इसपर चर्चा हो रही है और कल इन्हें सदन से पारित कराया जाएगा। राज्यसभा में सभापति सीपी राधाकृष्णन ने तेराश गोवाला (भाजपा असम), जोगेन मोहन (भाजपा असम), सुजीत कुमार (भाजपा ओडिशा), डॉ अभिषेक मनु सिंघवी (कांग्रेस तेलंगाना), वेम नरेंद्र रेड्डी (कांग्रेस तेलंगाना), विनोद कुमार तावड़े (भाजपा महाराष्ट्र), अनुराग शर्मा (कांग्रेस हिमाचल प्रदेश), संजय भाटिया (भाजपा हरियाणा), प्रमोद बोरो (यूपीपी (एल) असम), करमवीर सिंह बौद्ध (कांग्रेस हरियाणा), फूलो देवी नेतम (कांग्रेस छत्तीसगढ़), लक्ष्मी वर्मा (भाजपा छत्तीसगढ़), शिवेश कुमार (भाजपा बिहार), रामनाथ ठाकुर (जेडी(यू) बिहार) और उपेन्द्र कुशवाहा (आरएलएम बिहार) को शपथ दिलाई। उपसभापति ने सभी नए सदस्यों को बधाई दी। नितिन नवीन ने एक्स पर कहा, "आज संसद के उच्च सदन, राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेकर राष्ट्रसेवा के एक नए अध्याय का शुभारंभ कर रहा हूं। यह मेरे लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। मैं संकल्प लेता हूँ कि सदन में बिहार की आवाज को मुखरता से उठाते हुए, 'विकसित भारत' के लक्ष्य की प्राप्ति एवं जन-आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ निरंतर कार्य करता रहूंगा।

दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को जेड श्रेणी की सुरक्षा

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। अब उनकी सुरक्षा में सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस के कमांडो चौबीसों घंटे तैनात रहेंगे। दिल्ली विधानसभा सचिवालय के एक बयान में कहा कि बजट सत्र के बाद से बम संबंधी धमकियां आने और हाल में विधानसभा की सुरक्षा में चूक के बाद अध्यक्ष की सुरक्षा को बढ़ाकर जेड श्रेणी का किया गया है। विधानसभा सचिवालय और अध्यक्ष के कार्यालय को 23 मार्च को शुरू हुए बजट सत्र के बाद से छह-सात धमकी भरे ई-मेल मिल चुके हैं। इसके बाद यह कदम उठाया गया है। इन धमकियों के साथ-साथ हाल ही में हुई एक सुरक्षा चूक, जिसमें एक घुसपैठिए ने विधानसभा के गेट तोड़कर अध्यक्ष के वाहन में एक अज्ञात वस्तु रख दी थी।

अशोक चक्र पर गाइडलाइंस बनाने की मांग पर सुनवाई से कोर्ट का इनकार

एजेंसी। नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा पर अशोक चक्र के प्रदर्शन को लेकर गाइडलाइंस बनाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने साफ किया कि इस तरह के मामलों में अत्यधिक भावुक होने के बजाय रचनात्मक कार्यों पर ध्यान देना ज्यादा जरुरी है। मामले की सुनवाई सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बाघची और विपुल एम पंचोली की पीठ ने की। सुनवाई के दौरान पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि इन बातों को लेकर इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है। आपका विचार अच्छा है, आपने अपनी बात रख दी

पीठ ने याचिकाकर्ता को समाज के लिए सकारात्मक कार्य करने की दी सलाह

है। अब यह संबंधित अधिकारियों पर निर्भर करता है कि वे क्या फैसला लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को समाज के लिए कुछ सकारात्मक और रचनात्मक कार्य करने चाहिए, जिससे व्यापक स्तर पर लाभ मिल सके। दरअसल, याचिकाकर्ता ने कोर्ट के सामने अशोक चक्र के प्रदर्शन से जुड़ा एक मुद्दा उठाया था। उसने वाराणसी के एक चौराहे पर लगे अशोक चक्र की तस्वीर पेश करते हुए कहा कि इसके स्वरूप को लेकर गलत संदेश जा रहा है। याचिकाकर्ता के मुताबिक एक बच्चे ने इसे "बंदर जैसा" बताया, जिससे उसे ठेस पहुंची। याचिका में केंद्र सरकार और अन्य संबंधित प्राधिकरणों को निर्देश देने की मांग की गई थी कि राष्ट्रीय ध्वज पर अशोक चक्र के सही और मानक स्वरूप के प्रदर्शन के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएं। हालांकि, कोर्ट ने इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए इसे नीतिगत मामला माना और कहा कि इस पर निर्णय लेना संबंधित अधिकारियों का काम है।

आसनसोल में गरजे योगी आदित्यनाथ, बोले - भाजपा सरकार बनी तो खत्म होगा माफिया राज

एजेंसी। कोलकाता

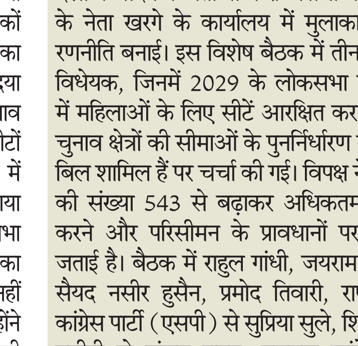

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। पहले चरण के मतदान से पहले सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को आसनसोल के बाराबनी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उम्मीदवार अरिजीत रॉय के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में भारी भीड़ उमड़ी और मुख्यमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोग घरों की छतों, वाहनों और पेड़ों तक पर चढ़े नजर आए। माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में रंगा हुआ था। अपने संबोधन में योगी आदित्यनाथ ने तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस और वामपंथी दलों पर जमकर हमला बोला और राज्य की मौजूदा स्थिति को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में आज अराजकता, दंगे और माफिया राज का माहौल है। विकास के लिए आने वाला पैसा कटमनी और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में राज्य को टेरर, माफियाराज और भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया है, जिससे आम जनता, खासकर युवाओं और महिलाओं में असुरक्षा का माहौल पैदा हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सैंड माफिया, कोल माफिया और लैंड माफिया का बोलबाला है और ये लोग राज्य के संसाधनों पर कब्जा जमाए हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र से आने वाले विकास के धन को भी हड़प लिया जाता है और जनता तक उसका लाभ नहीं पहुंचता। मुख्यमंत्री ने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि वे भाजपा उम्मीदवार अरिजीत रॉय को भारी मतों से विजयी बनाएं। उन्होंने कहा कि "अरिजीत" का अर्थ ही होता है जो शत्रु पर विजय प्राप्त करे, इसलिए जनता को उन्हें जीताकर राज्य में बदलाव लाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि भाजपा की डबल इंजन सरकार बनने पर राज्य की सभी समस्याओं का तेजी से समाधान होगा और कानून व्यवस्था मजबूत होगी। उन्होंने उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि लगभग नौ वर्ष पहले वहां भी यही स्थिति थी, जहां हर दूसरे-तीसरे दिन दंगे होते थे, अपराध चरम पर था और माफिया का दबदबा था।

राष्ट्रपति भवन में 18 अप्रैल को 'चेंज ऑफ गार्ड' समारोह नहीं होगा

नई दिल्ली। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में होने वाला साप्ताहिक 'चेंज ऑफ गार्ड' समारोह इस शनिवार (18 अप्रैल) को आयोजित नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन के अनुसार यह निर्णय कोरिया के राष्ट्रपति के आगामी राजकीय दौरे के मद्देनज़र होने वाली औपचारिक स्वागत समारोह के पूर्वाभ्यास के कारण लिया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निमंत्रण पर कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग 19 से 21 अप्रैल तक भारत की राजकीय यात्रा पर आएंगे। यह उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा होगी। उनके साथ प्रथम महिला किम हे क्युंग तथा मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा।

Mfg & mkt by.. ANGEN PHARMACEU-TICALS (OPC) PRIVATE LIMITED

Distributorship ke liye contact Karen .
(9315755133 / ya email Karen)
angenpharmaceuticals@gmail.com

खास खबर

सुप्रीम कोर्ट में प. बंगाल के डीजीपी और मुख्य सचिव के तबादलों से संबंधित याचिका खारिज

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी का ट्रांसफर करने के निर्वाचन आयोग के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसा हर जगह होता है, पहली बार नहीं हो रहा है। हालांकि, कोर्ट ने याचिकाकर्ता की इस दलील पर सहमति जताई कि निर्वाचन आयोग को इस संबंध में राज्य सरकार से बातचीत करनी चाहिए थी। कोर्ट ने कहा कि इस बिंदु पर कानून की बात खुली रहेगी। याचिका वकील अरका कुमार नाग ने दायर की थी। इसके पहले याचिकाकर्ता ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि ट्रांसफर होने वाले अधिकारियों की जगह दूसरे अधिकारियों ने ले ली है।

सुप्रीम कोर्ट से अनिल अंबानी को राहत नहीं, लोन खाते को फर्जी करार देने से इनकार

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने अनिल अंबानी को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने अनिल अंबानी के लोन खाते को फर्जी करार देने के बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीबीआई और इंडियन ओवरसीज बैंक के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके पहले अनिल अंबानी ने बांबे उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच ने अनिल अंबानी को राहत दी थी। उसके बाद बैंकों ने उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच में सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती दी थी। डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद अनिल अंबानी ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। सुनवाई के दौरान अनिल अंबानी की ओर से पेश कपिल सिब्बल ने कहा कि अंतरिम आदेश को इस तरह पलटना ठीक नहीं है। खाते को फर्जी करार देने से उन्हें कोई पैसा उधार नहीं देगा। तब चीफ जस्टिस ने कहा कि अनिल अंबानी के खिलाफ पैसों की हेराफेरी की सीबीआई और ईडी जांच कर रही है।

केजरीवाल ने लखनऊ के विकास नगर स्थित झुग्गी बस्ती में लगी आग पर जताया दुख

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आआपा) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को लखनऊ के विकास नगर स्थित झुग्गी बस्ती में लगी आग पर दुख व्यक्त किया। अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए लिखा कि लखनऊ के विकास नगर स्थित झुग्गी बस्ती में लगी भीषण आग में अपना सब कुछ खो देने वाले पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहन संवेदनाएं। उन्होंने कहा कि इन गरीब परिवारों के सिर से सिर्फ छत नहीं गई है, बल्कि उनके जीवनभर की जमा-पूंजी और रोजगार के साधन आग में जलकर खाक हो गए हैं। केजरीवाल ने सरकार से अपील की है कि पीड़ित परिवारों के लिए जल्द से जल्द उचित राहत, रोजगार एवं पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। उल्लेखनीय है कि, लखनऊ के विकास नगर की झुग्गी बस्ती में बुधवार शाम में आग लगने की घटना सामने आई। जिसमें 200 से ज्यादा झुग्गियां जल कर राख हो गई।

अनिवार्य मतदान वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने देशभर में हर मतदाता के लिए मतदान की अनिवार्यता की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि ये नीतिगत मामला है और अदालत इस पर कोई आदेश जारी नहीं कर सकती है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता अजय गोयल को निर्देश दिया कि वो सक्षम प्राधिकार के पास अपनी मांगों को लेकर जाएं। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई मतदान नहीं देना चाहता है तो उससे कोर्ट को नहीं निपटना चाहिए। याचिका में मांग की गई थी कि हर मतदाता के लिए मतदान अनिवार्य करने का दिशा-निर्देश जारी किया जाए और जो मतदाता वोट नहीं दे रहे हों, उन्हें सरकारी लाभ देना बंद कर देना चाहिए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जिस देश में कानून का शासन होता है और वो लोकतंत्र में विश्वास करता है, वहां ये उम्मीद की जा सकती है कि हर मतदाता वोट डाले। लेकिन अगर कोई मतदान नहीं करना है तो सबसे ज्यादा जरुरी है जागरुकता फैलाना। क्या कोर्ट उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश जारी करे। हम क्या कर सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अगर हम ये स्वीकार करें तो जस्टिस बागची को मतदान डालने के लिए पश्चिम बंगाल जाना होगा, भले ही वो कार्यदिवस हो। अगर कोई गरीब व्यक्ति है और उसे कमाना जरुरी है तो वो मतदान कैसे करेगा।

मंत्री सिरसा ने किया डीकेवीआईबी कर्मचारियों के वित्तीय उन्नयन से जुड़े मुद्दों का समाधान

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। दिल्ली के उद्योग, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने गुरुवार को दिल्ली सचिवालय में दिल्ली खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड (डीकेवीआईबी) के कर्मचारियों से मुलाकात की। इसके दौरान उन्होंने कर्मचारियों के 32 साल पुराने वित्तीय उन्नयन से जुड़े मुद्दे का समाधान किया, जो सीधे उनके पदोन्नति से जुड़ा हुआ है। इस फैसले से डीकेवीआईबी के रिटायर्ड कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा, जो लंबे समय से इस फैसले का इंतजार कर रहे थे। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, 'जो मामला पिछली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आआपा) सरकारों में दशकों तक लटका रहा, उसे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में आज हमने सुलझाकर कर्मचारियों को उनका हक दिलाने का काम किया है।' उन्होंने कहा कि किसी का हक न मारा जाए और सबको उसका सही सम्मान मिले, यही हमारी सरकार का असली मकसद है। जनसेवा की असली भावना के साथ हमारी सरकार काम कर रही है।

उप्र में ट्रेटा पैक में शराब बिक्री के विरूद्ध याचिका, सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में टेट्रा पैक में शराब की बिक्री के विरुद्ध दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि वे संबंधित अधिकारियों को याचिका की प्रति प्रतिवेदन के रूप में दें। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जो लोग शराब खरीदना चाहते हैं वे किसी भी रूप में खरीद सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि उप्र सरकार की आबकारी नीति में टेट्रा पैक में शराब बेचने की साफ-साफ अनुमति दिखाई नहीं देती है। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि 4 फरवरी 2025 को एक प्रशासनिक फैसले के जरिये छोटे पैक में शराब की अनुमति दी गई थी। यह नीति रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। याचिका मीनाक्षी तिवारी ने दायर की थी। याचिका में टेट्रा पैक में शराब की बिक्री की अनुमति पर सवाल खड़े किए गए थे। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि टेट्रा पैक में शराब उपलब्ध होने से बच्चों और छात्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि उप्र में छात्र इन छोटे पैक्स को आसानी से स्कूल या कॉलेज में ले जा सकते हैं।

फर्जी प्रोफाइल बनाकर 500 से ज्यादा महिलाओं को ठगा, आरोपित गिरफ्तार

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। दक्षिण-पश्चिम जिले की साइबर थाना पुलिस ने ऑनलाइन डेटिंग और मैट्रिमोनियल ऐप्स के जरिए महिलाओं को निशाना बनाकर करोड़ों की ठगी करने वाले एक शातिर साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपित की पहचान आनंद कुमार (35) के रूप में हुई है। वह पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। वह फर्जी पहचान बनाकर महिलाओं को प्रेमजाल में फंसाता था और बाद में ब्लैकमेल कर पैसे ऐंठता था। दक्षिण पश्चिम जिले के पुलिस उपायुक्त अमित गोयल ने गुरुवार को बताया कि आरोपित ने अब तक देशभर में 500 से अधिक महिलाओं को अपना शिकार बनाया और करीब दो करोड़ रुपये की ठगी व उगाही की। गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से 4 स्मार्ट फोन, 8 सिम कार्ड, तीन डेबिट कार्ड के अलावा ठगी के पैसों से खरीदे गए चार सोने के कंगन और पांच सोने की चेन बरामद की गई

हैं। आरोपित के खिलाफ पहले भी दिल्ली और गाजियाबाद में दो मामले दर्ज हैं। पुलिस उपायुक्त के अनुसार मामले का खुलासा उस समय हुआ जब एक महिला ने साइबर थाने में शिकायत दी कि 'वैभव अरोड़ा' नाम के एक व्यक्ति ने उससे शादी का झांसा देकर करीब सात लाख रुपये ठग लिए। आरोपित ने पहले डेटिंग ऐप पर महिला से संपर्क किया और खुद को एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बताकर भरोसा जीता। इसके बाद वह इंस्टाग्राम और फिर व्हाट्सएप पर बातचीत करने लगा। धीरे-धीरे उसने भावनात्मक संबंध बनाकर शादी का वादा किया। आरोपित ने खुद को और विश्वसनीय दिखाने के लिए 'आनंद' नाम से एक और फर्जी किरदार खड़ा किया, जिसे उसने अपना करीबी दोस्त बताया। बाद में उसने मेडिकल इमरजेंसी और बिजनेस में नुकसान का बहाना बनाकर महिला से पैसे ऐंठ लिए। जब महिला ने पैसे वापस मांगे तो आरोपित ने संपर्क तोड़ लिया और व्हाट्सएप पर यह झूठी सूचना भेज दी कि 'वैभव' की मौत हो गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर थाना पुलिस की एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने सोशल मीडिया अकाउंट्स, आईपी लॉग, मोबाइल नंबर और बैंक लेनदेन का गहन विश्लेषण किया। तकनीकी जांच के दौरान आरोपी के मोबाइल नंबर पश्चिम बंगाल के 24 परगना क्षेत्र में सक्रिय मिले। इसके बाद पुलिस टीम ने वहां छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपित एक साथ कई फर्जी पहचान जैसे वैभव अरोड़ा, डॉ. रोहित बहल, तरुण, आनंद शर्मा और शिखा के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट चला रहा था। वह खुद को कभी डॉक्टर, कभी वकील, कभी कारोबारी तो कभी फिल्म प्रोड्यूसर बताकर महिलाओं को झांसे में लेता था। पुलिस अधिकारी के अनुसार आरोपित पहले महिलाओं से दोस्ती करता, फिर भावनात्मक रिश्ता बनाता और निजी फोटो-वीडियो हासिल कर लेता था। बाद में इन्हीं फोटो-वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर पैसे वसूलता था। ठगी से मिली रकम का बड़ा हिस्सा वह ऑनलाइन गेमिंग और निजी खर्चों में उड़ा देता था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपत बेहद शातिर तरीके से कई सिम कार्ड और मोबाइल फोन बदलकर अपनी पहचान छिपाता था, जिससे उसे पकड़ना चुनौतीपूर्ण हो गया था। फिलहाल पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है और अन्य पीड़ितों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।

महिला आरक्षण ऐतिहासिक कदम, विपक्ष का विरोध निंदनीयः वीरेन्द्र सचदेवा

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। संसद के तीन दिवसीय विशेष बैठक के पहले दिन लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े तीन विधेयक पेश होने पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि 16 अप्रैल का दिन भारत के इतिहास में स्वर्णिम दिन के रूप में दर्ज होगा। सचदेवा ने संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026, डिलिमिटेशन बिल, 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, विधेयकों पर कहा कि 1947 में देश को स्वतंत्रता मिली थी और अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को नीति-निर्माण में भागीदारी का अधिकार मिल रहा है। सचदेवा ने कहा कि 2014 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण और स्वरोजगार योजनाएं शामिल हैं। अब संसद और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू कर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि इस ऐतिहासिक विधेयक को बाधित करने की कोशिश निंदनीय है। कांग्रेस, समाजवादी दलों और अन्य सहयोगी पार्टियों ने लंबे समय तक महिलाओं को पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं दिया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने आम आदमी पार्टी पर भी हमला बोलते हुए कहा कि संसद में 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' का विरोध कर पार्टी ने अपना "महिला विरोधी चेहरा" उजागर किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी महिलाओं के सशक्तिकरण के मुद्दे पर गंभीर नहीं है।

अशोक लेलैंड ने लॉन्च किए DOST और DOST+ XL के 'ट्विन फ्यूल' वेरिएंट

लोकतंत्र की शान

दिल्ली : हिंदुजा ग्रुप की प्रमुख भारतीय कंपनी और देश की अग्रणी कमर्शियल वाहन निर्माता, अशोक लेलैंड ने आज अपने लोकप्रिय लाइट कमर्शियल व्हीकल – DOST और DOST+ XL के ट्विन फ्यूल वेरिएंट लॉन्च करने की घोषणा की। यह कदम एलसीवी सेगमेंट में ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार बेहतर और भरोसेमंद समाधान प्रदान करने की कंपनी की प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है। इन वाहनों का अनावरण अशोक लेलैंड के एलसीवी, आईओ, डिफेंस और पावर सॉल्यूशंस के प्रेसिडेंट श्री अमनदीप सिंह ने एलसीवी बिजनेस हैड श्री विप्लव शाह की उपस्थिति में किया। नए ट्विन फ्यूल मॉडल्स एडवांस तकनीक से लैस हैं, जिससे वाहन सीएनजी और पेट्रोल के बीच आसानी से स्विच कर सकते हैं। इससे ग्राहकों को अधिक लचीलापन और भरोसा मिलता है। यह तकनीक सीएनजी वाहन उपयोगकर्ताओं

की एक बड़ी समस्या—रेंज की चिंता और रास्ते में सीएनजी पंप न मिलने का डर—को दूर करती है। अब ग्राहक बिना किसी रुकावट के लंबी दूरी तय कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर सीएनजी से पेट्रोल पर स्विच कर सकते हैं। अशोक लेलैंड के एलसीवी, आईओ, डिफेंस और पावर सॉल्यूशंस के प्रेसिडेंट श्री अमनदीप सिंह ने इस अवसर पर कहा, "DOST और DOST+ XL के ट्विन फ्यूल वेरिएंट का लॉन्च हमारी टिकाऊ और ग्राहक-केंद्रित इनोवेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये वाहन ऑपरेटरों को साफ और पर्यावरण-अनुकूल सीएनजी मोड में चलाने की सुविधा देते हैं और जरूरत पड़ने पर पेट्रोल बैकअप भी उपलब्ध कराते हैं। इससे ऑपरेटिंग लागत कम होती है और उत्सर्जन भी घटता है। हमें विश्वास है कि यह LCV सेगमेंट में नए मानक स्थापित करेगा।" अशोक लेलैंड के एलसीवी बिजनेस हैड श्री विप्लव शाह ने कहा, "DOST रेंज पहले से ही लाखों छोटे व्यवसायों का भरोसा जीत चुकी है। ट्विन फ्यूल वेरिएंट के साथ हम छोटे व्यापारियों और फ्लीट ऑपरेटरों को अधिक विकल्प और बेहतर दक्षता दे रहे हैं। ये वाहन सीएनजी पर कम लागत में चल सकते हैं और पेट्रोल से लंबी दूरी तय करने में मदद करते हैं, जिससे उपलब्धता की चिंता खत्म होती है। साथ ही, कम उत्सर्जन से कार्बन फुटप्रिंट घटता है और भारत के सस्टेनेबिलिटी लक्ष्यों को समर्थन मिलता है।" ट्विन फ्यूल DOST की खासियत है 1218 किलोग्राम की पेलोड क्षमता और 400 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज। इसमें 120 लीटर का बड़ा सीएनजी टैंक और आपात स्थिति के लिए 5 लीटर का पेट्रोल टैंक दिया गया है। वहीं ट्विन फ्यूल DOST+ XL में 1410 किलोग्राम की पेलोड क्षमता, 148 लीटर का सीएनजी टैंक और 5 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलता है, जिससे इसकी रेंज 500 किलोमीटर तक हो जाती है। इससे व्यापार के अधिक अवसर और बेहतर कमाई की संभावना बढ़ती है। DOST रेंज में ट्विन फ्यूल तकनीक जोड़कर अशोक लेलैंड शहरी और अर्ध-शहरी लॉजिस्टिक्स ऑपरेटरों, लास्ट-माइल डिलीवरी व्यवसायों और छोटे उद्यमों की बदलती जरूरतों को पूरा कर रहा है। अशोक लेलैंड लगातार अपने पोर्टफोलियो में भविष्य के लिए तैयार समाधान पेश करता रहा है। ट्विन फ्यूल DOST और DOST+ XL इस सेगमेंट में कंपनी की स्थिति को और मजबूत करते हैं, जहां भरोसेमंद प्रदर्शन के साथ नई तकनीक का मेल है। कीमत की बात करें तो ट्विन फ्यूल DOST की शुरुआती कीमत 8.20 लाख (एक्स-शोरूम) है, जबकि ट्विन फ्यूल DOST+ XL की शुरुआती कीमत 8.75 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है।

प्रियंका बोलीं- मौजूदा लोकसभा सीटों में से महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, साथ ही एससी-एसटी, ओबीसी महिलाओं को आरक्षण मिले

लोकतंत्र की शान, संवाददाता जीशान अली

नई दिल्लीः कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने लोकसभा में मांग की है कि महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मौजूदा 543 सीटों के भीतर ही दिया जाए और इसके साथ इसमें एससी-एसटी तथा ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा होगा तो महिला आरक्षण आज ही पारित हो सकता है। संविधान संशोधन विधेयक और परिसीमन विधेयक पर बोलते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि "अगर प्रधानमंत्री इस ऐतिहासिक कदम को ईमानदारी से उठा रहे होते, तो पूरा संसद इनके साथ एकजुट होकर इसे पारित करता" और "सही निर्णय ले लें, हम सब उनके साथ खड़े रहेंगे"।<प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार की पोल खोलते हुए कहा

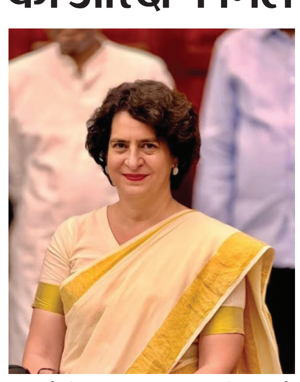

कि मोदी सरकार जनता की आंखों में धूल झोंककर देश की अखंडता पर बहुत बड़ा हमला कर रही है। महिला आरक्षण की बातें कर गुप्त तरीके से ओबीसी वर्ग का हक छीना जा रहा है। कुछ प्रदेशों की ताकत कम करके लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और अगले चुनाव के लिए भाजपा की मजबूती का ढांचा बनाया जा रहा है।

अली हुसैन आसिम बिहारी के सपनों को साकार करने का संकल्प लेंः वक्ताओं का आह्वान

» 137वें जन्मदिवस पर पसमांदा संगठनों का भव्य सम्मेलन, अधिकार और बराबरी की लड़ाई तेज़ करने का ऐलान

लोकतंत्र की शान

नई दिल्लीः प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, दिल्ली में ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के बैनर तले एक महत्वपूर्ण और गरिमामय सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन पसमांदा आंदोलन के प्रणेता अली हुसैन आसिम बिहारी के 137वें जन्मदिवस के अवसर पर आयोजित हुआ, जिसमें देशभर से आए सामाजिक कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। सम्मेलन में वक्ताओं ने अली हुसैन आसिम बिहारी के संघर्ष और उनके विचारों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका आंदोलन आज भी पूरी तरह जीवंत और प्रासंगिक है। वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि जब तक पसमांदा समाज को सम्मान, बराबरी और उनके संवैधानिक अधिकार नहीं मिलते, तब तक अली हुसैन आसिम बिहारी का सपना अधूरा रहेगा। कार्यक्रम का संचालन ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय

प्रवक्ता हाफ़िज़ गुलाम सरवर ने किया। सम्मेलन में प्रो. डॉ. फिरोज़ मंसूरी, शारिक अदीब अंसारी, मेराज राइन, अब्दुल हकीम होवारी, गफ्फार सलमानी, तौफीक अहमद शाह, सलीम अहमद कुरैशी, मौलाना जाहिद आलम मजाहिरी, निखत परवीन, डॉ. अब्दुस्सलाम, अफशां बेगम, अलाउद्दीन सलमानी और समीर सैफी सहित कई प्रमुख हस्तियों ने अपने विचार रखे। मेराज राइन, डायरेक्टर पसमांदा विकास फाउंडेशन ने अपने संबोधन में कहा कि समय की मांग है कि मुसलमान सरकारी योजनाओं का भरपूर लाभ उठाएं, ताकि वे सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें। उन्होंने प्रधानमंत्री से पसमांदा आयोग के गठन की भी अपील की।

पड़ोसी प्रथमः भारत के सहयोग से भूटान में 2 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास

लोकतंत्र की शान

थिम्पू। भारत के सहयोग से भूटान के गेदू कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज (जीसीबीएस) में 15 अप्रैल को एक नए अकादमिक ब्लॉक का शिलान्यास किया गया। यह परियोजना भारत और भूटान के बीच मजबूत विकास साझेदारी का एक हिस्सा है। इस नए ब्लॉक का निर्माण कॉलेज की बुनियादी ढांचागत सुविधाओं को बढ़ाने और छात्रों के लिए बेहतर शैक्षणिक वातावरण प्रदान करने के लिए किया गया है। भूटान स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा आज गेदू कॉलेज ऑफ़ बिज़नेस स्टडीज़ में एक नए एकेडमिक ब्लॉक के शिलान्यास समारोह में राजदूत शामिल हुए। पिछले एक दशक में जीसीबीएस को हॉस्टल, लाइब्रेरी, कम्युनिटी सेंटर बनाने, बड़े पैमाने पर मरम्मत और क्षमता-निर्माण में भारत से मिले सहयोग को आगे बढ़ाते हुए, यह नई सुविधा भूटान में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के विकास में भारत-भूटान सहयोग को और बढ़ाएगी। भूटान के चुखा जिले में स्थित गेदू कॉलेज भारत और भूटान के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों और शैक्षिक सहयोग का एक प्रमुख प्रतीक है। इससे पहले भी भारत-भूटान विकास साझेदारी के तहत इस कॉलेज में लगभग

200 छात्रों के लिए दो गर्ल्स हॉस्टल ब्लॉक का निर्माण किया गया था, जिनका उद्घाटन दिसंबर 2022 में हुआ था। भारत सरकार ने पिछले एक दशक में कॉलेज परिसर के भीतर छात्रावासों, पुस्तकालय और सामुदायिक केंद्र के निर्माण में महत्वपूर्ण वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की है। भारत अपनी 'पड़ोसी प्रथम' नीति के तहत विभिन्न क्षेत्रों में भूटान की निरंतर मदद करता रहा है। इस बानगी यहां भारत की मदद से एक और प्रोजेक्ट के शिलान्यास से देखी जा सकती है। दरअसल इसी दिन भूटान के युसिपांग में नेशनल सेंटर फ़ॉर हाइड्रोलॉजी एंड मीटियोरोलॉजी (एनसीएचएम) के नए मुख्यालय और वैज्ञानिक सुविधाओं का शिलान्यास भी किया गया, जिसकी स्थापना में भी भारतीय सहयोग शामिल है। समारोह में भारत की ओर से मिशन के उप प्रमुख (डीसीएम) अनिकेत मांडवगने और भारतीय दूतावास के प्रथम सचिव डॉ. जे. अरविंद भी उपस्थित थे। यह केंद्र राष्ट्रीय मौसम और बाढ़ चेतावनी केंद्र (एनडब्ल्यूएफडब्ल्यूसी) के रूप में कार्य करेगा, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के खतरों से सुरक्षा के लिए सटीक जानकारी और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को मजबूत करना है। भारतीय दूतावास ने एक अन्य पोस्ट में लिखा, भारत की 'प्रोजेक्ट सहायता' के जरिए समर्थित यह परियोजना, 'शीघ्र चेतावनी प्रणालियों' और 'जलवायु अनुकूलन क्षमता' को मज़बूत करने में योगदान देगी। यह लोगों के जीवन की सुरक्षा करने और एक टिकाऊ भविष्य के निर्माण की दिशा में भारत-भूटान के संयुक्त प्रयासों को दर्शाता है।

रेलवे टेंडर घोटाला के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 16 अप्रैल को आरोप तय करेगा कोर्ट

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने रेलवे टेंडर घोटाला के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय करने पर गुरुवार को फैसला टाल दिया है। कोर्ट ने 13 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। स्पेशल जज विशाल गोगने ने अब मामले पर फैसला 16 अप्रैल को सुनाने का आदेश दिया। कोर्ट ने 28 जनवरी, 2019 को ईडी की ओर से दर्ज केस में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर नियमित जमानत दी थी। इसके बाद 19 जनवरी, 2019 को कोर्ट ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से दर्ज केस में लालू यादव को नियमित जमानत दी थी। कोर्ट ने 13 अक्टूबर 2025 को रेलवे टेंडर घोटाले के सीबीआई से जुड़े मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत दूसरे आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने 17 सितंबर,

2018 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। इस मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी तेजस्वी यादव, मेसर्स लारा प्रोजेक्ट एलएलपी, सरला गुप्ता, प्रेमचंद गुप्ता, गौरव गुप्ता, नाथ मल ककरानिया, राहुल यादव, विजय त्रिपाठी, देवकी नंदन तुलस्यान, मेसर्स सुजाता होटल, विनय कोचर, विजय कोचर, राजीव कुमार रेलान और मेसर्स अभिषेक फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड को आरोपित बनाया है। लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए रेलवे के दो होटलों को आईआरसीटीसी को ट्रांसफर किया और होटलों की देखभाल के लिए टेंडर जारी किये थे। रांची और पुरी के दो होटलों का आवंटन कोचर बंधु की कंपनी सुजाता होटल को ट्रांसफर कर दिया था।

संक्षिप्त समाचार

स्वास्थ्य संबंधी कार्यशाला का माहेश्वरी महिला मंडल ने किया आयोजन

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा,
अमरोहाः गुरुवार को अमरोहा नगर में माहेश्वरी महिला मंडल की एक मासिक बैठक उपाध्यक्ष शिल्पा खटोड के निवास स्थान पर आयोजित की गई , बैठक का शुभारंभ माहेश्वरी महिला मंडल की अध्यक्षा योगेश मालीवाल, सचिव वर्षा माहेश्वरी ,संरक्षिका नीता मांधन्या ,शिल्पा खटोड़ ने दीप प्रज्वलित कर किया। मीटिंग में महिला सदस्यों बदलते मौसम में अपने स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रखें पर विस्तार से चर्चा की गई नीता लड्ढा ने बताया पानी ज्यादा से ज्यादा पिए ताकि शरीर हाइड्रेट रहे ,संतुलित आहार लें, जिसमें विटामिन और मिनरल भरपूर हो ,साथ ही नींद पूरी करें, नियमित व्यायाम करें और मौसम के हिसाब से कपड़े पहने, कपड़े ऐसे पहनें जिससे पूरा बदन ढाका रहे जिससे कोई भी कीटनाशक शरीर पर हमला न कर सके और गर्म हवा लू से भी बच सके। नीता मांघानिया, पूनम खटोड़, नविता मालीवाल, शिल्पा आदि सदस्य ने भी स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की और स्वास्थ्य संबंधी वार्ता पर अपने विचार व्यक्त किए। । मनोरंज के लिए हाऊजी खेली गई और सभी ने स्वादिष्ट व्यंजन का लुफ़्त लिया गया मीटिंग मे योगेश मालीवाल, नविता, वर्षा, शालिनी महेश्वरी, नीता लड्डा, मेघा लड्डा, दीपा मान्धन्य, गुंजन माहेश्वरी, पूनम, निधि, शिल्पा, पिंकी, शुचि, बीना, दीपा आदि सदस्य उपस्थित रहे।

भारतीय किसान संघ ने स्मार्ट मीटर सहित विभिन्न मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा,
हसनपुरः गुरुवार को भारतीय किसान संघ की एक बैठक आयोजित की गई जिसमें विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की गई, बैठक के उपरांत भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी कार्यालय पर उनकी अनुपस्थिति में नायब तहसीलदार मनोज कुमार को सौपा, किसानों ने ज्ञापन के माध्यम से बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर कड़ा रोष व्यक्त किया। उनका आरोप है कि मीटर रीडरों द्वारा घरेलू मीटरों के अनाप-शनाप बिल निकाले जा रहे हैं, जिससे आम उपभोक्ता मानसिक रूप से परेशान है। किसानों ने मांग की है कि गलत बिलों की तत्काल जांच कर उन्हें ठीक किया जाए। तथा स्मार्ट मीटर न लगाए जाएं। हसनपुर से रामपुर भूड़ तक गुजर रही 11 हजार की जर्जर लाइन के तारों को बदला जाए, क्योंकि इनसे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। बैठक में जमीन के विवादों और सरकारी योजनाओं की विफलता का मुद्दा भी छाया रहा। किसानों का कहना है कि लेखपालों ने बिना सही जांच-पड़ताल के जमीनों का अंश बंटवारा गलत तरीके से कर दिया है। इसके समाधान के लिए गांव-गांव कैंप लगाने की मांग की गई है। वहीं, 'हर घर जल' योजना के तहत बनी पानी की टंकियों को 'सफेद हाथी' बताते हुए किसानों ने कहा कि इन्हें जल्द चालू कर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। बैठक में भारतीय किसान संघ द्वारा प्रारंभ किया गया सुपोषण कार्यक्रम के तहत किसान अपने-अपने खेतों की मिट्टी लेकर आए। कार्यक्रम में मिट्टी का विधि-विधान से पूजन किया गया।किसानों ने रसायन मुक्त (जैविक) खेती करने का सामूहिक संकल्प लिया ताकि धरती और जनमानस का स्वास्थ्य सुधारा जा सके। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश शर्मा, रमेश चंद, ओमवीर सिंह चौहान, महिपाल सिंह, उमेश चंद, यशवीर सिंह, अशोक कुमार, रोहताश सिंह, जयप्रकाश शर्मा, चौधरी कार्मेंद्र सिंह और खिलेंद्र कुमार सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे 1

उनेरा प्राथमिक विधालय मे शिक्षा का चौपाल कार्यकर्म आयोजित

लोकतंत्र की शान : महमूदाबाद सीतापुर से अब्दुल्लाह खान आज दिनांक 16 अप्रैल 2026 को संकुल उनेरा में शिक्षा चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़े स्तर पर संकुल के वरिष्ठ एवं सम्मानित शिक्षक, ग्राम प्रधान, एस एम सी अध्यक्ष, ग्रामवासी एवं ARP साथियों में से श्री नरेंद्र यादव, श्रीकृष्ण तिवारी एवं श्री राहुल राय जी की गरिमामयी उपस्थिति रही। शिक्षा चौपाल कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए ARP श्री नरेन्द्र यादव जी ने बताया कि वर्तमान सरकार के प्रयासों से आज परिषदीय विद्यालयों क़ी आधारभूत सुविधाओं में आमूलचूक बदलाव हुआ है। ARP श्री कृष्ण तिवारी ने अपने सम्बोधन में बताया कि किस प्रकार सरकारी विद्यालय के योग्य टीचर्स के प्रयासों से आज ग्रामीण परिवेश के गरीब माता पिता के बच्चे नवोदय विद्यालय, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा में सफल हो रहे हैं। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कम्पोजिट विद्यालय उनेरा के शिक्षक डॉ सादिक़ हुसैन वारसी ने कहा कि शिक्षा के माध्यम से ही समाज एवं देश में खुशहाली आ सकती है। इस अवसर पर गांव वासियों से शत प्रतिशत अर्ह बच्चों का नामांकन करवाने क़ी अपील विद्यालय की प्रधानाध्यापिका श्रीमती गज़ाला परवीन ने की। ARP श्री राहुल रॉय ने नव प्रवेशी 15 बच्चों को स्कूल बैग देकर प्रोत्साहित किया। वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले बच्चों और संकुल के बेस्ट टीचर केटेगरी में पूर्व माध्यमिक विद्यालय उस्मानपुर के प्रधानाध्यापक श्री जुनैद अहमद को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर संकुल उनेरा के शिक्षक बड़े पैमाने पर उपस्थित रहे।

मिशन शक्ति 5.0 के दूसरे चरण में घर-घर जाकर महिलाओं व बच्चों को किया गया जागरूक

लोकतंत्र की शान : सैय्यद कुमैल ज़ैदी, संभल। जनपद में संचालित मिशन शक्ति 5.0 अभियान के दूसरे चरण के अंतर्गत थाना हजरत नगर गढ़ी पुलिस द्वारा क्षेत्र में घर-घर जाकर महिलाओं, बालिकाओं एवं बच्चों को जागरूक किया गया। इस दौरान पुलिस टीम ने आमजन से सीधे संवाद कर उन्हें सुरक्षा, अधिकारों एवं सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। पुलिस टीम ने महिलाओं व बालिकाओं को महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण तथा आत्मरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए 'गुड टच' और 'बैड टच' जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां भी साझा कीं, ताकि वे किसी भी प्रकार की अनुचित स्थिति को पहचान सकें और समय रहते कदम उठा सकें। अभियान के तहत लोगों को हेल्पलाइन नंबर 112, 1090, 1076, 1930 आदि के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि किसी भी आपात स्थिति में इन नंबरों का तुरंत उपयोग करें। साथ ही महिला संबंधी विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में भी विस्तार से बताया गया। इस दौरान मिशन शक्ति प्रभारी उपनिरीक्षक रश्मि मलिक के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मोहल्लों में पहुंचकर जनजागरूकता अभियान चलाया। कार्यक्रम थाना प्रभारी सुधीर पवार के निर्देशन में संपन्न हुआ। स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि घर-घर जाकर जागरूकता फैलाने से समाज में सुरक्षा के प्रति विश्वास बढ़ता है और महिलाएं व बच्चे स्वयं को अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं।

संघटक राजकीय महाविद्यालय में हुआ निबंध एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा

हसनपुरः गुरवार को संघटक राजकीय महाविद्यालय में बाबा साहब डॉ भीम राव अम्बेडकर जी की जयंती के उपरांत निबंध,भाषण प्रतियोगिता तथा विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया,विचार गोष्ठी की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ विनोद कुमार ने की तथा संचालन डॉ मदन पाल ने किया !अध्यक्षता करते हुए डॉ विनोद कुमार ने बाबा साहब के जीवन संघर्ष पर प्रकाश डालते हुए कहा की बाबा साहब सामाजिक समरसता के बड़े हिमायती रहे है !कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे दलित चिंतक मेरठ कॉलेज के प्रोफेसर डॉ सतीश प्रकाश ने कहा की तमाम तरह के जातीय उत्पीड़न क़ो सहकर हर तरह के तिरस्कार क़ो सहन करते हूए ज़ब भारत के भविष्य का निर्माण करने का अवसर मिला तो उन्होंने कहा "हम भारत के लोग" उन्होंने कहा की बाबा साहब ने उच्च कोटि की शिक्षा लेकर सम्पूर्ण दुनिया के सामने एक उदाहरण पेश किया की शिक्षा ही एक माध्यम है जिससे पूरी दुनिया क़ो जीता जा सकता है. कार्यक्रम में राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की प्रिंसपल डॉ पूनम शर्मा ने कहा की बाबा साहब डॉ अम्बेडकर आधुनिक भारत के निर्माता थे जिन्होंने भारत में सामाजिक समानता सामाजिक न्याय के लिए अनवरत कार्य किया और सम्पूर्ण दुनिया क़ो एक संदेश दिया की मानवीय मूल्यों के रक्षा करके हम ऐसे समाज निर्माण का कर सकते है जहां समता, समानता, बंधुत्व हो,कार्यक्रम में आयोजित की गयी निबंध प्रतियोगिता और भाषण प्रतियोगिता में उर्वशी शर्मा ने दोनों प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया. खीजरा, रिफा, उमेश ने द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त किया,कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉ मनोज जाटव, डॉ चित्रा शर्मा, ज्योति गर्ग, अंकिता शर्मा, डॉ परम् जीत कोर, डॉ पल्ल्वी सिंह, डॉ डीके अग्निहोत्री, डॉ मगेंद्र पाल, डॉ नरेंद्र, डॉ गिरेंद्र सिंह, डॉ दीपक तलान, डॉ गजेंद्र, डॉ अनिल कुमार, डॉ विक्की सिंह, डॉ निदा इदरीश, रीता कुमारी, शालनी अल्बर्ट आदि मौजूद रहे 1

रामपुरः जिलाधिकारी अजय द्विवेदी ने जनसुनवाई कर सुनीं समस्याएं, कई मामलों का मौके पर निस्तारण

लोक तंत्र की शान, मंडल प्रभारी अवनीत कुमार शर्मा

रामपुर। जिलाधिकारी अजय द्विवेदी ने कलेक्ट्रेट स्थित अपने कार्यालय में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित कर आम जनता की समस्याएं सुनीं। जनसुनवाई के दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे फरियादियों ने अपनी-अपनी समस्याएं जिलाधिकारी के समक्ष रखीं। डीएम अजय द्विवेदी ने एक-एक कर सभी फरियादियों की शिकायतें गंभीरता से सुनीं और संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कई मामलों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया, जबकि अन्य शिकायतों को जल्द से जल्द निस्तारित करने के आदेश दिए गए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध व पारदर्शी तरीके से निस्तारण किया जाए, ताकि जनता को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा है कि आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान हो और प्रशासन जनता के प्रति जवाबदेह बने। जनसुनवाई में राजस्व, पुलिस, नगर पालिका, बिजली, जल आपूर्ति, पेंशन, राशन कार्ड, भूमि विवाद सहित अन्य विभागों से संबंधित शिकायतें सामने आईं। डीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतकर्ता को प्राथमिकता के आधार पर राहत पहुंचाई जाए और रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत की जाए। जनसुनवाई कार्यक्रम में संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

सीता ग्रुप के आशुतोष बृजमोहन का रहा जलवा

लोक तंत्र की शान, अब्दुल्लाह खान ब्यूरो चीफ

महमूदाबाद, सीतापुरः सीबीएसई द्वारा घोषित कक्षा दस के परीक्षा परिणाम में क्षेत्र के आशुतोष बृज मोहन मेमोरियल कालेज का परीक्षा परिणाम शानदार रहा है। विद्यालय में हाईस्कूल में अनय सिंह पटेल ने 95.6 प्रतिशत अंक प्राप्त कर टॉप किया है। विद्यार्थियों की सफलता पर विद्यालय व उनके परिवार में हर्ष का माहौल है। सीता ग्रुप ऑफ एजूकेशन की सीबीएसई ब्रांच आशुतोष बृजमोहन लाल मेमोरियल कालेज में हाईस्कूल की टॉप टेन सूची में अनय सिंह पटेल को 95.6 प्रतिशत, वैभव वर्मा को 94.6 प्रतिशत, हर्षित पटेल को 94.4 प्रतिशत, विकास वर्मा को 94.2 प्रतिशत, ध्रुव शर्मा को 93.8 प्रतिशत, वंश वर्मा को 93.4 प्रतिशत, कार्तिकेय शुक्ल व अपूर्वा वर्मा को 92.6 प्रतिशत, आदर्श वर्मा, अमन वर्मा, अनन्त कुमार को 92.4 प्रतिशत, आयुष कुमार को 92 प्रतिशत व अंशुल पटेल को 91.8 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं। विद्यार्थियों की सफलता पर संस्था के चेयरमैन आरके वाजपेयी, डिप्टी मैनेजर आंजनेय आशीष, वागीश दिनकर, क्वार्डिनेटर ऋतुजा वाजपेयी, उप प्रधानाचार्य रवि शुक्ल, मनोज गुप्त सहित शिक्षक-शिक्षिकाओं ने खुशी व्यक्त करते हुए बधाई दी। महमूदाबाद, सीतापुर सीबीएसई बोर्ड के घोषित परीक्षा परिणाम में आशुतोष बृज मोहन लाल मेमोरियल कालेज की कक्षा दस के छात्र अनय सिंह पटेल को 95.6 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं। छात्र 15 किमी दूर बाराबंकी जनपद के बड्डूपुर थाना क्षेत्र के आलमपुर गांव से स्कूटी से प्रतिदिन विद्यालय आता है। अनय के पिता अशोक कुमार कृषक है और माता निहारिका देवी साधारण गृहणी हैं। स्वाध्याय के बल पर सफलता अर्जित करने वाले अनय प्रतिदिन पांच से छह घंटे पढ़ाई करते हैं। अनय ने बताया कि सफलता का श्रेय अपने गुरूजनों और माता-पिता को देना चाहते है। वह भविष्य में इंजीनियर बनकर देश सेवा करना चाहते हैं तथा पूर्व राष्ट्रपति डा. अब्दुल कलाम को अपना आदर्श मानते हैं।

नारी शक्ति वंदन अधिनियमः सशक्त नारी, समृद्ध भारत की दिशा में ऐतिहासिक पहल-श्री केशव प्रसाद मौर्य

» महिलाओं की भागीदारी से राष्ट्र-निर्माण को मिलेगी नई गति
» समानता, सम्मान और सशक्तिकरण का सशक्त माध्यम बना अधिनियम

लोक तंत्र की शान

लखनऊ/नोएडाः "सशक्त नारी, सशक्त भारत" के संकल्प को साकार करते हुए नोएडा, जनपद गौतम बुद्ध नगर में आयोजित नारी शक्ति वंदन अधिनियम अभियान कार्यक्रम में संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यह अधिनियम भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में स्थापित हो चुका है। यह महिलाओं को न केवल समान अधिकार देता है, बल्कि उन्हें निर्णय प्रक्रिया में सहभागी बनाकर राष्ट्र-निर्माण को नई दिशा प्रदान करता है। कार्यक्रम में श्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं को लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाने का एक ऐतिहासिक कदम है। यह अधिनियम केवल एक विधिक प्रावधान नहीं, बल्कि देश के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास को नई ऊर्जा देने वाला परिवर्तनकारी निर्णय है। कार्यक्रम में श्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। सरकार का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि जब नारी सशक्त होती है, तब परिवार, समाज और राष्ट्र—सभी सशक्त होते हैं। "महिलाओं के विकास" से आगे बढ़कर अब "महिलाओं के नेतृत्व में विकास" की अवधारणा को साकार किया जा रहा है। श्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भारतीय संस्कृति में नारी को सदैव शक्ति, संवेदना और सृजन की प्रतीक माना गया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसी मूल भावना को सुदृढ़ करते हुए महिलाओं को नेतृत्व और निर्णय क्षमता के केंद्र में स्थापित करता है। यह अधिनियम महिलाओं के आत्मविश्वास, सम्मान एवं सामाजिक प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य करेगा।

महमूदाबाद में सफाई कर्मियों का फूटा गुस्साः "जब वेतन नहीं मिलेगा, तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा

लोक तंत्र की शान, अब्दुल्लाह खान ब्यूरो चीफ

महमूदाबाद (सीतापुर): उत्तर प्रदेश के महमूदाबाद नगर पालिका परिषद में तैनात संविदा सफाई कर्मियों की स्थिति अब दयनीय हो चुकी है। महीनों से वेतन न मिलने और वर्षों से पीएफ कटौती में हो रही अनियमितता को लेकर कर्मचारियों का आक्रोश अब सड़कों पर उतर आया है। आंदोलनरत कर्मचारियों का एक ही सीधा सवाल है— "जब वेतन ही नहीं मिलेगा, तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा?"

करोड़ों का पीएफ घोटाला या लापरवाही? कर्मचारियों द्वारा लगाए गए आरोप बेहद गंभीर हैं। उनके अनुसार, वर्ष 2011 से लेकर 2026 तक उनके वेतन से भविष्य निधि (पीएफ) के नाम पर लगातार कटौती की गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह धनराशि आज तक उनके पीएफ खातों में जमा नहीं की गई। कर्मचारी अब यह पूछ रहे हैं कि आखिर यह पैसा गया कहाँ? इन 15 वर्षों का ब्याज किसकी जेब में जा रहा है?

आर्थिक के साथ मानसिक प्रताड़ना-सफाई कर्मियों का कहना है कि वे शौक से हड़ताल नहीं कर रहे, बल्कि यह उनकी मजबूरी है। बार-बार अधिकारियों के चक्कर काटने के बावजूद उन्हें केवल कोरे आश्वासन मिले हैं। हद तो तब हो गई जब कर्मचारियों के बैंक खाते तक सीज कर दिए गए, जिससे कई परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। "जिन कर्मचारियों के दम पर शहर स्वच्छ रहता है, उन्हें उनका बुनियादी हक तक नहीं मिल रहा। यह केवल आर्थिक शोषण नहीं बल्कि गंभीर मानसिक प्रताड़ना है।"

प्रमुख बिंदु और शिकायतें:

वेतन का संकटः कई महीनों से वेतन न मिलने के कारण दैनिक गुजारा मुश्किल।

पीएफ का हिसाब नहींः 2011 से काटी जा रही पीएफ राशि खातों में गायब।

विभागीय संवेदनहीनताः एक महिला कर्मचारी की सेवा समाप्त हुए 5 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन उसका भुगतान आज तक नहीं हुआ।

खाते हुए सीजः आर्थिक तंगी के बीच बैंक खातों पर लगी रोक ने हालात और बिगाड़े।

सरकार से उम्मीद और चेतावनी-कर्मचारियों ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से हस्तक्षेप की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि जहाँ एक ओर सरकार स्वच्छता और विकास के बड़े दावे करती है, वहीं जमीनी स्तर पर काम करने वालों का शोषण हो रहा है। कर्मियों ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया और बकाये का भुगतान नहीं हुआ, तो यह आंदोलन और भी उग्र रूप ले सकता है नवागत उप जिलाधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ नगर पालिका पहुंची और उग्र लोगो को समझा बुझाकर शांत कराया साथ ही उन्होंने कहा की आपकी मांगो को देखा जाएगा और जो भी समस्याए है उनका समाधान किया जाएगा

बांग्ला में बात कर दिल जीता सीएम योगी ने

लोक तंत्र की शान

बीरभूम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल की जनसभाओं में उपस्थित जनसमूह से बांग्ला में संवाद कर उनका दिल जीत लिया। रामपुरहाट व बोलपुर में मुख्यमंत्री ने मतदाताओं से कहा कि आप सबको भाजपा प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताना है। अपना आशीर्वाद देना है। इसलिए अब मैं जो कहूंगा, आप लोग उसका जवाब दीजिएगा। फिर सीएम ने कहा, ऑन्धकार हटबे (अंधकार हटेगा)। जनता ने उत्तर दिया- सूरोज उठेबे, कोमोल खिलबे (सूरज उगेगा-कमल खिलेगा)। मुख्यमंत्री ने आगे कहा, पलटानो दोरकार (परिवर्तन की जरूरत है), जनता ने उत्तर दिया- चाई बीजेपी सोरकार (चाहिए भाजपा सरकार)। सीएम ने जब "आमार सोनार बांग्ला, टीएमसी मुक्तो बांग्ला (हमारा सोने जैसा बंगाल, टीएमसी मुक्त बंगाल)" कहा तो उपस्थित जनसमूह ने भी दोनों हाथ उठाकर इसे कई बार दोहराया। सीएम योगी के इस संवाद ने जनसभा में उपस्थित लोगों के साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं में भी नया जोश भर दिया।

सेठ एम.आर. जयपुरिया स्कूल,के स्वस्तिक शर्मा ने रचा इतिहास

लोक तंत्र की शान, अब्दुल्लाह खान महमूदाबाद

सीतापुरः के सभी विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम लगभग शत प्रतिशत रहा और बच्चों ने अपनी प्रतिभा को दिखाते हुए बोर्ड में अच्छे अंक अर्जित किए। इस परीक्षा में कुल 39 विद्यार्थियों ने भाग लिया था जिसमे 38 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और एक विद्यार्थी का परिणाम आशा अनुरूप नहीं आया। विद्यालय में 10 से ज्यादा विद्यार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 85 % से ऊपर और विद्यालय को टॉप करने वाला विद्यार्थी स्वास्तिक शर्मा जिसका परिणाम 93.6% रहा ।अगर बात की जाए विषयवार अंक प्राप्त करने की तो सूचना प्रौद्योगिकी में 100 अंक,हिंदी में 95,अंग्रेजी में उच्चतम 91,सामाजिक विज्ञान में उच्चतम 97,विज्ञान मे 95 व गणित में उच्चतम 91 अंक रहा। विद्यालय की इस सफलता को देखते हुए विद्यालय के अध्यक्ष श्री शिव कुमार गुप्ता जी, निदेशक श्री आशीष कुमार गुप्ता जी और विद्यालय के प्रधानाचार्य विजय कुमार दुबे ने सभी विद्यार्थियों को बहुत-बहुत बधाई और उनको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए बहुत-बहुत शुभकामनायें दिया और यह आश्वासन भी दिया कि आगामी परीक्षाओं में विद्यालय के होनहार विद्यार्थी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे। विद्यालय की इस सफलता पर सभी अभिभावको को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होने विद्यालय पर अपना विश्वास व सहयोग दिया.

अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह के तहत स्कूलों में जागरूकता अभियान, छात्र-छात्राओं को दी गई आग से बचाव की ट्रेनिंग

» निबंध व चित्रकला प्रतियोगिता के साथ अग्निशमन उपकरण चलाने का भी दिया गया प्रशिक्षण

लोक तंत्र की शान, खिज़र अहमद

नजीबाबाद। अग्निशन महानिदेशक उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा मुख्यालय लखनऊ के आदेशानुसार एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद बिजनौर डॉ. राजीव कुमार पाण्डेय के निर्देशन में तहसील नजीबाबाद क्षेत्र में "अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह" के अंतर्गत व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया।प्रभारी अग्निशमन केंद्र नजीबाबाद के. एस. जादौन के नेतृत्व में "Safe School, Safe Hospital & Fire Safety Aware Society – Together for Fire Prevention" ("सुरक्षित विद्यालय, सुरक्षित अस्पताल एवं अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक समाज – आग की रोकथाम के लिए एक साथ") थीम पर विभिन्न विद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान छात्र-छात्राओं के बीच निबंध लेखन एवं चित्रकला प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया गया, जिससे बच्चों में अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ सके। साथ ही विद्यार्थियों को आग लगने की स्थिति में बचाव के उपायों की विस्तार से जानकारी दी गई। अग्निशमन कर्मियों द्वारा बच्चों को फायर उपकरणों के संचालन का लाइव प्रदर्शन कर बताया गया कि आपात स्थिति में किस प्रकार इनका उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही यह भी समझाया गया कि आग लगने पर घबराएं नहीं, बल्कि तुरंत फायर सर्विस को सूचना दें। कार्यक्रम के अंत में विद्यालयों में अग्नि सुरक्षा संबंधी पम्पलेट वितरित कर लोगों को जागरूक किया गया।

इन विद्यालयों में हुआ आयोजनः ग्रीन लाइट सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, नांगल नजीबाबाद कुंदन सिंह मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हरिद्वार रोड साहनपुर ग्लोबल वालिया एकेडमी, नगीना-बूंदकी रोड मूलचंद एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कोटद्वार रोड पर आयोजित की गई

संक्षिप्त समाचार

हेड मास्टर ने गांधी सेतु से लगाई छलांग

लोकतंत्र की शान : हाजीपुर। वैशाली के बिदुपुर स्थित जनता उच्च विद्यालय धर्मपुर के प्रभारी प्रधानाध्यापक फजलूल बासित सिद्दीकी ने महात्मा गांधी सेतु से कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया। यह घटना सुबह स्कूल में उपस्थिति दर्ज कराने के बाद हुई। उन्हें SDRF की टीम ने बचा लिया। प्रधानाध्यापक सिद्दीकी स्कूल से सीधे जदुआ होते हुए गांधी सेतु पहुंचे। उन्होंने पुल के 42 नंबर पाया के पास से छलांग लगाई। बताया जा रहा है कि जिस जगह उन्होंने छलांग लगाई, वहां पानी कम था। गाय घाट किनारे तैनात एसडीआरएफ की टीम ने तुरंत रेस्क्यू कर उन्हें बाहर निकाला। स्कूल के कुछ शिक्षकों ने बताया कि फजलूल बासित सिद्दीकी एक अच्छे और सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। वे अपनी पारिवारिक बातें अन्य शिक्षकों के साथ साझा नहीं करते थे। शिक्षकों का अनुमान है कि पारिवारिक कलह के कारण उन्होंने यह आत्मघाती कदम उठाया होगा। रेस्क्यू के बाद प्रभारी प्रधानाध्यापक को इलाज के लिए पटना के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों और पुलिस ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है। गाय घाट के पास स्थित आलमगंज थाना में प्रधानाध्यापक से पूछताछ की जा रही है। घटना की सूचना मिलने के बाद जनता उच्च विद्यालय के अन्य शिक्षकों में हड़कंप मच गया। हालांकि, इस संबंध में कोई भी शिक्षक स्पष्ट रूप से कुछ भी बताने से बच रहे थे।

लव मैरिज के बाद मारपीट, लड़की के पिता ने लड़के के पिता-भाई का सिर फोड़ा, बेटी बोली- पति के साथ ही रहूंगी

लोकतंत्र की शान : हाजीपुर। वैशाली जिले के महिसौर थाना क्षेत्र के सोहर्थी गांव में प्रेम प्रसंग में शादी के बाद लड़की पक्ष के लोगों ने लड़के के भाई और पिता पर हमला कर दिया। इस हमले में वे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जंदाहा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। घायल सोहर्थी गांव निवासी रामविलास शर्मा के पुत्र संदीप कुमार ने महिसौर थाना में इस संबंध में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। संदीप कुमार ने पुलिस को बताया कि जब वे अपनी दुकान बंद कर घर पहुंचे और दरवाजे पर गाड़ी खड़ी कर रुके, तभी पहले से घात लगाए बैठे 10 से 12 लोगों ने उन पर हमला कर दिया। जब परिवार के अन्य सदस्य बचाने आए, तो उनके साथ भी मारपीट की गई। यह घटना संदीप कुमार के छोटे भाई सरोज कुमार द्वारा पड़ोस की प्रीति कुमारी (राम नारायण शर्मा की पुत्री) से बीते सप्ताह प्रेम प्रसंग के चलते घर से भागकर 26 मार्च को कोर्ट मैरिज करने के बाद हुई है। लड़की के पिता ने पहले बेटी के अपहरण का मामला दर्ज कराया था। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, पुलिस ने 11 अप्रैल को लड़की को बरामद कर न्यायालय में प्रस्तुत किया था। प्रीति ने न्यायालय में अपने पति और सास-ससुर के साथ रहने की सहमति दी थी, जिसके बाद उसे लड़के वाले अपने घर ले आए थे। हालांकि, प्रीति के भाई और अन्य लोगों द्वारा लड़के की हत्या करने और परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट करने की धमकी दी गई थी। प्रीति कुमारी का कहना है कि वह अपनी स्वेच्छा से पति के साथ रहना चाहती है, लेकिन उसके परिवार वाले जानलेवा हमला करने की फिराक में हैं। उसने पुलिस अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई है। पुलिस फिलहाल मामले की गहनता से जांच कर रही है। संदीप ने अपनी प्राथमिकी में गुड्डू शर्मा, राम नारायण शर्मा, राम सकल शर्मा, कांत लाल शर्मा, सुबोध शर्मा, विश्वनाथ शर्मा, बिट्टू शर्मा, रोहित शर्मा और पप्पू शर्मा सहित नौ लोगों को नामजद किया है।

वैशाली में गेहूं की क्रॉप कटिंग, प्रति हेक्टेयर 31.60 क्विंटल उपज दर्ज, सरकार ने आंका उत्पादन

लोकतंत्र की शान : हाजीपुर। वैशाली जिले के बिदुपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत सहदुलहपुर धोबौली पंचायत के हरिवंश नारायण सिंह के खेत पर गेहूं की क्रॉप कटिंग की गई। यह प्रक्रिया बिहार सरकार के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के अधिकारियों की देखरेख में संपन्न हुई। मौके पर संयुक्त निदेशक श्री शैलेंद्र कुमार पाण्डेय, जिला सांख्यिकी अधिकारी श्रवण रजक, सहायक जिला सांख्यिकी अधिकारी शिवानंद भारती, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी सुजीत कुमार, कृषि समन्वयक सोनिया कुमारी, किसान सलाहकार प्रेम प्रकाश सिंह समेत सुनील कुमार, रवि रंजन कुमार, राजीव कुमार, चंद्रकांत ठाकुर, संजीव कुमार उपस्थित रहे। क्रॉप कटिंग 10×5 मीटर के निर्धारित प्लॉट में की गई। कटाई के बाद कुल 15.800 किलोग्राम गेहूं का उत्पादन हुआ। इसके आधार पर प्रति हेक्टेयर उपज 31.60 क्विंटल दर्ज की गई। यह आंकड़ा क्षेत्र में गेहूं उत्पादन क्षमता का स्पष्ट संकेत देता है। अधिकारियों ने बताया कि सरकार द्वारा फसल का वास्तविक उत्पादन आंकने के लिए यह प्रक्रिया आवश्यक है। इससे न केवल उपज की सटीक जानकारी मिलती है, बल्कि किसानों को उचित मूल्य एवं राहत योजनाओं का लाभ दिलाने में भी मदद मिलती है। मौजूद किसानों ने अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की। क्षेत्र में इस बार मौसम अनुकूल रहने से अच्छी पैदावार की उम्मीद जताई जा रही है।

वैशाली में पशु बांझपन निवारण कैंप, बिदुपुर में 191 पशुओं का मुफ्त इलाज, दवाएं बांटी गई

लोकतंत्र की शान : हाजीपुर। आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 के तहत वैशाली जिले के बिदुपुर प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय मथुरा, पंचायत मथुरा सुल्तानपुर में एक दिवसीय पशु बांझपन निवारण शिविर एवं पशुपालन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस शिविर में कुल 57 पशुपालकों के 191 पशुओं का निःशुल्क इलाज किया गया और आवश्यक दवाएं वितरित की गईं। शिविर का उद्घाटन सरपंच शैलेन्द्र सिंह ने फीता काटकर किया। पशुओं के रख-रखाव, बांझपन के कारणों और उसके निवारण के बारे में डॉ. धर्मवीर सिंह, भ्रमणशील पशुचिकित्सा पदाधिकारी, गोकुला ने पशुपालकों को विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर डॉ. धर्मवीर सिंह, डॉ. प्रमोद कुमार (भ्रमणशील पशुचिकित्सा पदाधिकारी, बिदुपुर), डॉ. रंजू कुमारी (MVU प्रभारी, बिदुपुर), पारा वेट अनोज कुमार, परिचारी निकेत कुमार (पशु चिकित्सालय गोकुला), नवनीष कुमार, मैत्री गोलू कुमार, अजीत कुमार, मंजीत कुमार, सुभाष चंद्र रॉय सहित कई पशु चिकित्सा कर्मी उपस्थित रहे। शिविर का सजीव निरीक्षण डॉ. प्रभावती कुमारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, वैशाली द्वारा किया गया। उन्होंने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे शिविरों से पशुपालकों को काफी लाभ मिलता है और पशुओं में बांझपन की समस्या से निपटने में मदद मिलती है। पशुपालकों में सुमन सिंह, अमोद सिंह, मुकेश कुमार, मंजेश कुमार पासवान, हरेंद्र राय, लालदेव सिंह, संत किशोर सिंह, उत्तम चंद्र कुमार, ममता देवी, सुनीता देवी, उषा देवी आदि ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत करते हुए ऐसे शिविरों को नियमित रूप से आयोजित करने की मांग की है। जिला प्रशासन एवं पशुपालन विभाग ने बताया कि आगे भी इस तरह के जागरूकता एवं उपचार शिविर जिले के अन्य गांवों में लगाए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक पशुपालक लाभान्वित हो सकें।

आम के बगीचे में हत्या की प्लानिंग करते 3 अरेस्ट

लोकतंत्र की शान : मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में तीन बदमाशों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। पूछताछ में पता चला कि वे सुपारी लेकर हत्या करते थे। बदमाशों के पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल, कट्टा और गोली बरामद की गई है। मामला कुढ़नी थाना क्षेत्र का है। आरोपी आम के बगीचे में बैठकर किसी की हत्या की योजना बना रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने तीनों को अरेस्ट किया। मामले की जानकारी देते हुए ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रेलवे गुमटी संख्या-17 के पास कुछ संदिग्ध युवक इकट्ठा होकर आपराधिक घटना की योजना बना रहे हैं। सूचना के आधार पर कुढ़नी थाना की टीम ने छापेमारी की और मौके से तीनों को दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान श्रीवन कुमार उर्फ गोलू कुमार (कुढ़नी), प्रीतम राज (सदर) और आयुष कुमार (गोरौल, वैशाली) के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान इनके पास से एक देसी कट्टा, तीन कारतूस, तीन मोबाइल और दो चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने हत्या के लिए सुपारी लेने की बात स्वीकार की है। बरामद मोटरसाइकिल वैशाली के बेलसर थाना क्षेत्र से चोरी की बताई जा रही है। इस मामले में कुढ़नी थाना में कांड संख्या 59/26 दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इनकी साजिश का टारगेट कौन था और गिरोह से जुड़े अन्य लोग कौन-कौन हैं।

नीट छात्रा रेप-मौत, हॉस्टल मालिक मनीष रंजन को जमानत

90 दिन बाद मिली डिफॉल्ट बेल, पीड़ित की मां की तबीयत बिगड़ी, पीएमसीएच में भर्ती

लोकतंत्र की शान, पटना

NEET छात्रा रेप-मौत मामले में शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक मनीष रंजन को गुरुवार को पटना सिविल कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने डिफॉल्ट बेल दी है। इसका मतलब ये है कि CBI ने समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं की। इसी वजह से आज मनीष को बेल दी गई है। 90 दिन बाद मनीष को इस केस में जमानत मिली है। अदालत ने 10 अप्रैल 2026 को स्पष्ट आदेश दिया था कि मामले में 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल की जाए। आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत यह समय सीमा अनिवार्य होती है, जिसके तहत अगर निर्धारित अवधि में चार्जशीट दाखिल नहीं होती, तो आरोपी को डिफॉल्ट बेल का अधिकार मिल जाता है।

मनीष रंजन का बेल बॉन्ड आज अदालत में पेश नहीं हो सका। सूत्रों के अनुसार, यह प्रक्रिया संभवतः कल पूरी की जाएगी, जिसके बाद उसकी रिहाई का रास्ता साफ हो सकता है। अदालत ने इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए न केवल आरोपी को डिफॉल्ट बेल दी। कोर्ट की अवहेलना पर जांच अधिकारी (IO) के खिलाफ विभागीय जांच की अनुशंसा की है।

मनीष रंजन की जमानत मिलने की खबर सुनने के बाद पीड़िता की मां की तबीयत बिगड़ गई है। वो PMCH के इमरजेंसी में भर्ती हैं।

दोषमुक्त नहीं माना गयाः मनीष की जमानत का आदेश सबूतों पर आधारित नहीं है। इसका अर्थ है कि आरोपी को मिली राहत तकनीकी आधार पर है, न कि उसे दोषमुक्त मानते हुए। ऐसे में मामले की कानूनी लड़ाई अभी समाप्त नहीं मानी जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच पीड़ित पक्ष और उससे जुड़े लोग अपने रुख पर कायम हैं। उनका कहना है कि वे इस फैसले से विचलित नहीं हैं और न्याय के लिए आखिरी दम तक संघर्ष जारी रखेंगे।

वकील बोले- मनीष की बेल से CBI ज्यादा खुश दिखीः पीड़ित पक्ष के वकील एसके पांडे ने बताया, कोर्ट ने CBI को निर्धारित समय में चार्जशीट दाखिल करने को कहा था। ये सीमा 90 दिनों की थी। 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं की जाती तो कोर्ट अभियुक्त को ज्यादा दिन जेल में नहीं रख सकती है। CBI को चार्जशीट पेश करने में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन CBI को लेकर मैंने महसूस किया, जितनी खुशी मनीष रंजन को नहीं थी, उससे ज्यादा CBI को थी।

चूक से पूरा केस प्रभावित हो सकता हैः अदालत परिसर में CBI के अधिकारियों के चेहरे पर संतोष नजर आया। आमतौर पर ऐसे मामलों में एजेंसी पर दबाव होता है, लेकिन इस बार उनका रुख कुछ अलग दिखा, जिससे कई तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। कानूनी जानकारों का मानना है कि इस तरह के मामलों में जांच एजेंसियों को समय सीमा का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि तकनीकि चूक से पूरा केस प्रभावित हो सकता है। अब सबकी नजर इस पर टिकी है कि आगे की सुनवाई में क्या नया मोड़ आता है और क्या CBI अपनी जांच को मजबूत तरीके से अदालत के सामने पेश कर पाती है या नहीं।

सहरसा में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर सख्ती, कालाबाजारी रोकने को प्रशासन अलर्ट

लोकतंत्र की शान

सहरसा |मो. ज़ियाउद्दीन, जिला संवाददाताः सहरसा जिले में आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क और सक्रिय नजर आ रहा है। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा आम जनता को जरूरी सामान समय पर उपलब्ध कराने के साथ-साथ अनियमितताओं पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जिला आपूर्ति शाखा द्वारा जारी दैनिक स्थिति रिपोर्ट के अनुसार जिले की वर्तमान स्थिति संतोषजनक है। जिला स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्ष (डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम) लगातार कार्यरत है। गुरुवार को नियंत्रण कक्ष में कुल 13 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनका त्वरित निपटारा कर दिया गया। एलपीजी आपूर्ति और सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन ने विशेष सतर्कता बरती है। जिले की 34 गैस एजेंसियों में से 11 संवेदनशील एजेंसियों पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस बल की तैनाती की गई है। आंकड़ों के अनुसार, जिले में 3,222 बुकिंग के मुकाबले 2,130 सिलेंडरों की होम डिलीवरी सुनिश्चित की गई है। वर्तमान में जिले में 6,078 भरे हुए सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ प्रशासन द्वारा सख्त अभियान चलाया जा रहा है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आज एक स्थान पर छापेमारी की गई। अब तक जिले में कुल 193 निरीक्षण किए जा चुके हैं, जिनमें 5 मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आवश्यक वस्तुओं की कृत्रिम कमी पैदा करने या निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर बिक्री करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि किसी भी शिकायत के लिए जिला नियंत्रण कक्ष से संपर्क करें।

दक्षिण-मध्य बिहार में पारा 40 पार जाएगा

लोकतंत्र की शान, पटना

राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले तीन-चार दिनों तक मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। पूर्वानुमान के अनुसार दक्षिण और मध्य बिहार के जिलों में तापमान 40-42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। हालांकि उत्तर-पूर्व बिहार के कुछ हिस्सों जैसे किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार में 17-18 अप्रैल के आसपास हल्की बारिश की संभावना जताई गई है, लेकिन इससे व्यापक राहत मिलने के आसार नहीं हैं।

पटना समेत अन्य जिलों में लू चलने लगी हैः पटना समेत राज्य के कई जिलों में लू चलने लगी है। कई जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंच गया है। मौसम विभाग के पटना केंद्र के

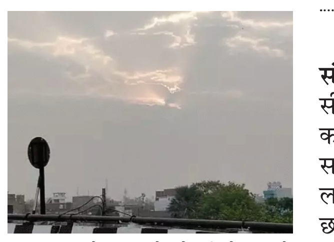

मुताबिक, रोहतास के डेहरी में सबसे अधिक तापमान 41.8 डिग्री रहा। इसके अलावा औरंगाबाद, बक्सर, शेखपुरा और कैमूर में भी 41 डिग्री के आसपास रहा।

पटना में भी बुधवार को दिनभर लू जैसे हालात बने रहे। यहां का अधिकतम तापमान 38.9 डिग्री तक पहुंच गया, जो सामान्य से 1.5 डिग्री अधिक है। वहीं, आर्द्रता 31 प्रतिशत रही, जिससे तेज गर्म हवाओं का सामना करना पड़ा। दिन में बाहर निकलना मुश्किल हो गया।

सीबीएसई 10वीं में इंडियन हाई स्कूल सहरसा का जलवा 98% रिजल्ट के साथ कई छात्रों ने 90%+ अंक किए हासिल

लोकतंत्र की शान

सहरसा | मो. ज़ियाउद्दीन, जिला संवाददाताः सहरसा स्थित इंडियन हाई स्कूल ने सीबीएसई 10वीं परीक्षा 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए एक बार फिर अपनी शैक्षणिक उत्कृष्टता साबित की है। इस वर्ष विद्यालय का कुल परिणाम लगभग 98% रहा, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। विद्यालय प्रबंधन के अनुसार, इस बार 90% से ऊपर अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या काफी प्रभावशाली रही, वहीं 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या भी उल्लेखनीय है। इस उपलब्धि से विद्यालय परिसर में खुशी और उत्साह का माहौल है।

टॉपर्स की सूची में प्रमुख नाम इस प्रकार हैंः प्रीति कुमारी (रोल नंबरः 22247055) ने 96.8% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया। आशी मिश्रा (22246793) ने 95.6% अंक लाकर दूसरा स्थान प्राप्त किया। सत्यम कुमार (22246896) और अनुष्का (22246972) ने

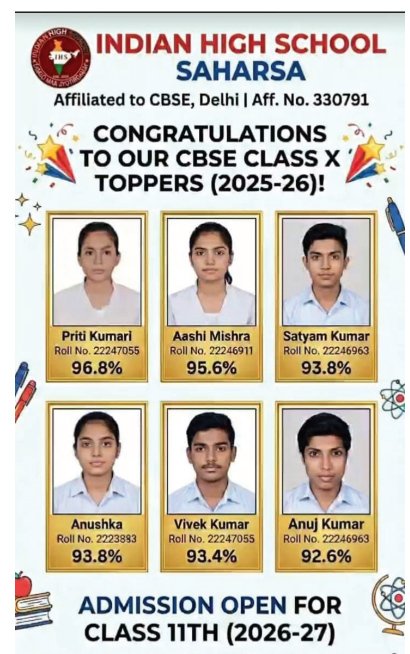

93.8% अंक के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा अन्य मेधावी छात्र-छात्राओं में विवेक कुमार (93.4%), अनुज कुमार (92.6%), हर्षिता वत्स (92.6%), किशु राज (92.4%), प्रेम स्नेही कुमार (92.2%), शिवम कुमार (92.0%), मंखुश कुमार (92.0%), आकाश वर्मा (92.0%), आयुष्मान झा (92.0%), प्रत्युष राज (91.8%), ऋतिक कुमार (91.8%), चंद्रमोहन कुमार (91.6%), तन्नु श्री (91.2%), हिमांशु कुमार (90.8%), प्रियांशु भारद्वाज (90.8%), निक्की कुमारी (90.8%), आयुष आनंद (90.6%) और रजनीश मोहन (90.4%) शामिल हैं। विद्यालय के प्राचार्य ने सभी सफल विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि यह सफलता छात्रों की मेहनत, शिक्षकों के समर्पण और अभिभावकों के सहयोग का परिणाम है। स्कूल के निदेशक नरेंद्र वर्मा ने बताया कि विद्यालय भविष्य में भी इसी तरह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर परिणाम देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस शानदार परिणाम के बाद विद्यालय में जश्न का माहौल है और छात्र-छात्राएं अपनी सफलता का उत्सव मना रहे हैं।

17 अप्रैल से 1 मई तक स्व-गणना, हर नागरिक की सहभागिता आवश्यकः जिला पदाधिकारी

लोकतंत्र की शान

सहरसा, मो. ज़ियाउद्दीन, जिला संवाददाताः जनगणना-2027 के अंतर्गत आवश्यक जानकारी साझा करने हेतु जिला पदाधिकारी श्री दीपेश कुमार की अध्यक्षता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस दौरान उन्होंने बताया कि जिले में स्व-गणना की प्रक्रिया 17 अप्रैल 2026 से 01 मई 2026 तक निर्धारित की गई है। इस अवधि में नागरिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वयं एवं अपने परिवार की जानकारी दर्ज कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह पहल जनगणना प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। संबंधित व्यक्ति https://se.census.gov.in पोर्टल पर लॉग-इन कर परिवार पंजीकरण, भाषा चयन, OTP सत्यापन एवं स्थान संबंधी विवरण भरने के बाद प्रश्नावली पूर्ण कर अंतिम सबमिशन कर सकते हैं। जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि अंतिम सबमिशन के बाद परिवार के मुखिया का नाम, मोबाइल नंबर आदि में संशोधन संभव नहीं होगा, इसलिए

सभी जानकारी सावधानीपूर्वक भरना आवश्यक है। स्व-गणना पूर्ण होने के बाद प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट स्व-गणना पहचान संख्या (SE ID) प्राप्त होगी, जिसे सुरक्षित रखना जरूरी है। क्षेत्रीय सत्यापन के दौरान गणनाकार (Enumerator) के आने पर नागरिकों को यह SE ID प्रस्तुत करनी होगी। उन्होंने यह भी बताया कि इस प्रक्रिया के लिए किसी प्रकार के दस्तावेज (जैसे आधार, पासपोर्ट, रेंट एग्रीमेंट आदि) दिखाने की आवश्यकता नहीं है और नागरिकों की सभी जानकारियां पूर्णतः गोपनीय रखी जाएंगी। प्रवासी मजदूर एवं बाहर रह रहे व्यक्ति भी अपने वर्तमान निवास स्थान से ही स्व-गणना कर सकते हैं। जिला पदाधिकारी ने जिले के सभी नागरिकों से अपील की कि वे स्व-गणना प्रक्रिया में बढ़-चढ़कर भाग लें, निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करें तथा अन्य लोगों को भी इस महत्वपूर्ण कार्य में भाग लेने के लिए प्रेरित करें, ताकि जनगणना का कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सके। उन्होंने स्वास्थ्य, पंचायती राज, शिक्षा, ICDS, जीविका, कल्याण, कृषि एवं सहकारिता विभागों को भी इस कार्य में सक्रिय एवं प्रभावशाली भूमिका निभाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त श्री गौरव कुमार, अपर समाहर्ता श्री निशांत, उप निदेशक सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

पटना मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर का सिविल वर्क हुआ पूरा

लोकतंत्र की शान, पटना

पटना मेट्रो ने प्रायोरिटी कॉरिडोर में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मेट्रो के ISBT स्टेशन और पटना डिपो को जोड़ते हुए अंतिम यू-गर्डर को लॉन्च कर दिया गया है। यह यू-गर्डर पिलर नंबर 187–188 के बीच अप लाइन में लॉन्च किया गया है। अंतिम गर्डर की लॉन्चिंग के साथ ही प्रायोरिटी कॉरिडोर के सिविल वर्क का बड़ा हिस्सा पूरा हो चुका है। इसके साथ ही इस कॉरिडोर के लिए सभी प्रीकास्ट एलिमेंट्स की स्थापना का काम पूरा हो गया है।

यू-गर्डर लांचिंग की शुरुआत 26 जनवरी 2023 को हुई थीः यह उपलब्धि इस परियोजना के निर्माण कार्य में एक महत्वपूर्ण चरण माना जा रहा है। पटना मेट्रो में यू-गर्डर लांचिंग की शुरुआत 26 जनवरी 2023 को की गई थी। तब से लेकर अब तक कुल 328 यू-गर्डर स्थापित किए गए हैं। इन यू-गर्डर्स के माध्यम से

एलिवेटेड ट्रैक का ढांचा तैयार किया जाता है, जिस पर मेट्रो ट्रेनें चलेंगी। अब अगले चरण में ट्रैक बिछाने, सिग्नलिंग, ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन और स्टेशन से जुड़े फिनिशिंग कार्यों को तेजी से पूरा किया जाएगा।

पटना मेट्रो के मुताबिक यू-गर्डर लॉन्चिंग के दौरान कई स्थानों पर सुरक्षा कारणों से यातायात को डायवर्ट करना पड़ता था। इससे आम लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ता था। अब इस प्रमुख कार्य के पूरा होने के बाद लोगों को ट्रैफिक जाम और डायवर्जन से काफी राहत मिलने की उम्मीद है।

नीतीश के 20 साल पर मूवी लॉन्च, रो पड़े अशोक चौधरी

लोकतंत्र की शान, पटना

नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने गुरुवार को JDU दफ्तर में अपने पिता नीतीश कुमार पर बनी शॉर्ट फिल्म 'मेरा नेता मेरा अभिमान' की लॉन्चिंग की। फिल्म में नीतीश के 20 साल के काम को दिखाया गया है। उन्होंने नीतीश पर बने एक गाने को भी रिलीज किया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री अशोक चौधरी भी मौजूद थे। मूवी लॉन्च होने के बाद अशोक चौधरी रो पड़े। निशांत ने कंधे पर हाथ रखकर ढांढस बंधाया।

निशांत ने कहा कि उनकी प्राथमिकता पार्टी संगठन को मजबूत करना और जनता का आशीर्वाद लेना रहेगा। उन्होंने कहा कि उनके पिताजी नीतीश कुमार ने 20 सालों में बिहार के लिए बहुत काम किए हैं। कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री अशोक चौधरी

नीतीश कुमार का जिक्र करते ही रो पड़े। उन्होंने कहा, 'नीतीश जी का फैसला था कि वो राज्यसभा जाएंगे। वो जा रहे हैं ठीक है, लेकिन उनके साथ काम करने का एक अलग ही मजा था। हर व्यक्ति की बॉडी लैग्वेज और रिएक्ट करने का तरीका अलग होता है। हो सकता है वो भी इसे लेकर भावुक हों। हर तरह से उन्होंने काम किया था। हम चाहते थे कि वो 5 साल और काम करते। बिहार समृद्धशाली हो पाता। उन्होंने जो सपना देखा था वो पूरा हो पाता।

सहरसा में पांडुलिपि सर्वेक्षण अभियान को मिली रफ्तार, सांस्कृतिक धरोहर सहेजने की पहल तेज

लोकतंत्र की शान

सहरसा |मो. ज़ियाउद्दीन, जिला संवाददाताः भारत ज्ञान मिशन के अंतर्गत सहरसा जिले में प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण और दस्तावेजीकरण को लेकर चल रहा सर्वेक्षण अभियान अब तेजी पकड़ चुका है। जिला प्रशासन की टीम लगातार विभिन्न गांवों का दौरा कर दुर्लभ पांडुलिपियों की खोज और उनके डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने में जुटी है। इसी क्रम में बनगांव स्थित बाबा जी कुटी से लक्ष्मीनाथ गोसाईं द्वारा लिखित एक महत्वपूर्ण पांडुलिपि प्राप्त हुई है, जो क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण साक्ष्य मानी जा रही है। इसके अलावा महिषी क्षेत्र में आनंद

दत्त झा, जवाहर ठाकुर और सुमन समाज के पास से भी कई प्राचीन पांडुलिपियां चिन्हित की गई हैं। प्रशासनिक टीम ने उनके आवास पर पहुंचकर विस्तृत सर्वेक्षण कार्य किया। जिला प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि यदि उनके पास या उनके आसपास कहीं भी पुरानी पांडुलिपियां सुरक्षित हैं, तो वे इसकी जानकारी साझा करें। प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि पांडुलिपियों को किसी से स्थायी रूप से नहीं लिया जाएगा, बल्कि केवल उनका डिजिटलाइजेशन कर सुरक्षित किया जाएगा और तत्पश्चात उन्हें संबंधित व्यक्ति को वापस कर दिया जाएगा। प्रशासन का मानना है कि इस पहल से न केवल हमारी अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षित रहेगी, बल्कि डिजिटल माध्यम के जरिए यह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुलभ और जीवंत बनी रहेगी। अभियान को सफल बनाने के लिए लोगों को जागरूक करने और अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने के प्रयास लगातार जारी हैं।

संक्षिप्त समाचार

गांव चलो-बस्ती चलो' जनसेवाओं का महत्वपूर्ण अभियान -डा अशोक कुमार

कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर हुई बैठक

राजेंद्र करनाल की रिपोर्ट , करनालः गांव चलो-बस्ती चलो' अभियान के तहत करनाल नगर निगम के वार्ड 12 के चार चमन इलाके एवं बूथ नंबर 33,34,35 में होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर कर्ण मंडल उपाध्यक्ष आकाश अरोड़ा एवं शक्ति केंद्र प्रमुख सतीश कश्यप की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई। इस अवसर पर मुख्य तौर पर भाजपा जिला मीडिया प्रभारी एवं शक्ति केंद्र पालक डा अशोक कुमार के अलावा शक्ति केंद्र सह प्रमुख नंद लाल, बूथ अध्यक्ष पुष्पिंदर माथुर,ओम प्रकाश, रविन्द्र कश्यप,अशोक कुमार वर्मा एवं अनिल पाहवा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस बैठक में शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं, बुनियादी सुविधाओं एवं अन्य आवश्यकताओं को क्षेत्र के घर- घर तक पहुंचाने हेतु विचार- विमर्श कर समीक्षा की गई एवं इस बैठक में उत्साह से भरपूर समर्पित कार्यकर्ताओं ने पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ जनसेवा का संकल्प लिया। बैठक में गांव चलो बस्ती चलो कार्यक्रम के अंतर्गत शक्ति केंद्र में होने वाले कार्यक्रमों की चर्चा करते हुए ड्यूटियां निर्धारित की गई। इस मौके जिला मीडिया प्रभारी डा अशोक कुमार ने बताया कि पार्टी द्वारा चलाया जा रहा गांव चलो-बस्ती चलो अभियान प्रदेशभर में व्यापक जनसंपर्क और जनसेवा का एक महत्वपूर्ण अभियान है। इसका उद्देश्य गांव-गांव और बस्ती-बस्ती तक पहुंचकर केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाना तथा उनकी समस्याओं को सुनकर समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता इस अभियान में पूरी निष्ठा और उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। प्रत्येक मंडल, बूथ एवं शक्ति केंद्र स्तर पर युवाओं की टीम बनाकर घर-घर संपर्क किया जा रहा है। कार्यकर्ता जनता को सरकार की उपलब्धियों से अवगत करा रहे हैं और उनके सुझाव भी प्राप्त कर रहे हैं।

अवैध रेत परिवहन पर रोक लगाने रात भर चला धरपकड़ अभियान 4वाहनो पर हुई कार्रवाई

चार वाहन जब्त, चालकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान सीधी। कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक के निर्देशन और जिला खनिज अधिकारी के मार्गदर्शन में खनिज एवं पुलिस के संयुक्त दल द्वारा जिले में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध सघन जांच अभियान चलाया गया। यह अभियान 15 अप्रैल 2026 की रात्रि 10 बजे से 16 अप्रैल 2026 की सुबह 10 बजे तक निरंतर जारी रहा। अभियान के दौरान गोपदबनास, बहरी, सिहावल एवं चुरहट तहसील के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक जांच की गई, जिसमें कुल 4 वाहनों को अवैध रेत परिवहन करते पाए जाने पर जब्त किया गया। सभी वाहनों को सुरक्षार्थ संबंधित थानों में खड़ा कराया गया है। कार्रवाई के तहत ग्राम मयापुर, तहसील बहरी में रेत का अनाधिकृत परिवहन करते हुए दो हाइवा वाहन क्रमांक UP64AT7247 एवं UP63AT2117 को जब्त कर थाना बहरी की अभिरक्षा में सौंपा गया। इसी प्रकार ग्राम चमरौहा, तहसील सिहावल में हाइवा क्रमांक UP63AT1918 को अवैध रेत परिवहन करते पाए जाने पर जब्त कर थाना अमिलिया को सुपुर्द किया गया। एक अन्य कार्रवाई में तहसील सिहावल अंतर्गत जांच के दौरान मिनी ट्रक क्रमांक MP53ZF6979 खनिज रेत से भरा हुआ पाया गया। जांच दल को देखकर चालक ने वाहन से रेत सड़क पर गिराते हुए भागने का प्रयास किया और वाहन को ग्राम मेढ़ौली स्थित शीतला माता मंदिर के पास छोड़कर फरार हो गया। बाद में वाहन को जब्त कर पुलिस चौकी सिहावल परिसर में सुरक्षित खड़ा कराया गया। संबंधित वाहन चालकों एवं स्वामियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश खनिज (अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियम 2022 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई के लिए कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। कलेक्टर के निर्देशानुसार खनिज विभाग द्वारा जिले मेंw अवैध खनन पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध उत्खनन, परिवहन या भंडारण पाए जाने पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, ताकि जिले में इस पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके।

झारखंड महादेव शिवाला मंदिर पर विधि विधान के साथ हुई मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा, हसनपुर : गुरुवार को नगर के झारखंड महादेव शिवाला मंदिर पर पंडितों द्वारा मंत्रोउच्चारण के बीच शिव परिवार एवं बृहस्पति देव जी की मूर्तियों की विधि विधान के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा कराई गई, सर्वप्रथम विधि विधान के अनुसार हवन यज्ञ कर आहुति लगाई गई तथा मूर्तियों को स्थापित करने के बाद भंडारे का भी आयोजन किया गया, इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भंडारे में भोजन ग्रहण किया, वहीं विधायक महेंद्र सिंह खड़कवंशी ने भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भाग लिया और भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया, इस मौके पर शिवाला प्रबंध कमेटी के प्रबंधक अंकुर अग्रवाल, अमित अग्रवाल उर्फ निक्कू, प्रमोद अग्रवाल, सुनील अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल, कपिल अग्रवाल, मोहित अग्रवाल, प्रदीप अग्रवाल, मयंक अग्रवाल, शिखर अग्रवाल, यशपाल प्रधान, संजय शर्मा, कपिल अग्रवाल, अरविंद अग्रवाल, वेद प्रकाश अग्रवाल, रोहित, संदीप गुप्ता, उदित, विभोर अग्रवाल, मुलायम सिंह आदि सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे 1

बाल विवाह रोकथाम के लिए जिला प्रशासन सजग और मुस्तैद

» **बाल विवाह कराने, सहयोग देन वाले व्यक्ति, संस्था व संगठन को दो वर्ष तक कारावास और 1 लाख रूपये के जुर्माना या दोनों का है प्रावधान**

लोकतंत्र कि शान हसन रशीद जिला ब्यूरो चीफ जबलपुर कटनी मध्य प्रदेश

कटनी - जिले में अक्षय तृतीया पर्व एवं अन्य विवाह मुहूर्तों पर बाल विवाह की रोकथाम के लिए एक सशक्त, समन्वित और बहुस्तरीय व्यापक कार्ययोजना बनाई गई है। इसके लिए विकासखंड स्तर पर संबंधित क्षेत्र के एसडीएम की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय बाल विवाह रोकथाम दल गठित किया गया है। कलेक्टर श्री आशीष तिवारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि बाल विवाह निगरानी समितियां और कोर ग्रुप बाल विवाह संबंधी गतिविधियों पर सख्त नजर रखें। उन्होंने कहा कि बाल विवाह एक गंभीर सामाजिक बुराई है। समाज में इस कुप्रथा का स्वरूप बहुत ही भयावह है। कलेक्टर श्री तिवारी ने बाल विवाह की रोकथाम के लिए समाज से भी आगे आने और जिला प्रशासन के साथ सहयोग करने की अपील की है*। उन्होंने कहा कि बाल विवाह की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम सहित संबंधित एसडीएम और महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारियों को भी दी जा सकती है। कलेक्टर ने ताकीद किया कि प्रशासन बाल विवाह की रोकथाम के लिए सजग और मुस्तैद है। बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 की धारा 9,10,11 एवं 13 के तहत बालविवाह कराने, सहयोग देने वाले व्यक्ति, व्यक्तियों , संस्था, सामाजिक संगठन के लिए दो वर्ष तक कारावास अथवा एक लाख रूपये का जुर्माना या दोनो का प्रावधान है। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास ने हलवाई, प्रेस करने वाले, कैटरर्स, धर्मगुरू, समाज के मुखिया, बैंड बाजा वाले, घोड़ी वाले और ट्रांसपोर्टर आदि से भी अनुरोध किया है कि वे बाल विवाह करने और कराने वालों को अपनी सेवायें कदापि प्रदान नहीं करें, अन्यथा वे भी बाल विवाह के सहयोगी माने जायेंगें और बाल विवाह रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत विधि संगत धाराओं के तहत कार्यवाही के दायरे में आ जायेंगें।

बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल-महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरूआत की गई है। इसके तहत बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल बनाया गया है। यह पोर्टल एक ऐसा अभिनव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो नागरिकों को बाल विवाह की घटनाओं की रिपोर्ट करने, शिकायत दर्ज करने और देशभर में बाल विवाह निषेध अधिकारियों के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम बनाता है। हेल्पलाइन नंबर 181, 1098, 100 और बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल (https://stopchildmarriage.wcd.gov.in) का पर भी सूचना या जानकारी दर्ज कराई जा सकती है।

नौ सौ लीटर जप्त शराब को प्रशासन ने किया नष्ट

» **साढ़े सात लाख से अधिक कीमत की शाराब थी जप्त**

» **ऑपरेशन प्रहार के तहत जप्त मदिरा का नष्टीकरण**

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान

सीधी। कलेक्टर विकास मिश्रा के निर्देशन में संचालित "ऑपरेशन प्रहार" अभियान के तहत आबकारी विभाग सीधी द्वारा न्यायालयीन प्रकरणों में जप्तशुदा मुद्देमाल के नष्टीकरण की कार्यवाही की गई।

कलेक्टर द्वारा अनुमोदित मुद्देमाल नष्टीकरण समिति में राकेश शुक्ला अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास, प्रिया पाठक डिप्टी कलेक्टर एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पालिका सीधी, मीनाक्षी जायसवाल नजूल तहसीलदार सीधी, एकता शुक्ला नायब तहसीलदार तहसील गोपद बनास, भूपेश वैस पुलिस उपनिरीक्षक यातायात एवं प्रीति वर्मा पुलिस उपनिरीक्षक सहित आबकारी विभाग की टीम की उपस्थिति में दिनांक 16 अप्रैल 2026 को नष्टीकरण की कार्रवाई संपन्न हुई। इस दौरान कुल 507 प्रकरणों में जप्त मदिरा, जिसमें 504.72

बल्क लीटर देशी मदिरा प्लेन, 350.28 बल्क लीटर विदेशी मदिरा स्प्रिट, 168.55 बल्क लीटर बीयर एवं 1416 बल्क लीटर हाथ भट्टी मदिरा शामिल थी, का नष्टीकरण किया गया। नष्टीकृत मदिरा की अनुमानित बाजार कीमत लगभग 7 लाख 60 हजार रुपये आंकी गई है।

जैन नर्सरी इंग्लि.मी.हा.से.स्कूल की छात्रा प्राची गर्ग ने जिले की टॉप-10 में जगह बनाई

» **विद्यालय द्वारा सभी बच्चों को विशेष पुरूस्कार से सम्मानित किया**

लोकतंत्र की शान हसन रसीद जिला ब्यूरो चीफ जबलपुर कटनी मध्य प्रदेश

कटनी। जैन नर्सरी इंग्लि. मी.हा.से.स्कूल के छात्र-छात्राओं ने कक्षा 10 वीं एवं 12 की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया जिसमें प्राची गर्ग ने जिलें की टॉप-10 की सूची में 500 में से 489 अंक प्राप्त करते हुये विद्यालय एवं जिलें का नाम रोशन किया बुधवार को मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की दसवीं व बारहवीं का परीक्षा परिणाम घोषित करने के साथ ही मैरिट में स्थान पाने वाले विद्यार्थियों, उनके परिजन व शिक्षक-शिक्षिकाओं में खुशी की लहर दौड़ गई। छात्रा-छात्राओं ने एमपी बोर्ड 10वीं-12वीं में

उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। विद्यालय का कक्षा 12 का रिजल्ट शत प्रतिशत रहा जिसमें प्रमुख रूप से कक्षा 10 वीं के छात्र-छात्राओं में जिलें की टॉप टेन की सूची में प्राची गर्ग- 489-97.5 प्रतिशत,द्वितीय प्रियंका प्रजापति 447-89.4 प्रतिशत एवं तृतीय स्थान सौरभ पटेल 400-80 प्रतिशत अंक रहें इसी प्रकार कक्षा 12 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र अर्थव गुप्ता 435-87 प्रतिशत, द्वितीय स्थान-अश्विन रैकवार 421-84.2 एवं तृतीय राधिका यादव 413-82.6 प्रतिशत प्राप्त करते हुये छात्रों ने अपने सपनों और मेहनत से सफलता पाई इस अवसर पर विद्यालय द्वारा एक सम्मान समारोह में बच्चों की इस सफलता पर उन्हें विशेष उपहारों से सम्मानित किया गया। जो अनुकरणीय रहेगी इस अवसर पर प्राचार्य-श्रीमति वर्षा जैन, कोषाध्यक्ष-ए.पी.चर्तुवेदी, उप-प्राचार्य परम जैन,शिक्षकगण-बसंत गुप्ता, मनोज देशपाण्डेय, अंकिता हाके स्वाति सेन, सतीश विश्वकर्मा, सोनम सोनी, गीता पाण्डेय, की उपस्थिति रही।

कटनी के छात्रों का शानदार प्रदर्शनः MPBSE 10वीं परिणाम 2026 में श्वेता पांडे 98.4% के साथ टॉप सूची में

लोकतंत्र कि शान हसनरसीद जिला ब्यूरो चीफ जबलपुर कटनी मध्य प्रदेश

कटनी : मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) द्वारा घोषित हाईस्कूल (10वीं) परीक्षा 2026 के परिणाम में कटनी जिले के छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रवीण सूची में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई इस वर्ष कटनी जिले के छात्रों छात्राएं ने शानदार अंक प्राप्त कर टॉप सूची में स्थान बनाया, जिससे पूरे जिले में खुशी और गर्व का माहौल है। नोबल हार्ट पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा श्वेता पांडे ने कक्षा दसवीं की मध्य प्रदेश की टॉप 10 सूची में98.4% अंक लाकर कटनी शहर का एवं प्रदेश का नाम रोशन किया। और अपने स्कूल का गौरव बढ़ाया। कटनी नगर के केलवारा खुर्द मार्ग में स्थित नोबल हार्ट इंग्लिश पब्लिक मीडियम हाई सेकेंडरी स्कूल में इस साल 15 अप्रैल 2026 का परिणाम10वीं और 12वीं के सबसे ज्यादा इस स्कूल में किए हैं हाला के और भी अन्य स्कूल हैं जो बच्चों ने टाप किये हैं, जब नोबेल हार्ड के विद्यालय संचालक एवं डायरेक्टर अनिल गर्ग से संपर्क कर जान ना चाहे की इस साल की आपके आपके स्कूल में बच्चे टॉप किए हैं उनके बारे में कुछ प्रकाश डालिए उन्होंने बताया कि बच्चों की शिक्षा पढ़ाई विशेष ध्यान दिया गया है जो भी होमवर्क शिक्षक के माध्यम से दिया जाता था वह लगन पूर्व करते थे और अपनी तैयारी जोर शोर से करते हुए आज बच्चे अपने इस मुकाम में पहुंचे हैं हमारे यहां नर्सरी से बारहवीं तक का स्कूल लगता है हमारे विद्यालय में विशेषता यह है हम मध्यम एवं सामान्य

वर्ग को विशेष ध्यान देते हैं और आज दसवीं कक्षा के छात्रा छात्र मेरिट में आए हैं श्वेता पांडे 98.4 आभा गुरु 96.7 % काजल कुशवाह 96 % नेहा सिंह 92% अंशिकागप्ता। 95,6% प्रशांत महबिया 95.2% सजल गर्ग 93.5%जिन्होंने इस नोबल हायर सेकेंडरी स्कूल का नाम रोशन किया है दसवीं बारहवीं बच्चों को अच्छी शिक्षा देना ताकि उनका भविष्य आगे सुरक्षित रहे हमारे उद्देश्य होता है वैसे भी रिजल्ट देखकर बच्चे बहुत उत्साहित है यह सब डायरेक्टर और प्रिंसिपल टीचर पूरी टीम का मेहनत है जो रंग लाई है आज जिले में एक महत्वपूर्ण स्थान स्थापित कर ली जो अपने आप में गौरव है।

लापरवाही से अधेड़ की मौत,नहीं मिला शव वाहन तो स्कूटी से शव ले जाने को मजबूर हुए परिजन

» **सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सेमरिया का मामला**

लोकतंत्र की शान

सीधी। जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेमरिया से शव को स्कूटी से ले जाने का मामला सामने आया है। घटना बुधवार रात करीब 12 बजे की है। मृतक के बेटों ने आरोप लगाया है कि उनके पिता की अस्पताल में इलाज न मिल पाने से मौत हो गई। शव ले जाने के लिए एंबुलेंस भी नहीं मिली। मजबूरन वे पिता के शव को स्कूटी से लेकर घर गए। अपने परिजन को इस तरह ले जाता देख महिलाएं चीख-चीखकर रोने लगीं। परिजनों के अनुसार बुधवार रात करीब 11 बजे रामसजीवन गुप्ता की तबीयत अचानक बिगड़ी थी। उन्हें तुरंत सेमरिया अस्पताल लाया गया। अस्पताल पहुंचने पर परिजनों को इलाज की कोई मदद नहीं मिली। उनके बेटा-बेटी इलाज के लिए भटकते रहे

लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। ड्यूटी डॉक्टर को तलाशने के दौरान उनके पिता की मौत हो गई। मरीज की मौत के बाद भी परिजनों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्हें शव ले जाने के लिए न तो एंबुलेंस मिली और न ही कोई शव वाहन उपलब्ध कराया गया। मजबूरन परिवार को रामसजीवन गुप्ता के शव को स्कूटी पर बैठाकर घर ले जाना पड़ा।

इनका कहना है। जिस वक्त का मामला बताया जा रहा है रात में वे खाना खाने के लिए अपने कमरे में गए थे। मुझे इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। डॉ. संजय पटेल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेमरिया।

बेटे ने लगाया लापरवाही का आरोप

मृतक रामसजीवन गुप्ता के बेटे संजीव गुप्ता ने आरोप लगाया कि घटना के समय डॉक्टर संजय पटेल की ड्यूटी थी, लेकिन वे अस्पताल में नहीं थे। उन्होंने कहा कि समय पर डॉक्टर मिलते, तो उनके पिता की जान बच सकती थी। उन्होंने यह भी बताया कि अस्पताल प्रशासन ने न इलाज की व्यवस्था की और न शव ले जाने की सुविधा दी। इस मामले में डॉक्टर संजय पटेल ने कहा कि वे खाना खाने अपने कमरे में गए थे। उन्होंने दावा किया कि उन्हें घटना की जानकारी नहीं दी गई थी।

अस्पताल में नहीं थे डयूटी डॉक्टर

मृतक के बेटे संजीव गुप्ता ने आरोप लगाया कि घटना के समय डॉ. संजय पटेल की ड्यूटी थी, लेकिन वे अस्पताल में मौजूद नहीं थे। संजीव गुप्ता ने कहा कि यदि समय पर डॉक्टर उपलब्ध होते तो उनके पिता की जान बचाई जा सकती थी। उन्होंने यह भी बताया कि अस्पताल प्रशासन ने न तो इलाज की व्यवस्था की और न ही शव ले जाने के लिए कोई सुविधा दी। मौत के बाद भी परिजन को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। शव ले जाने के लिए न एंबुलेंस मिली, न शव वाहन। मजबूरन परिवार को मृतक रामसजीवन गुप्ता का शव स्कूटी से घर ले जाना पड़ा।

फायर सर्विस डे पर अल्ट्राटेक सीमेंट वर्क्स बघवार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

लोकतंत्र की शान (ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख)

सीधी। अल्ट्राटेक सीधी सीमेंट वर्क्स बघवार में 14 अप्रेल को फायर सर्विस डे के अवसर पर एक गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत एफएच-एचआर अभिषेक शर्मा, डीएच-एडमिन एवं सिक्योरिटी दिनेश शर्मा तथा सेफ्टी डीएच दिवाकर विश्वकर्मा द्वारा 14 अप्रैल 1944 को शहीद हुए अग्निशमन कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ हुई। इस दौरान उनकी आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखा गया। उल्लेखनीय है कि 14 अप्रैल 1944 को एस.एस. फोर्ट स्टिकीन नामक मालवाहक जहाज में हुए भीषण विस्फोट में कई अग्निशमन कर्मियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। इसी घटना की स्मृति में प्रतिवर्ष फायर सर्विस डे मनाया जाता है। 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक आयोजित फायर सर्विस सप्ताह के दौरान कर्मचारियों एवं उनके परिवारजनों के लिए विभिन्न अग्नि सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित एवं सुरक्षित प्रतिक्रिया के बारे में जानकारी दी जा रही है।

नारी शक्ति बंदन के समर्थन में बोली राधा सिंह

» **देश की दशा और दिशा बदलने में महिलाओं की सहभागिता जरूरी**

» **महिलाओं ने निकाला भव्य जुलूस, मंत्री राधा सिंह शामिल होकर महिलाओं का किया हौसला अफजाई**

लोकतंत्र की शान (ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख)

सीधी । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अत्यंत महत्वाकांक्षी संविधान संशोधन नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में जिले की महिलाओं ने मध्यप्रदेश सरकार की राज्य मंत्री राधा सिंह की अगुवाई और मुख्य आतिथ्य में एवं भाजपा जिला अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान के निर्देशन में विशाल जुलूस बैनर, पोस्टर एवं नारे लिखी हुई दप्पतियो के साथ निकली गई भव्य एवं शानदार महिलाओं की रैली, स्थानीय पूजा पार्क सीधी से होते हुए अस्पताल चौक, सम्राट चौक, कोतवाली मार्ग, गल्ला मंडी, गांधी चौक होते हुए स्थानीय पूजा पार्क के विशाल प्रांगण में समाप्त हुई। जहां पर महिलाओं ने मानव श्रृंखला बनाकर नारी शक्ति राष्ट्र शक्ति, महिलाओं के सम्मान में भाजपा

मैदान में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के साथ प्रधानमंत्री के प्रति अपार स्नेह एवं आभार के साथ संपन्न हुई। रैली में बहनों का उत्साह हाई रहा, हजारों की संख्या में जिले के विभिन्न अंचलों से शामिल हुई। उल्लेखनीय की नारी शक्ति वंधन अधिनियम से महिलाओं को लोकसभा एवं विधानसभा में 33 प्रतिशत सीट आरक्षित होगी और देश के दिशा निर्धारण में महिलाओं की अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूती देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री राधा सिंह की अगुवाई एवं मुख्य अतिथि में सैकड़ो महिलाओं के साथ रैली निकाली गई । रैली का उद्देश्य नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लोकसभा एवं राज्यसभा में पूर्ण बहुमत के साथ पारित करना है। इस अवसर पर प्रमुख रूप से अभियान की संयोजक डॉ मनीला सिंह चौहान, सह संयोजक सुनीता रानी वर्मा, पार्षद पूनम सोनी, विभा शर्मा, जिला पंचायत सदस्य सरस्वती बहेलिया, अनीता चौरसिया, पूर्व जिला पंचायत सदस्य हीराबाई सिंह, जिला पंचायत सदस्य पूजा सिंह कुशराम ,महिमा तिवारी, पूर्व जन भागीदारी अध्यक्ष नीलम पाण्डेय, निशा सिंह चौहान, संगीता सिंह चौहान, ज्योति कुशवाहा, कंचन केसरी सहित सैकड़ो महिलाएं रैली में शामिल हुई।

अंबेडकर जयंती पर एक्सीलेंस एकेडमी में आयोजित हुआ वार्षिकोत्सव

» **उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को हुआ सम्मान**

लोकतंत्र की शान (ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख)

सीधी। चुरहट स्थित एक्सिलेंस एकेडमी एवं कोचिंग में वार्षिकोत्सव डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती पर उत्साह और गरिमा के साथ आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक शरतेंदु तिवारी उपस्थित रहे, वहीं समाजसेवी संजय तिवारी की गरिमामई उपस्थिति रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. डीके त्रिपाठी प्राचार्य पीएम जेएनवी चुरहट ने की। विशेष अतिथियों में अशोक तिवारी प्राचार्य पीएम गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल चुरहट, राजनीश शुक्ला, एडवोकेट रमेश सिंह, विजय सिंह, समाजसेवी सुखनंदन सोनी, द्वारिका प्रसाद गुप्ता, उमेश गुप्ता, रामकृष्ण पटेल, बुद्धिमान पटेल सहित गणमान्यजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विंध्य के स्टार गायक अशिष अकेला पंचू ने अपनी प्रस्तुति से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। साथ ही राज पटेल, सत्यम सोनी, दीपक सिंह, विपुल पांडे, सतीश सोनी, राजेश पटेल, नवनीत सिंह सहित अन्य सम्मानित अतिथियों ने भी अपनी उपस्थिति से समारोह की शोभा बढ़ाई। विद्यालय के विद्यार्थियों ने राजस्थानी, हरियाणवी, छत्तीसगढ़ी, ओडिसी और लोकनृत्यों की मनमोहक प्रस्तुति देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कोरियोग्राफर ज्योत्सना गुप्ता ने विद्यार्थियों को नृत्य की शानदार प्रस्तुतियों के लिए तैयार किया। कार्यक्रम का संचालन हीना कौसर ने किया, जिसमें अनिता मिश्रा, दीक्षा गुप्ता, बबीता सेन, हर्षिता सिंह, मोनिका सिंह, प्रीति तिवारी, निकिता पांडे, फौजिया अली, योगिता मिश्रा ने सहयोग किया। समन्वयक टीम में अमृतलाल पटेल, अमर सिंह दहिया, राजेंद्र कछेर, कमला पटेल, रामरती कुशवाहा, मालती वर्मा, शिवनरेन्द्र तिवारी आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों का हुआ सम्मान

कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार एवं प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। यह सम्मान समारोह विद्यालय के व्यवस्थापक द्वारा आयोजित किया गया, जिन्होंने सभी अतिथियों को स्मृति-चिह्न मोमेंटो भेंट कर उनका अभिनंदन किया। कार्यक्रम के संचालन में विद्यालय के सभी स्टाफ सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। पैट्रन राजकुमार गुप्ता,व्यवस्थापक प्रशांत गुप्ता, प्रधानाध्यापक प्रतीक गुप्ता तथा शिक्षकों में सुनील सिंह, कमलेश पांडे, शतेंद्र पटेल, आदित्यराज पटेल, अमृतलाल साकेत, यशोदा पांडे, सुशीला विश्वकर्मा आदि ने अपनी जिम्मेदारियाँ निभाईं।

संक्षिप्त समाचार

कंबोडिया में अवैध रूप से रह रहे 46 नेपाली नागरिकों को स्वदेश भेजा गया

काठमांडू। कम्बोडिया में अवैध रूप से रह रहे 46 नेपाली नागरिकों को स्वदेश वापस भेजा गया है। कम्बोडिया से बचाकर लाए गए नेपाली नागरिक गुरुवार को नेपाल पहुंचे हैं। थाईलैंड में नेपाली राजदूतावास ने एक बयान में बताया कि ये नेपाली नागरिक विभिन्न लालच में पड़कर अलग-अलग माध्यमों से कम्बोडिया पहुंचे थे, जहां उन्हें अवैध रूप से संचालित ऑनलाइन स्कैमिंग सेंटर, कसीनो में ऑनलाइन ठगी और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों में लगाया गया था। साथ ही वे बिना वीज़ा के वहां रह रहे थे। नेपाल के 46 नागरिक १३ और १४ अप्रैल को भेजे गए, जो गुरुवार को नेपाल पहुंचे हैं। दूतावास ने यह भी जानकारी दी है कि कम्बोडिया में फंसे अन्य नेपाली नागरिकों को वापस लाने के प्रयास जारी हैं। दूतावास के अनुसार नेपाली नागरिकों को ऑनलाइन ठगी जैसे गैरकानूनी कार्यों में लगाया जा रहा है और कई लोग बिना वीज़ा या वीज़ा अवधि समाप्त होने के बाद भी वहां रह रहे हैं। कम्बोडिया के पर्यटन संबंधी आंकड़ों के अनुसार हाल के वर्षों में वहां जाने वाले नेपाली नागरिकों की संख्या तेजी से बढ़ी है। वर्ष 2021 में सिर्फ 101 नेपाली पर्यटक वीज़ा पर कम्बोडिया गए थे। इसके बाद 2022 में यह संख्या 1977, 2023 में 2940, 2024 में 6404 और 2025 में बढ़कर 9676 हो गई है।

ओली और रमेश लेखक के खिलाफ हत्या से जुड़े मामले की जांच के लिए नए दिशा-निर्देश जारी

काठमांडू। जिला अदालत काठमांडू में नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व गृहमंत्री रमेश लेखक के खिलाफ हत्या से जुड़े मामले की जांच के लिए पुलिस को चार बिंदुओं वाला कार्यादेश दिया है। जिला सरकारी वकील कार्यालय के अनुसार, उच्चतम न्यायालय के आदेश पर ओली और लेखक पिछले एक हफ्ते से हाजिरी जमानत पर बाहर हैं। हालांकि उनके खिलाफ जांच की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। दोनों को जरूरत पड़ने पर पुलिस के सामने उपस्थित होने और जांच में सहयोग करने की शर्त पर रिहा किया गया है। इनकी रिहाई के बावजूद मामले की जांच न रोकने के लिए सरकारी वकील कार्यालय ने पुलिस को चार निर्देश दिए हैं। पहले निर्देश में कहा गया है कि 8 सितंबर 2025 को जेन जी आंदोलन के दौरान हुई घटनाओं में मारे गए सभी व्यक्तियों के पोस्टमार्टम संबंधित दस्तावेज संलग्न किए जाएं। इसके अलावा, 8 सितंबर 2025 की घटना के प्रत्यक्षदर्शियों की पहचान कर उनके बयान दर्ज करने का निर्देश भी दिया गया है। तीसरे बिंदु में घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज को साक्ष्य के रूप में शामिल करने को कहा गया है। इस दौरान अगर नए तथ्य आते हैं तो आरोपितों के अतिरिक्त बयान लेने का निर्देश दिया गया है। ओली और लेखक की रिहाई पूरक बयान के लिए उपस्थित होने की शर्त पर की गई है। जिला प्रहरी परिसर काठमांडू के प्रवक्ता एसपी पवन कुमार भट्टराई के अनुसार, अदालत और सरकारी वकील कार्यालय के निर्देशों के अनुसार दोनों की रिहाई के बावजूद मामले की जांच जारी है। ओली और लेखक का प्रारंभिक बयान दर्ज किया जा चुका है। लेखक का बयान जिला सरकारी वकील कार्यालय काठमांडू में लिया गया, जबकि ओली का बयान अस्पताल में ही पुलिस और सरकारी वकील द्वारा दर्ज किया गया। स्वास्थ्य समस्या के कारण ओली गिरफ्तारी के दिन से ही शिक्षण अस्पताल में भर्ती हैं और रिहाई के बाद भी वहीं उपचाररत हैं।

अकासा एयर और स्पाइसजेट के विमान टकराए

नई दिल्ली। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्पाइसजेट का विमान अकासा एयर के विमान से टकरा गया। घटना गुरुवार दोपहर 2 बजे हुई। जानकारी के मुताबिक अकासा एयर की दिल्ली से हैदराबाद जाने वाली फ्लाइट नंबर QP1406 पार्किंग बे से पुशबैक कर रहा था, तभी लेह से दिल्ली आया स्पाइसजेट का B737-700 विमान टेक्सी वे से गेट की तरफ बढ़ते समय उससे टकरा गया। हादसे में स्पाइसजेट विमान के राइट विंगलेट टूट गया। वहीं, अकासा के प्लेन के लेफ्ट होरिजोंटल स्टेबलाइजर को नुकसान पहुंचा है। इस घटना के बाद ग्राउंड क्रू ने तुरंत ही दोनों प्लेन के सभी यात्रियों को सुरक्षित रूप से निकाल लिया। घटना के बाद स्पाइसजेट और अकासा के प्लेन दिल्ली में ही ग्राउंड कर दिए गए हैं, यानी इन्हें अगली उड़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। घटना की जांच की जा रही है। अकासा एयरलाइंस के प्रवक्ता ने बताया कि अकासा एयर की दिल्ली से हैदराबाद जा रही फ्लाइट QP 1406 को 16 अप्रैल 2026 को वापस बे (पार्किंग एरिया) में लौटना पड़ा। ग्राउंड टीम यात्रियों को जल्द से जल्द हैदराबाद भेजने के लिए ऑप्शनल इंतजाम कर रही है।

राजस्थान-एमपी में पारा 42° के पार

नई दिल्ली/भोपाल/जयपुर/लखनऊ। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश , छत्तीसगढ़, दिल्ली, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पिछले दो दिन से पारा 40°C से 44°C के बीच बना हुआ है। बुधवार को राजस्थान के बाड़मेर में 42.8°C, मध्य प्रदेश के नौगांव में 42°C, उत्तर प्रदेश के बांदा में 44°C, महाराष्ट्र के अकोला में 44.2°C, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में 43°C और आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में 43.4°C दर्ज हुआ। गर्मी के चलते मध्य प्रदेश के बुरहानपुर, हरदा, रतलाम में स्कूलों का समय बदल दिया गया है। महाराष्ट्र के वर्धा में गुरुवार को सभी स्कूल बंद रखने के निर्देश हैं। छत्तीसगढ़ में 20 अप्रैल के बाद स्कूल बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अचानक गर्मी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण पश्चिमी विक्षोभ का कमजोर पड़ना है। ऐसा मौसम 20 अप्रैल तक रहेगा, जिसके कारण पश्चिमी, मध्य और दक्षिण भारत में भीषण गर्मी पड़ेगी। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गंगा से सटे बंगाल और नगालैंड में आज बिजली गिरने के साथ आंधी-बारिश होने का अनुमान है। जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी, पंजाब और हरियाणा में बारिश हो सकती है। जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में ओले भी गिर सकते हैं।

यूपी के संभल में ईदगाह-इमामबाड़े को बुलडोजर से ढहाया

संभल। उत्तर प्रदेश के संभल में ईदगाह और इमामबाड़े पर गुरुवार सुबह 8 बजे से दोपहर 2.30 बजे तक बुलडोजर की कार्रवाई चली। इसमें ईदगाह और इमामबाड़ा गिरा दिया गया। इमामबाड़े को तोड़ने के लिए चार बुलडोजर लगे। मौके पर 5 थानों की पुलिस फोर्स और एक कंपनी PAC तैनात रही। इसी बीच, गांव के लोग मौके पर जुट गए। विरोध की आशंका को देखते हुए अफसरों ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया। प्रशासन के मुताबिक, करीब 7 बीघा चारागाह की जमीन पर ईदगाह और खाद गड्ढे की भूमि पर इमामबाड़ा बनाया गया था। गांव वालों की शिकायत के बाद लेखपाल स्पर्श गुप्ता ने 18 जनवरी को तहसीलदार कोर्ट में अपील दायर की थी। 31 जनवरी को कोर्ट के आदेश पर नोटिस अखबार में छपवाया गया था। इसमें कहा गया था कि जो भी कब्जेदार हैं, वे सामने आएं। हालांकि, कोई भी सामने नहीं आया। एक ग्रामीण जुबैदा ने कहा कि यह कार्रवाई रुकनी चाहिए। यहां इमामबाड़े और ईदगाह से सभी को सुविधा मिलती थी। गरीबों की बारातें भी यहीं रुकती थीं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सरकारी जमीन पर निर्माण का मामला है, तो मंदिर भी तो सरकारी जमीन पर बने हैं। लेकिन, कार्रवाई सिर्फ मस्जिदों पर हो रही है। वहीं, गुरुवार सुबह करीब 7.30 बजे एसडीएम निधि पटेल और नायब तहसीलदार दीपक कुमार जुरैल टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वहां कुछ लोग छेनी-हथौड़ी से इमामबाड़ा तोड़ रहे थे। प्रशासन ने उन्हें हटा दिया। मामला कोतवाली संभल क्षेत्र के बिछोली गांव का है।

अमेरिका ने ईरान से निकल रहे 13 जहाजों को लौटाया

एजेंसी, तेल अवीव/तेहरान/वॉशिंगटन डीसी

❑ 3 दिन में एक ने भी होर्मुज क्रॉस नहीं किया, इजराइल-लेबनान की बातचीत आज

अमेरिकी सेना ने कहा है कि उसने ईरान के बंदरगाहों से निकलने की कोशिश कर रहे 13 जहाजों को वापस लौटा दिया। अमेरिकी सेना ने ईरान के समुद्री इलाके में नाकाबंदी कर रखी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के मुताबिक, सोमवार से शुरू हुई इस नाकाबंदी के बाद अब तक कोई भी जहाज इसे पार नहीं कर पाया है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने नाकाबंदी नहीं हटाई, तो वह खाड़ी (Gulf) इलाके में व्यापार को बाधित कर सकता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा कि आज इजराइल और लेबनान के नेता जंग खत्म करने पर सीधे बातचीत करेंगे। यह पिछले 34 साल में दोनों देशों के बीच पहली सीधी बातचीत होगी। इजराइल और लेबनान के नेता आखिरी बार 1991 में मैड्रिड कॉन्फ्रेंस में आमने-सामने बैठे थे।

अमेरिका-ईरान शांति समझौते के करीब पहुंचेः अमेरिका और ईरान 21 अप्रैल को खत्म हो रहे सीजफायर से पहले समझौते के करीब पहुंच रहे हैं। अमेरिकी मीडिया के अनुसार, दोनों पक्षों के बीच बातचीत आगे बढ़ी है, हालांकि कुछ मतभेद अब भी बाकी हैं। इस बीच तेहरान में ईरानी अधिकारियों और पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर के बीच अहम बैठक होगी। मुनीर पहले ही ईरान पहुंचकर विदेश मंत्री अब्बास अराघची से मुलाकात कर चुके हैं और वे अमेरिकी संदेश लेकर गए हैं।

पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। उधर, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के साथ मिलकर बातचीत और ड्राफ्ट प्रस्ताव साझा कर रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक, डील के लिए सीजफायर को बढ़ाया जा सकता है, हालांकि अमेरिका ने अभी औपचारिक सहमति नहीं दी है।

लश्कर के को-फाउंडर आमिर हमजा पर फायरिंग

एजेंसी, लाहौर

♦ अस्पताल में भर्ती, लाहौर में न्यूज चैनल के ऑफिस के बाहर हमला, पिछले साल भी अटैक हुआ था

पाकिस्तान के लाहौर में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के संस्थापक सदस्य आमिर हमजा पर अज्ञात हमलावरों ने गोली चला दी। हमले के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हमलावरों ने लाहौर में एक न्यूज चैनल के दफ्तर के बाहर उन पर फायरिंग की। हमला किसने और क्यों किया, यह अभी साफ नहीं हो पाया है। यह एक साल से भी कम समय में दूसरा मौका है, जब हमजा पर हमला हुआ है। इससे पहले पिछले साल मई में भी उनके घर के बाहर अज्ञात लोगों ने उन्हें गोली मारी थी। पिछले हमले के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। इसके बाद पाकिस्तानी अधिकारियों ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी थी, हालांकि उस घटना पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया था। आतंकी आमिर हमजा 1987 में लश्कर-ए-तैयबा की स्थापना में शामिल 17 लोगों में से एक है। वह आतंकी गतिविधियों, प्रचार, फंड जुटाने और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े कई अखबारों और पत्रिकाओं का संपादन करता था। वह लश्कर की सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी का सदस्य भी रहा है और अन्य आतंकी समूहों के साथ संबंध स्थापित करने में एक्टिव रहा है। हमजा ने हाफिज सईद के नेतृत्व में लश्कर-ए-तैयबा को दूसरे आतंकी समूहों से जोड़ने का काम किया। वह लश्कर से जुड़े एक चैरिटी संगठन का नेतृत्व करता था और लश्कर के यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के बोर्ड में शामिल था, जिसे पहले हाफिज सईद संभालता था।

गाजियाबाद में 200 झोपड़ियों में भीषण आग, सिलेंडर फटे

10 किमी दूर से दिखा धुआं, 22 गाड़ियों ने बुझाई आग

एजेंसी, गाजियाबाद

गाजियाबाद में गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे 200 झुग्गी-झोपड़ियों में भीषण आग लग गई। सिलेंडरों में लगातार धमाके होते रहे। धुएं का गुबार करीब 10 किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया। मौके पर अफरा-तफरी मच गई। लोग अपने घरों का सामान और गैस सिलेंडर लेकर भागते नजर आए। आसपास की इमारतों को एहतियातन खाली करा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। प्रशासन ने नोएडा से भी दमकल की गाड़ियां मंगाईं। आग इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के कनवानी गांव में लगी। घटना में फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। प्रत्यक्षदर्शी आशीष गुप्ता ने बताया कुछ लोग झुग्गियों में खाना बना रहे थे, तभी तिरपाल में आग लग गई। देखते-देखते आग भड़क गई और पास में स्थित पन्नी का गोदाम जलकर राख हो गया। डीएम रविंद्र कुमार ने बताया कि इलाके में कबाड़ का काम होता था। यही काम करने वाले लोग झुग्गियां बनाकर रहते हैं। किसी भी तरह की अनहोनी से निपटने के लिए एंबुलेंस मौके पर मौजूद हैं। पास के अस्पतालों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। इससे पहले, बुधवार को लखनऊ के विकासनगर में झुग्गी-झोपड़ियों में आग लगी थी।

सुप्रीम कोर्ट बोला- बंगाल में सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट बने

एजेंसी, नई दिल्ली

♦ ट्रिब्यूनल 21 अप्रैल तक जिन्हें वोटर मानेगा, वे 23 को वोट डाल सकेंगे

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (16 अप्रैल) को चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह पश्चिम बंगाल में सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट जारी करे। इसमें उन वोटर्स को शामिल किया जाए, जिनकी अपीलों पर ट्रिब्यूनल में फैसला हो गया है। कोर्ट ने कहा कि जिनकी अपीलें पेंडिंग हैं, उन्हें वोट डालने की इजाजत नहीं होगी। बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) में 90.83 लाख वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं। इन वोटर्स की अपील सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं।

बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए दो फेज में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोटिंग होना है। पहले फेज में जहां वोटिंग होना है, वहां 21 अप्रैल तक वोटर्स की अपील पर फैसला हो जाने पर वे वोट दे सकेंगे। वहीं दूसरे फेज वाले इलाकों के वोटर्स 27 अप्रैल तक अपील पर फैसला होने पर वोट डाल सकेंगे। जैसे ही ट्रिब्यूनल नाम जोड़ने का आदेश देगा, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर तुरंत सूची में संशोधन करे। CJI सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच SIR प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इस प्रक्रिया में बड़ी संख्या में नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं।

19 ट्रिब्यूनल के सामने 34 लाख से ज्यादा अपीलेंः सुनवाई के दौरान बताया गया कि 19 ट्रिब्यूनल के सामने 34 लाख से ज्यादा अपीलें लंबित हैं। ये ट्रिब्यूनल रिटायर्ड हाईकोर्ट जजों की अगुवाई में बनाए गए हैं। पश्चिम बंगाल में SIR अभियान का मकसद वोटर लिस्ट से डुप्लिकेट और अयोग्य नाम हटाना बताया जा रहा है। हालांकि इस पर सियासी विवाद तेज है। सत्ताधारी पार्टी ने बड़े पैमाने पर मतदाताओं को बाहर करने का आरोप लगाया है, जबकि ECI इसे निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी बता रहा है।

बंगाल में 11.85% नाम हटे, ज्यादातर बांग्लादेश बॉर्डर के पासः पश्चिम बंगाल में अक्टूबर 2025 में कुल वोटर 7.66 करोड़ थे। इनमें से अब तक 90.83 लाख नाम हटाए गए। लगभग 11.85% वोटर कम हो गए। यानी अब राज्य में 6.76 करोड़ वोटर हैं। चुनाव आयोग ने फाइनल आंकड़े जारी नहीं किए हैं। इसके अलावा जांच के तहत आए 60.06 लाख वोटरों में से 27.16 लाख के नाम हटाए गए। बांग्लादेश सीमा से लगे जिलों में भी बड़े स्तर पर नाम हटे। नॉर्थ 24 परगना में 5.91 लाख में से 3.25 लाख नाम हटे। वहीं, 8.28 लाख में से 2.39 लाख नाम हटे।

महिला आरक्षण से जुड़े विधेयकों पर पक्ष-विपक्ष के दावे, गोगोई ने बताया संविधान विरोधी, सूर्या बोले- दक्षिण को फायदा

एजेंसी, नई दिल्ली

संसद के तीन दिवसीय विशेष सत्र में गुरुवार को महिला आरक्षण से जुड़े तीन अहम संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सरकार पर आरोप लगाया कि महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़कर इसे जटिल बना रही है। जबकि, भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि इन विधेयकों पर विपक्ष का विरोध राजनीतिक रूप से प्रेरित है और दक्षिण भारत को इससे नुकसान नहीं बल्कि फायदा होगा।

लोकसभा में आज चर्चा के दौरान गौरव गोगोई ने कहा कि महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ना गलत है। सरकार बार-बार जनगणना और परिसीमन का बहाना बनाकर महिलाओं को अधिकार देने से बच रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा महिला आरक्षण के पक्ष में रही है और उनकी मांग है कि इसे तुरंत लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि इसे मौजूदा 543 सीटों के साथ ही लागू किया जाना चाहिए ताकि महिलाओं को तुरंत प्रतिनिधित्व मिल सके। यदि सरकार 2023 में विपक्ष की बात मानती तो 2024 के चुनाव से ही महिला आरक्षण लागू हो जाता। सरकार महिला आरक्षण के नाम पर इसे टालने की कोशिश कर रही है और यह बिल महिला विरोधी, संविधान विरोधी और संघीय ढांचे के खिलाफ है।

वहीं, भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि विपक्ष का परिसीमन विरोध राजनीतिक रूप से प्रेरित है और दक्षिण भारत की कुछ पार्टियां भ्रम फैलाने का काम कर रही हैं। विपक्ष के तर्क के हिसाब से अमीरों के पास ज्यादा वोट और गरीबों के पास कम वोट होंगे। विपक्ष और कुछ क्षेत्रीय दल केवल घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि इससे दक्षिण भारत को नुकसान नहीं होगा बल्कि फायदा होगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि केरल की सीटें 20 से बढ़कर 30 होंगी, तमिलनाडु की सीटें 39 से बढ़कर 59 होंगी और आंध्र प्रदेश की सीटें 25 से बढ़कर 37 होने की उम्मीद है।

उन्होंने कहा कि यदि 2027 की जनगणना के आधार पर परिसीमन होता तो दक्षिण भारत को नुकसान होता लेकिन सरकार की वर्तमान योजना से ऐसा नहीं होगा। हर राज्य में सीटों को करीब 50 फीसदी बढ़ाने का फैसला ऐतिहासिक है और यह सभी के साथ न्याय सुनिश्चित करेगा। परिसीमन जरूरी संवैधानिक प्रक्रिया है।

अमेरिका में परमाणु-स्पेस पर रिसर्च करने वाले 5 वैज्ञानिक गायब

एजेंसी, वॉशिंगटन डीसी

अमेरिका में न्यूक्लियर और स्पेस रिसर्च से जुड़े वैज्ञानिकों की मौत और गुमशुदगी के मामलों पर अब व्हाइट हाउस सवालों के घेरे में है। 2023 से अब तक ऐसे 10 मामले सामने आए हैं, जिनमें वैज्ञानिक या अधिकारी या तो लापता हो गए या संदिग्ध हालात में मरे। बुधवार को व्हाइट हाउस ब्रीफिंग में पहली बार प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट स इन घटनाओं पर सवाल पूछा गया। जवाब में उन्होंने कहा, "मैंने अभी संबंधित एजेंसियों से इस बारे में बात नहीं की है। मैं ऐसा करूंगी और आपको जवाब दूंगी।" उन्होंने आगे कहा, "अगर यह सही है, तो यह निश्चित तौर पर ऐसी बात है जिसे सरकार जांच के लायक मानेगा।" उनके इस जवाब के बाद लोगों में नाराजगी देखने को मिली। कई लोगों ने आरोप लगाया कि सरकारी एजेंसियां इस पैटर्न को गंभीरता से नहीं ले रही हैं या फिर इसे छुपाने की कोशिश कर रही हैं।

वैज्ञानिकों के लापता या मौत के सभी मामले अमेरिका की हाई-सिक्योरिटी रिसर्च संस्थाओं से जुड़े बताए जा रहे हैं। इनमें लॉस एलामोस नेशनल लैब, NASA का जेट प्रोपल्शन लैब और MIT का प्लाज्मा साइंस एंड फ्यूजन सेंटर शामिल हैं। ये संस्थान न्यूक्लियर हथियार, एडवांस्ड प्रोपल्शन और नई ऊर्जा तकनीकों पर काम करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई लापता वैज्ञानिक अपने घरों से अचानक पैदल निकल गए।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 अप्रैल को आएंगी हिमाचल

एजेंसी, शिमला

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 अप्रैल से छह दिन के दौरे पर हिमाचल प्रदेश आ रही हैं। राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, वे शिमला, अटल टनल और पालमपुर यूनिवर्सिटी जाएंगी। राष्ट्रपति 27 अप्रैल को दिल्ली से चंडीगढ़ और वहां से सीधे शिमला के कल्याणी हेलिपेड आएंगी। वह दोपहर लगभग 12:15 बजे शिमला पहुंचेंगी और राष्ट्रपति निवास रिट्रीट (छराबड़ा) में ठहरेंगी।

28 अप्रैल की सुबह वे राष्ट्रपति निवास में आयोजित उद्घाटन समारोह में शामिल होंगी। 29 अप्रैल को राष्ट्रपति शिमला से अटल टनल रोहतांग जाएंगी, जहां वे सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगी। इसके बाद शाम को वे वापस छराबड़ा स्थित रिट्रीट लौटेंगी।

30 अप्रैल को पालमपुर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में होंगी शामिलः 30 अप्रैल को राष्ट्रपति पालमपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय के 17वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी और उसी शाम शिमला वापस लौटेंगी। 1 मई को शिमला में "एट होम" कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। 2 मई को राष्ट्रपति मुर्मू दिल्ली लौट जाएंगी। बता दें कि शिमला से लगभग 13 किलोमीटर दूर स्थित छराबड़ा में राष्ट्रपति निवास रिट्रीट है। परंपरागत रूप से राष्ट्रपति यहां ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान ठहरते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी दो बार शिमला का दौरा कर चुकी हैं।

सुप्रीम कोर्ट में चुनावों में वोटिंग अनिवार्य करने की मांग, याचिका खारिज

सीजेआई बोले- जरूरत जागरूकता की है, हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते

एजेंसी, नई दिल्ली

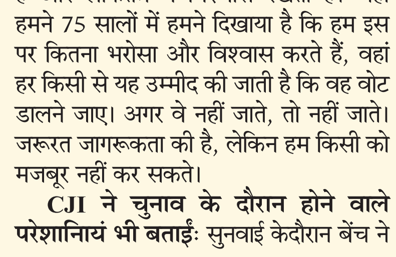

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को देश में वोटिंग अनिवार्य करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसा आदेश नीतिगत दायरे में आता है और न्यायपालिका इसे जारी नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने कहा कि जान-बूझकर वोट न डालने वालों के लिए दंडात्मक कार्रवाई की मांग और वोटिंग अनिवार्य बनाने वाली याचिकाओं पर कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकता। बेंच ने PIL याचिकाकर्ता अजय गोयल से कहा कि वे अपनी शिकायतों को लेकर संबंधित पक्षों से संपर्क करें।याचिकाकर्ता ने यह भी मांग की थी कि जो लोग जान-बूझकर वोट डालने से दूर रहते हैं, उनके लिए सरकारी सुविधाओं पर रोक लगाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।

CJI ने कहा- लोकतंत्र कानूनी दबाव के बजाय जन जागरूकता से फलता-फूलता है। एक ऐसे देश में जो कानून के शासन से चलता है और लोकतंत्र में विश्वास रखता है। जहां हमने 75 सालों में हमने दिखाया है कि हम इस पर कितना भरोसा और विश्वास करते हैं, वहां हर किसी से यह उम्मीद की जाती है कि वह वोट डालने जाए। अगर वे नहीं जाते, तो नहीं जाते। जरूरत जागरूकता की है, लेकिन हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते।

CJI ने चुनाव के दौरान होने वाले परेशानियां भी बताईंः सुनवाई केदौरान बेंच ने अनिवार्य वोटिंग कानून की व्यावहारिक कठिनाइयों का जिक्र किया और कहा कि चुनाव के दिनों में, जजों समेत कई नागरिकों को काम करना पड़ता है। दरअसल, याचिकाकर्ता ने सुझाव दिया था कि कोर्ट को चुनाव आयोग को निर्देश देना चाहिए कि वह वोट न डालने वालों के लिए सरकारी सुविधाओं पर रोक लगाए। इस पर CJI ने घर पर रहने के काम को अपराध बनाने के तर्क पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, "अगर हम आपका सुझाव मान लेते हैं, तो मेरे साथी जस्टिस बागची को वोट डालने के लिए पश्चिम बंगाल जाना पड़ेगा, भले ही उस दिन काम का दिन हो।" बेंच ने समाज के वंचित वर्गों के लिए भी चिंता जताई। बेंच ने पूछा, "अगर कोई गरीब व्यक्ति कहता है कि मुझे अपनी दिहाड़ी कमानी है, तो मैं वोट कैसे डालूं, हम उनसे क्या कहें।" याचिकाकर्ता ने कहा कि चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वह एक समिति बनाए, जो उन लोगों पर रोक लगाने के प्रस्ताव दे, जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने में नाकाम रहते हैं।

महिला आरक्षण बिल अब केवल महिला सशक्तिकरण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह उत्तर बनाम दक्षिण, जनसंख्या बनाम प्रतिनिधित्व और सत्ता बनाम संतुलन की बहस में बदला-संसद में सियासी रण का गहन विश्लेषण

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं

» विशेष संसद सत्र में तीखी बहस-महिला आरक्षण बनाम परिसीमन- विपक्ष को महिला आरक्षण का विरोध नहीं परिसीमन के साथ जोड़ने का विरोध?

» विपक्ष को परिसीमन के बाद संसद में सत्ता संतुलन और अधिक एकतरफा होने की आशंका छाई- सियासी लड़ाई उत्तर बनाम दक्षिण पर आई-पुरे विश्व नें नज़रें लगाई -एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र

महिला आरक्षण-परिसीमन विधेयक में ऐसा क्या है जो विरोध में उतर आया विपक्ष?

गोंदिया - वैश्विक स्तरपर भारत की संसदीय राजनीति एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर खड़ी है,जहाँ एक ओर महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐतिहासिक प्रयास दिखाई देता है,वहीं दूसरी ओर परिसीमन (डेलिमिटेशन) के माध्यम से राजनीतिक शक्ति संतुलन में संभावित बदलाव ने व्यापक विवाद को जन्म दिया है। संसद के विशेष सत्र में पेश किए गए तीन प्रमुख विधेयक (1) महिला आरक्षण से संबंधित संवैधानिक संशोधन बिल 2026 (2) परिसीमन (डेलिमिटेशन) बिल2026 (3) केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े कानूनों में संशोधन बिल 2026 जहां कानून मंत्री ने संवैधानिक संशोधन और परिसीमन बिल पेश किए, वहीं केंद्रीय गृहमंत्री ने केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ासटीक संशोधन विधेयक पेश किया। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं क़ि महिला आरक्षण से संबंधित संवैधानिक संशोधन,परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े संशोधन ने न केवल राजनीतिक बहस को तेज किया है,बल्कि देश के संघीय ढांचे, प्रतिनिधित्व और क्षेत्रीय संतुलन को लेकर गहरे सवाल भी खड़े कर दिए हैं। यह मुद्दा अब केवल महिला सशक्तिकरण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह उत्तर बनाम दक्षिण,जनसंख्या बनाम प्रतिनिधित्व और सत्ता बनाम संतुलन की बहस में बदल चुका है। 16 अप्रैल 2026 को विशेष संसद सत्र के पहले दिन सरकार द्वारा पेश किए गए तीनविधेयकों में सबसे अधिक ध्यान महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक पर केंद्रित रहा। संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 के तहत लोकसभा की सीटों को बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव रखा गया है,जिसमें 815 सीटें राज्यों और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्धारित की गई हैं। इसके साथ ही लगभग 272 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने की योजना है। तीनों बिलों को संसद में पेश करने के लिए ध्वनि मत से रखने के लिए विपक्ष तैयार नहीं हुआ इसलिए वोटिंग करानी पड़ी वोटिंग के दौरान सरकार को 251 सांसदों का समर्थन मिला,जबकि 185 सांसदों ने विरोध किया। यह स्पष्ट संकेत है कि संसद में यह मुद्दा केवल नीतिगत नहीं बल्कि गहराई से राजनीतिक और क्षेत्रीय विभाजन का विषय बन चुका है। ध्वनि मत के बजाय डिवीजन की मांग ने इस विवाद को और अधिक औपचारिक और गंभीर बना दिया।

साथियों बात अगर हम महिला आरक्षण बनाम परिसीमन असली विवाद कहाँ है? इसको समझने की करें तो यह समझना महत्वपूर्ण है कि विपक्ष महिला आरक्षण का विरोध नहीं कर रहा,बल्कि उसका मुख्य विरोध इस बात से है कि महिला आरक्षण को परिसीमन के साथ जोड़ा गया है। विपक्ष का कहना है कि महिला आरक्षण को तुरंत लागू किया जाना चाहिए,न कि इसे जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया से जोड़कर टाल दिया जाए दरअसल 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने के लिए यह आवश्यक शर्त रखी गई थी कि पहले नई जनगणना होगी और उसके बाद परिसीमन के जरिए नई सीटों का निर्धारण किया जाएगा। यहीं से विवाद की जड़ शुरू होती है। विपक्ष इसे एक डिले टैक्टिक यानी देरी करने की रणनीति मानता है,जबकि सरकार इसे संरचनात्मक सुधार का महत्वपूर्ण तथा आवश्यक हिस्सा बताती है।

साथियों बात अगर हम विशेष रूप से परिसीमन का गणित: जनसंख्या आधारितप्रतिनिधित्व का सवाल इसको समझने की करें तो, परिसीमन का मूल उद्देश्य जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन करना होता है। लेकिन भारत में 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों का निर्धारण लंबे समय तक स्थिर रखा गया, ताकि परिवार नियोजन को बढ़ावा देने वाले राज्यों को नुकसान न हो। 1976 में यह तय किया गया कि 2026 तक परिसीमन नहीं होगा। अब जब 2026 के बाद परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है,तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्याजनसंख्या के आधार पर सीटों का पुनर्वितरण किया जाएगा? यदि ऐसा होता है,तो उत्तर भारत के अधिक जनसंख्या वाले राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश,बिहार,मध्य प्रदेश को अधिक सीटें मिलेंगी,जबकि दक्षिण भारत के अपेक्षाकृत कम जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों जैसे तमिलनाडु,केरल, कर्नाटक की सीटें घट सकती हैं।यही वह बिंदु है जहाँ यह मुद्दा एक राष्ट्रीय बहस से क्षेत्रीय संघर्ष में बदल जाता है। दक्षिण भारतीय राज्यों का तर्क है कि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में सफलता हासिल की है, शिक्षा और स्वास्थ्य में बेहतर प्रदर्शन किया है,और अब उन्हें सजा के रूप में कमप्रतिनिधित्व दिया जा रहा है।दक्षिण के राजनीतिक दलों, विशेषकर डीएमके और कांग्रेस, ने इसे संघीय ढांचे के लिए खतरा बताया है। उनका मानना है कि इससे संसद में दक्षिण की आवाज कमजोर हो जाएगी और राष्ट्रीय नीतियों में उनका प्रभाव घट जाएगा। यह स्थिति भारत के संघीय संतुलन को अस्थिर कर सकती है।

साथियों बात अगर हम सत्ताधारी पार्टी का दृष्टिकोण: समान वृद्धि और संतुलन का दावा इसको समझने की करें तो,सरकार का पक्ष इससे अलग है। सरकार का कहना है कि सभी राज्यों में सीटों की संख्या समान अनुपात में बढ़ाई जाएगी,जिससे किसी राज्य कावर्तमान प्रतिनिधित्व कम नहीं होगा।पीएम ने संसद में अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि यह कदम महिलाओं को राजनीतिक मुख्यधारा में लाने और लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाने के लिए उठाया गया है।सरकार का यह भी दावा है कि परिसीमन आयोग निष्पक्ष रूप से काम करेगा और किसी राज्य के साथ भेदभाव नहीं होगा।उनके अनुसार, यह केवल जनसंख्या के आधार पर नहीं बल्कि व्यापक प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखकर किया जाएगा।

साथियों बात अगर हम राजनीतिक आशंका: क्या यह पोलिटिकल कूप है? इसको समझने की करें तो विपक्ष का आरोप है कि यह पूरा कदम एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है,जिससे उन राज्यों में सीटें बढ़ाई जाएँगी जहाँ सत्ताधारी दल का प्रभाव अधिक है। हिंदी भाषी उत्तर भारतीय राज्यों में बीजेपी की मजबूत पकड़ को देखते हुए विपक्ष को आशंका है कि परिसीमन के बाद संसद में सत्ता संतुलन और अधिक एकतरफा हो सकता है।यह आशंका केवल राजनीतिक नहीं बल्कि संरचनात्मक भी है, क्योंकि संसद में सीटों का वितरण सीधे तौर पर नीति निर्माण और संसाधनों के आवंटन को प्रभावित करता है।

साथियों बात अगर हम जनगणना का सवाल: बिना डेटा के निर्णय? इसको समझने की करें तो एक और महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि परिसीमन से पहले जनगणना होनी चाहिए या नहीं। विपक्ष का कहना है कि बिना नई जनगणना के परिसीमन करना तर्कसंगत नहीं है,क्योंकि इससे वास्तविक जनसंख्या का सही प्रतिनिधित्व नहीं होगा।सरकार ने संविधान में जनसंख्या की परिभाषा को संशोधित कर यह प्रावधान किया है कि संसद जिस जनगणना को मान्यता देगी,उसी के आधार पर परिसीमन होगा। इससे सरकार को कुछ हद तक लचीलापन मिल जाता है, लेकिन इससे पारदर्शिता पर सवाल भी उठते हैं।

साथियों बात कर हम लोकसभा का विस्तार: प्रतिनिधित्व या जटिलता? इसको समझने की करें तो लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 करना एक बड़ा कदम है। यह दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था को और भी विशाल बना देगा। इससे प्रतिनिधित्व तो बढ़ेगा,लेकिन साथ ही निर्णय लेने की प्रक्रिया और अधिक जटिल हो सकती है।इतिहास पर नजर डालें तो लोकसभा की सीटें समय-समय पर बढ़ाई गई हैं, लेकिन इस बार का विस्तार अभूतपूर्व है। यह बदलाव न केवल राजनीतिक बल्कि प्रशासनिक और संवैधानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। बता दें लोकसभा में कब-कब बढ़ी सांसदों की संख्या, वर्ष /सीटें 1950/ 489, 1956/494, 1962/520, 1973/545 (जिसमें 2 एंग्लो इंडियन नामित) 2020+543 (एंग्लो-इंडियन मनोनयन समाप्त होने से) 2026 / 8 5 0 (प्रस्तावित) अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि लोकतंत्र का विस्तार या नई असमानता की शुरुआत?महिला आरक्षण और परिसीमन का यह पूरा मुद्दा भारतीय लोकतंत्र के लिए एक दोधारी तलवार की तरह है। एक ओर यह महिलाओं को सशक्त बनाने और प्रतिनिधित्व बढ़ाने का अवसर देता है, वहीं दूसरी ओर यह क्षेत्रीय असंतुलन और राजनीतिक ध्रुवीकरण को भी बढ़ा सकता है। यह स्पष्ट है कि यह केवल एक विधेयक नहीं बल्कि भारत के राजनीतिक भविष्य की दिशा तय करने वाला निर्णय है। यदि इसे संतुलित, पारदर्शी और सहमति के साथ लागू किया गया, तो यह लोकतंत्र को मजबूत करेगा। लेकिन यदि इसमें राजनीतिक लाभ-हानि का संतुलन हावी रहा, तो यह उत्तर-दक्षिण विभाजन को और गहरा कर सकता है।इसलिए,यह सवाल केवल यह नहीं है कि महिलाओं को आरक्षण मिले या नहीं, बल्कि यह है कि भारत का लोकतंत्र किस दिशा में आगे बढ़ेगा समावेशिता की ओर या विभाजन की ओर इस पर सबकी नज़रें लगी हुई है।

-संकलनकर्ता लेखक - क़र विशेषज्ञ स्तंभकार साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्यम सीए (एटीसी) एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र 9284141425

आस्था के नाम पर फैलते छल से बचकर ही सुरक्षित रहेगी किसान की मेहनत

लेखक- डॉ. सत्यवान सौरभ

उत्तर भारत के गाँवों में गेहूँ की कटाई केवल एक मौसम नहीं, बल्कि जीवन का उत्सव होती है। यह वह समय है जब किसान की महीनों की तपस्या, धूप में जले हाथ, सर्द रातों की पहरेदारी और अनिश्चित मौसम के साथ लड़ी गई जंग अंततः रंग लाती है। खेतों में झूमती सुनहरी बालियाँ किसी साधारण फसल का दृश्य नहीं, बल्कि आशा, संघर्ष और आत्मसम्मान का प्रतीक होती हैं। जब यही फसल कटकर घर के आँगन में ढेर बनाती है, तो वह केवल अनाज नहीं होती—वह पूरे साल की सुरक्षा होती है, बच्चों की पढ़ाई का आधार, बीमारियों में सहारा, और भविष्य की अनिश्चितताओं से लड़ने की ताकत होती है। घर की महिलाएँ उस अनाज को सहेजती हैं, साफ करती हैं, सुखाती हैं और बड़े जतन से उसे भंडार में रखती हैं, क्योंकि वे जानती हैं कि यही दाने आने वाले समय में घर की नींव को मजबूत बनाए रखेंगे। लेकिन इस सुनहरे और संतोष भरे दृश्य के साथ ही एक ऐसी परछाईं भी गाँव की गलियों में उतरने लगती है, जो धीरे-धीरे इस खुशी को कम करने लगती है। यह परछाईं है झोली लेकर घूमने वाले तथाकथित बाबाओं और मोड़ों की, जो इसी मौसम का इंतजार करते हैं। जैसे ही अनाज घरों में आता है, ये लोग अचानक गाँवों में दिखाई देने लगते हैं। उनके वस्त्र, उनका रूप और उनकी वाणी सब कुछ इस तरह से रचा गया होता है कि वे श्रद्धा के पात्र प्रतीत हों। माथे पर तिलक, सिर पर पटका या टोपी, रंग-बिरंगे कपड़े और हाथ में एक झोली—यह सब मिलकर एक ऐसा रूप तैयार करते हैं, जिसे देखकर सामान्य ग्रामीण सहज ही प्रभावित हो जाता है। वे घर-घर जाकर दरवाजे पर खड़े होते हैं और मीठे शब्दों में आशीर्वाद देते हैं—"भगवान भला करेगा", "माता रानी कृपा बनाए रखे"—और बदले में कुछ अनाज या पैसे की अपेक्षा रखते हैं। गाँवों में दान और सेवा की परंपरा सदियों से चली आ रही है। यह परंपरा केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक भी है, जो आपसी सहयोग और सह-अस्तित्व की भावना को मजबूत करती है। खासकर महिलाएँ इस परंपरा को निभाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे घर की दहलीज पर खड़ी होकर आने-जाने वालों का स्वागत करती हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देती हैं। उनके लिए यह केवल एक सामाजिक कर्तव्य नहीं, बल्कि आस्था का हिस्सा होता है। लेकिन यही आस्था कई बार उनकी कमजोरी बन जाती है, जब कुछ लोग इसका लाभ उठाने लगते हैं। एक घर से दी गई एक मुट्ठी गेहूँ शायद बहुत छोटी बात लगती है। देने वाले को लगता है कि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यही प्रक्रिया जब पूरे गाँव में दोहराई जाती है, तो यह छोटी-छोटी मुट्ठियाँ मिलकर एक बड़े ढेर में बदल जाती हैं। दिन भर में सैकड़ों घरों से इकट्ठा किया गया अनाज शाम तक एक बड़ी मात्रा में पहुँच जाता है। इसके बाद यह अनाज अक्सर बाजार में बेच दिया जाता है, और उससे प्राप्त धन का उपयोग जरूरी जरूरतों के बजाय नशे, जुए या अन्य अनुचित गतिविधियों में होने की शिकायतें सामने आती हैं। इस प्रकार, जो अनाज किसान ने अपने खून-पसीने से उगाया था, वह धीरे-धीरे ऐसे हाथों में चला जाता है जहाँ उसका सम्मान नहीं होता। यह केवल आर्थिक नुकसान की बात नहीं है, बल्कि यह विश्वास के टूटने की कहानी भी है। जब कोई व्यक्ति धर्म और आस्था का सहारा लेकर किसी की मेहनत का लाभ उठाता है, तो वह केवल संसाधनों की चोरी नहीं करता, बल्कि सामाजिक मूल्यों को भी कमजोर करता है। इससे भी अधिक चिंताजनक स्थिति तब होती है जब कुछ लोग दान न देने पर डराने-धमकाने का सहारा लेते हैं। "अगर दान नहीं दिया तो अनिष्ट होगा", "घर में अशांति आ जाएगी"—ऐसे शब्द केवल अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते, बल्कि लोगों के मन में अनावश्यक भय भी पैदा करते हैं। यह भय खासकर महिलाओं और बुजुर्गों को प्रभावित करता है, जो पहले से ही धार्मिक मान्यताओं से गहराई से जुड़े होते हैं। हालाँकि, इस पूरी तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। समाज में ऐसे लोग भी हैं जो वास्तव में जरूरतमंद हैं—बुजुर्ग, विकलांग या ऐसे व्यक्ति जिनके पास जीवनयापन का कोई साधन नहीं है। उनके लिए भिक्षा माँगना कोई विकल्प नहीं, बल्कि मजबूरी होती है। उनके चेहरे पर बनावटीपन नहीं, बल्कि संघर्ष और थकान की सच्चाई झलकती है। इसलिए हर झोली लेकर आने वाले व्यक्ति को एक ही नजर से देखना उचित नहीं होगा। यही वह बिंदु है जहाँ विवेक और संवेदनशीलता दोनों की आवश्यकता होती है।

महिला आरक्षण बिल के बाद बदलेगी संसद की सूरत

लेखक-सौरभ वार्ष्णेय

१६ अप्रैल से संसद का विशेष संत्र आयोजित होने जा रहा है। इस सत्र में भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था एक नए दौर में प्रवेश कर रही है। लंबे इंतजार और व्यापक राजनीतिक विमर्श के बाद पारित हुआ महिला आरक्षण बिल—जिसे आधिकारिक रूप से नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाता है—देश की संसद और विधानसभाओं की संरचना में ऐतिहासिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करता है। यह विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करता है, जो भारतीय राजनीति में लैंगिक संतुलन की दिशा में एक निर्णायक कदम माना जा रहा है। आज तक भारतीय संसद में महिलाओं की भागीदारी सीमित रही है। हालांकि इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज और ममता बनर्जी जैसी प्रभावशाली महिला नेताओं ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है, लेकिन कुल संख्या के लिहाज से महिलाएं अब भी कम प्रतिनिधित्व वाली श्रेणी में रही हैं। ऐसे में यह आरक्षण बिल केवल संख्या बढ़ाने का नहीं, बल्कि नीति निर्माण में महिलाओं की दृष्टि और संवेदनशीलता को शामिल करने का प्रयास भी है। इस विधेयक के लागू होने के बाद संसद की सूरत में व्यापक बदलाव देखने को मिल सकता है। अधिक संख्या में महिला सांसदों की भागीदारी से सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा और पोषण जैसे मुद्दों पर अधिक गंभीरता से चर्चा होने की संभावना है। इससे नीतियां अधिक समावेशी और जमीनी हकीकत के करीब बन सकती हैं। हालांकि, इस बदलाव के साथ कुछ चुनौतियां भी सामने आएंगी। राजनीतिक दलों को योग्य महिला उम्मीदवारों को तैयार करने और उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में ठोस प्रयास करने होंगे। केवल आरक्षण से ही वास्तविक सशक्तिकरण संभव नहीं है; इसके लिए सामाजिक मानसिकता में बदलाव और राजनीतिक प्रशिक्षण भी उतना ही आवश्यक है। इसके अलावा, आरक्षण की व्यवस्था को लागू करने के लिए परिसीमन की प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण होगी, जो इस कानून के क्रियान्वयन को प्रभावित कर सकती है। इस कारण, इसके प्रभावी लागू होने में समय लगने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।फिर भी, यह कहना गलत नहीं होगा कि महिला आरक्षण बिल भारतीय लोकतंत्र को अधिक प्रतिनिधिक, संतुलित और संवेदनशील बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर है। यह न केवल संसद की सूरत बदलेगा, बल्कि राजनीति की सोच और प्राथमिकताओं को भी नई दिशा देगा। यह विधेयक केवल महिलाओं के अधिकारों की बात नहीं करता, बल्कि एक मजबूत, समावेशी और न्यायपूर्ण भारत के निर्माण की आधारशिला रखता है। केंद्र सरकार ने हाल ही में उन आशंकाओं को दूर करने का प्रयास किया है, जो 2029 तक विधानसभाओं में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू करने के लिए प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया को लेकर विशेषकर दक्षिण भारतीय राज्यों में उभर रही हैं। यह मुद्दा केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि संघीय ढांचे, प्रतिनिधित्व के संतुलन और लोकतांत्रिक विश्वास से भी जुड़ा हुआ है।महिला आरक्षण का उद्देश्य राजनीति में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। लंबे समय से संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी अपेक्षाकृत कम रही है। ऐसे में 33त्न आरक्षण का प्रावधान एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। लेकिन इसके साथ जुड़ा परिसीमन का सवाल कई जटिलताओं को जन्म देता है। परिसीमन का अर्थ है जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण। 2026 के बाद होने वाली संभावित परिसीमन प्रक्रिया में जनसंख्या के वर्तमान आंकड़ों को आधार बनाया जाएगा। यहीं से दक्षिण भारत के राज्यों की चिंता शुरू होती है। इन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया है, जबकि उत्तर भारत के कुछ राज्यों में जनसंख्या वृद्धि अधिक रही है। ऐसे में आशंका है कि परिसीमन के बाद दक्षिणी राज्यों की सीटें घट सकती हैं, जिससे उनकी राजनीतिक ताकत कमजोर हो सकती है। केंद्र सरकार का कहना है कि महिला आरक्षण और परिसीमन दो अलग-अलग प्रक्रियाएँ हैं, और किसी भी राज्य के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि संतुलन और न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए ही कोई निर्णय लिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल आश्वासन से राज्यों की चिंताएँ दूर हो जाएंगी? यह भी समझना जरूरी है कि महिला आरक्षण को परिसीमन से जोडऩे का प्रावधान क्यों रखा गया। इसका एक कारण यह है कि नए सिरे से सीटों का निर्धारण होने पर आरक्षित सीटों का संतुलित और न्यायसंगत वितरण संभव हो सके। लेकिन यही प्रावधान अब राजनीतिक विवाद का कारण बन रहा है। समाधान के लिए आवश्यक है कि केंद्र और राज्यों के बीच संवाद और विश्वास कायम रखा जाए। एक ऐसा मॉडल विकसित किया जाए, जिसमें महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए क्षेत्रीय संतुलन भी बना रहे। संभव है कि परिसीमन के लिए केवल जनसंख्या ही नहीं, बल्कि अन्य मानकों को भी शामिल किया जाए, ताकि न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके।महिला आरक्षण एक सामाजिक और लोकतांत्रिक आवश्यकता है, लेकिन इसे लागू करने की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जो किसी भी क्षेत्र या राज्य के साथ असमानता की भावना पैदा न करे। यह समय राजनीतिक परिपक्वता और दूरदर्शिता दिखाने का है, ताकि देश एक समावेशी और संतुलित लोकतंत्र की ओर आगे बढ़ सके।

महिला आरक्षणः एक सामाजिक और लोकतांत्रिक आवश्यकता- भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी केवल एक अधिकार नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की अनिवार्यता है। लंबे समय से राजनीति और नीति-निर्माण के केंद्र में पुरुषों का वर्चस्व रहा है, जिसके कारण महिलाओं से जुड़े कई मुद्दे अपेक्षित प्राथमिकता नहीं पा सके। ऐसे में महिला आरक्षण का प्रश्न केवल प्रतिनिधित्व का नहीं, बल्कि बराबरी और सशक्तिकरण का भी है।महिलाएं देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन संसद और विधानसभाओं में उनकी भागीदारी अभी भी सीमित है। पंचायत स्तर पर आरक्षण लागू होने के बाद यह स्पष्ट हो चुका है कि जब महिलाओं को अवसर मिलता है, तो वे न केवल प्रभावी नेतृत्व करती हैं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव भी लाती हैं। इस अनुभव को उच्च स्तर की राजनीति में लागू करना समय की मांग है।महिला आरक्षण सामाजिक असमानताओं को दूर करने का एक प्रभावी माध्यम बन सकता है। भारतीय समाज में अब भी कई स्तरों पर लैंगिक भेदभाव मौजूद है, जो महिलाओं की प्रगति में बाधा बनता है। आरक्षण नीति उन्हें एक सशक्त मंच प्रदान करती है, जहां वे अपनी आवाज़ बुलंद कर सकती हैं और अपने अधिकारों की रक्षा कर सकती हैं।लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें सभी वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व हो। यदि आधी आबादी निर्णय-निर्माण प्रक्रिया से बाहर रहती है, तो लोकतंत्र अधूरा ही रहेगा। महिला आरक्षण इस अधूरेपन को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

भक्ति नहीं है हिन्दू युवा शक्ति को ढोल मंजीरा नचैया बनाने का खेल!

लेखक - मनोज कुमार अग्रवाल

अभी दो दिन पहले वृंदावन में यमुना जी में स्टीमर पलटने से हुए हादसे में महिलाओं बच्चों समेत करीब डेढ़ दर्जन जीवन अकाल मौत का शिकार हो गए। वहीं इस हादसे के एक दिन बाद ही वृंदावन में ही एक कथावाचक मृदुल कृष्ण शास्त्री और श्रद्धालुओं की कार भिड़ंत के बाद रोडरेज मारपीट की वारदात भी चर्चा का बिंदु बनी है। आज इन दोनों हादसा और वारदात तथा धर्म नगरी में फैले अनाचार कदाचार दुर्व्यवहार और धर्म के नाम पर चल रही दुकान का सटीक विश्लेषण करने की जरूरत है । सबसे पहले वृंदावन की नाव दुर्घटना का संदर्भ लें किस तरह लुधियाना से आए श्रद्धालुओं के परिवार जरा सी लापरवाही और प्रशासन की नाकामी के चलते अपना जीवन दे गए। आपको पता हो कि मथुरा के वृंदावन में यमुना में हुए नाव हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया है. हादसे के तीन दिन बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जहां 13 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं 3 लोग अब भी लापता हैं. सेना, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की बड़ी टीम लगातार सर्च ऑपरेशन में जुटी है. वृंदावन में एक नाव हादसे ने कई परिवारों की खुशियां छीन लीं. वहीं कुछ परिवार अब भी अपने अपनों के मिलने की आस में नदी किनारे टकटकी लगाए खड़े हैं. हादसा शुक्रवार को हुआ, जब श्रद्धालुओं से भरी एक मोटर बोट देवरहा बाबा के दर्शन के लिए जा रही थी. किसे पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होगा. इस हादसे में मरने वाले अधिकांश युवक युवती और बच्चे शामिल हैं। इस हादसे में मृत डिंकी बीए फाइनल ईयर की छात्रा थी, जिसके सपने अभी अधूरे ही रह गए. वहीं ऋषभ शर्मा 12वीं पास था और अपने पिता के काम में हाथ बंटाता था. दोनों अपने परिवार के साथ धार्मिक यात्रा पर निकले थे, लेकिन यह यात्रा कभी खत्म न होने वाले दर्द में बदल गई. युवा शक्ति को पुरूषार्थी योगी पराक्रमी चरित्रवान नैतिकता और सदाचार का कठोर जीवन अभ्यास करने वाला साहसी निडर धर्म रक्षक देश भक्त बनने की प्रेरणा दें सिर्फ ढोलक मंजीरे नृत्य से मनोरंजन से पर्यटन और कुछ फर्जी बाबाओं गुरू घंटालो की जेब भरने का व्यवसाय चल रहा है और युवा पीढ़ी का धर्म और भक्ति की गलत व्याख्या कर धर्मभीरू परावलंबी कृतध्न और चमत्कार की उम्मीद में जीवन को तबाह बर्बाद करने की ओर धकेलने की धृष्टता अक्षम्य अपराध है। सनातन संस्कृति को सबसे ज्यादा खतरा इसकी आड़ लेकर धर्म के नाम पर अनर्थ कर रहे छिपे कालनेमियो से है। विचार करें सिर्फ़ लाइफ जेकेट पहन लेते तो पंद्रह जीवन बचाए जा सकते थे। अब दूसरी वारदात का हवाला लें कोतवाली क्षेत्र के राधानिवास स्थित बस स्टैंड के समीप शनिवार की दोपहर कथावाचक आचार्य मृदुलकांत शास्त्री अपनी कार से घर जा रहे थे।इसी दौरान दिल्ली के श्रद्धालुओं की कार ने ओवरटेक करते हुए दोनों कार टकरा गयी । कथावाचक के चालक ने श्रद्धालुओं की कार को रोका और चाबी निकाल कर कालर पकड़ कर बाहर निकाला जिस पर दोनो पक्षों में मारपीट शुरू हो गई ।आरोप है कि कार में टक्कर कथावाचक और उनके कार चालक ने उतरकर दिल्ली के श्रद्धालुओं से अपना विरोध जताया तो वह बदसलूकी करने लगे। श्रद्धालु सुरेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति ने स्वजन के साथ मिलकर कथावाचक और चालक भगवान सिंह संग मारपीट की।कथावाचक शास्त्री ने रोडरेज की इस वारदात को लूट का रंग दे दिया। तहरीर के अनुसार जब ड्राइवर भगवान सिंह ने टक्कर का विरोध किया, तो विपक्षी कार से सुरेंद्र सिंह नामक व्यक्ति अपने पांच अन्य साथियों जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं के साथ नीचे उतरा। आरोप है कि इन लोगों ने उतरते ही गाली-गलौज शुरू कर दी और मृदुल कांत शास्त्री के साथ मारपीट की। हमलावरों ने उनके कपड़े फाड़ दिए और गले से सोने की चेन व रुद्राक्ष की माला तोड़कर गायब कर दी। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि हमलावरों ने उन पर जान से मारने की नीयत से हमला किया था। कथावाचक और उनके सहयोगी स्थानीय लोगों के दबाव में तीन महिलाओं दो छोटे बच्चों समेत छह लोगों को रात भर पुलिस हिरासत में रखा गया। काफी चिरौरी के बावजूद कथावाचक अपने डीआईजी एसएसपी सर्किल अफसर और कोतवाल से सहयोग मिलने के बयान देते रहे उधर आकस्मिक तनाव में रोडरेज का दूसरा पक्ष महिलाओं बच्चो को भूखे हवालात में रखा गया लेकिन कथावाचक अपनी शान में कथित गुस्ताखी के लिए महिलाओं बच्चो को भी हवालात से बाहर कराने के लिए तैयार नहीं हुए। यह बेहद शर्मनाक है कि मंचों पर क्षमा करुणा और परोपकार का प्रवचन करने वाला कथित संत महिलाओं बच्चो को लाकअप में रखवा कर आत्मसंतुष्टि अनुभव करते हैं। दूसरे पक्ष का आरोप है कि पुलिस ने एकतरफ़ा कारवाई की। कथावाचक ने रसूख का दुरुपयोग कर के इस परिवार के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर के इनको पूरी रात पुलिस लॉकअप में बन्द रखते हैं। इस तरह का एकतरफ़ा प्रकरण ब्रज क्षेत्र के धर्माटन और पर्यटन लिए पतन का कारण भी बन सकता है। यहां श्रद्धालु परिवार दर्शन के लिए आते हैं और श्रद्धा के साथ आते हैं उनके सम्मान की और सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? यदि ऐसे पक्षपात पूर्ण कारवाई होगी तो एक दिन वो आजाएगा कि श्रद्धालु बृज में आने से ही डरेगा। आपको बता दें कि कथा का धंधा इंडस्ट्री बन गया है कथा वाचक अपने तिलिस्म और रसूख के बूते पर तमाम कानून को अपने चरणों में मानने लगे हैं सैकड़ों करोड़ की संपत्ति जुटा कर धर्म की मर्यादा को तोड़ रहे हैं। आपको पता रहे कि धर्म के दस मूल सिद्धांत शम दम क्षमा धैर्य अस्तेय इंद्रिय निग्रह विद्या पवित्रता सत्य अक्रोध को जीवन में उतारने का अभ्यास करें कथावाचकों की खरपतवार इन धर्म की मूल बुनियाद को आमजन को समझाने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वह स्वयं अपने जीवन में इन सिद्धांतों पर आचरण नही करते और भांति भांति के प्रपंच कर आस्था और श्रद्धा का शोषण कर अपने सुख सुविधा संपन्नता के लिए संपत्ति बटोरने में लगे हुए हैं।

'खिलाड़ी डरते हैं, नहीं जाना चाहते'

मुनाफ पटेल ने लगाए NCA में ठीक से काम न होने का आरोप

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की देखभाल की जिम्मेदारी बेंगलुरु स्थित नेशनल क्रिकेट एकेडमी (अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) पर होती है। सीओई खिलाड़ियों के शरीर और फिटनेस का ध्यान रखता है, चोटिल होने पर वह वही रिहैब करते हैं। भारत के पूर्व क्रिकेटर मुनाफ पटेल ने एनसीए के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बताया कि फिजियो और ट्रेनर जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। मुनाफ ने कहा कि एनसीए को 100 प्रतिशत बदलना होगा। वह आज भी उसी ढर्रे पर चल रहा जिस पर वह 2000 में शुरू होने पर चल रहा था,

जबकि ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की ऐसी व्यवस्था दर्जनों बार बदलाव से गुजरी है।

मुनाफ पटेल ने टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा, 'ईमानदारी से फिजियो और ट्रेनर जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। उनका वर्कलोड बढ़ जाता है। आप सेटअप देखो। आप एनसीए के सेटअप में घुस जाओ आपको पूरा सिस्टम पता चल जाएगा। आपको कहीं और नहीं जाना है। एनसीए को 100 प्रतिशत बदलना होगा। पूरे वर्ल्ड के सिस्टम को बीसीसीआई चला रहा है। मैं इंजर्ड हुआ। मुझे एनसीए जाना है। क्यों जाना है फिट होने के लिए। मतलब मैं ऐसा बॉलर हूं कि मेरी गलती नहीं है। मैं ऐसा बैट्समैन हूं कि मेरी गलती नहीं है तो एनसीए फिटनेस सेंटर रखा हुआ आपने। अस्पताल बन गया है। आप फिट हो जाओ वापस आ जाओ सीधे टीम में हो और वो परमिशन दे रहा है।'

प्लेयर्स भी एनसीए जाने से डरते हैं– मुनाफ पटेल ने कहा, 'एनसीए दे रहा है तो मेरी गलती नहीं है मेरी गलती भी तो सुधारेगा कोई बंदा जो बॉलिंग कोच आपको रखा हुआ है या बैटिंग कोच वहां रखा हुआ है तो आप कितने दिन वर्क करते हो उनके पीछे वो बता दो जरा।

प्लेयर्स भी एनसीए जाने से डरते हैं। कोई जाना नहीं चाहता है। सबकी रोजी रोटी चल रही है। इसलिए सब चुप बैठे हुए हैं किसी को बोलना नहीं है। बोलेंगे तो पंगा हो जाएगा। हालांकि, ऑफिस बियरर को पता चलना चाहिए कि सही क्या और गलत क्या है। वो लोग भी इतने ईगो वाले नहीं है कि मैं खिलाफ बोलूंगा और वो नाराज हो जाएंगे।' मुनाफ पटेल ने कहा, 'आप सही ताओ समझ तो सबको है, लेकिन आप जब तक उनको समझाओगे नहीं अभी जय शाह जैसा इंसान है उनको क्रिकेट नहीं मालूम तो आप उनको समझाओगे न कि सर देखो हम ये करेंगे तो हमारा ये डेवलप हो सकता है। मैं शर्त लगा लूं कि वो तुरंत ओके कर देंगे,लेकिन वहां तक बात पहुंचनी चाहिए न। वहां तक बात पहुंचती ही नहीं कि हमें वहां पे क्या करना है। वहां पे कुछ भी नहीं हो रहा। इंजर्ड हुआ, गए वापस आए।' मुनाफ पटेल ने कहा, 'एनसीए को रीजनल करना पड़ेगा। परफॉर्म किए लोग ही जा रहा हैं। कोई अनपरफॉर्मर नहीं जा रहा है तो मेरे ख्याल से उसका कोई यूज नहीं है। एनसीए के जो 50 एकड़ में आपने बनाया ना वो तो पांच एकड़ में भी हो जाता। मुझे नहीं लगता है कि इतना खर्चा हमें करना चाहिए और वहां रहने के लिए लोग लड़ रहे हैं। मुझे जाना है क्योंकि आराम है न वहां कोई जिम्मेदारी नहीं है।'

लखनऊ सुपर जायंट्स को झटका

ऋषभ पंत चोटिल

आरसीबी के खिलाफ कीपिंग करने नहीं उतरे

नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में बुधवार (15 अप्रैल) को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ लखनऊ सुपर जायंट्स को बड़ा झटका लगा। कप्तान ऋषभ पंत चोटिल होने के कारण कीपिंग करने नहीं उतरे। मुकुल चौधरी ने उनकी जगह कीपिंग की जिम्मेदारी संभाली। पंत की गैर-मौजूदगी में निकोलस पूरन ने कप्तानी की जिम्मेदारी संभाली। पंत को बल्लेबाजी के दौरान बाएं हाथ की कोहनी पर चोट लगी थी। इसके कारण उन्हें रिटायर्ड हर्ट होना पड़ा। बाद में वह बल्लेबाजी के लिए आए, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए।

आरसीबी के खिलाफ मैच में ऋषभ पंत नंबर-3 पर बल्लेबाजी के लिए उतरे। एडेन मार्कराम को रासिख सलाम डार ने चौथे ओवर में पवेलियन भेजा था। उन्होंने 12 रन बनाए थे। पंत ने पांचवें ओवर में पहली गेंद का सामना किया। उन्हें चौथी गेंद पर चोट लगी। हेजलवुड ने ऑफ स्टंप से बागर शॉर्ट गेंद की थी। पंत ने लेग साइड में शॉट लगाने की कोशिश की। गेंद ने बल्ले का किनारा लिया और उनकी कोहनी पर लगकर विकेटकीपर के पास गई।

पंत रिटायर्ड हर्ट

इसके बाद पंत दर्द में दिखे। लखनऊ सुपर जायंट्स के फिजियो पैट्रिक फरहार्ट उनका उपचार करने मैदान पर पहुंचे। दर्द के कारण पंत को बल्लेबाजी छोड़कर पवेलियन लौटना पड़ा। वह 16वें ओवर में आयुष बदोनी के आउट होने के बाद बल्लेबाजी के लिए लौटे। उनकी बाईं कोहनी पर पट्टी बंधी थी।

पंत बल्लेबाजी के लिए लौटे

रसिख सलाम की ऑफ स्टंप से बाहर की फुलटॉस गेंद पर पंत शॉट लगाने से चूक गए। उन्होंने पांचवीं गेंद पर खाता खोला, लेकिन भाग्यशाली रहे कि शॉर्ट थर्ड मैन पर सुयस शर्मा कैच नहीं लपक पाए। पंत को तीन गेंद बाद ही भुवनेश्वर कुमार ने पवेलियन भेजा। डीप मिड विकेट पर फिल साल्ट ने शानदार कैच लपका। इस तरह से पंत 6 गेंद पर 1 रन बनाकर पवेलियन लौटे। लखनऊ सुपर जायंट्स की बल्लेबाजी काफी खराब रही और टीम 146 पर आउट हो गई।

मुंबई इंडियंस को झटक

पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच से बाहर हो सकते हैं रोहित शर्मा

नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच से पहले मुंबई इंडियंस को झटका लगा है। रोहित शर्मा गुरुवार (16 अप्रैल) के मैच से लगभग बाहर हो गए हैं। फिलहाल वह टीम के मेडिकल स्टाफ की निगरानी में हैं। पिछले रविवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ बड़े स्कोर वाले मैच के दौरान मुंबई इंडियंस की पारी के छठे ओवर में रोहित को पैर की मांसपेशियों में परेशानी महसूस हुई थी। इसके बाद वह मैदान से बाहर चले गए थे। रोहित शर्मा रिटायर्ड हर्ट होकर बाहर गए तब वह 13 गेंद पर 19 रन बनाकर खेल रहे थे। इसके बाद मुंबई इंडियंस यह मैच 18 रन से हार गई जो मौजूदा सत्र में टीम की लगातार तीसरी हार थी। मुंबई इंडियंस के ट्रेनिंग सत्र के दौरान बुधवार (15 अप्रैल) को टीम के एक अधिकारी ने रोहित को लेकर कहा, 'मेडिकल टीम और कोचिंग स्टाफ उनकी जांच कर रहे हैं और हमें जल्द ही पता चल जाएगा।'

विल जैक्स जल्द मुंबई इंडियंस से जुड़ेंगे

इस बीच इंग्लैंड के ऑलराउंडर विल जैक्स जल्द ही मुंबई इंडियंस से जुड़ने वाले हैं। वह मौजूदा सत्र में अब तक टीम के चारों मैच से बाहर रहे हैं और गुरुवार (16 अप्रैल) को भी नहीं खेल पाएंगे। जैक्स और न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर (अब तक दो मैच खेले हैं) ने भारत में टीम से जुड़ने से पहले कुछ और समय मांगा था।

आरसीबी ने लखनऊ को 5 विकेट से हराया

29 गेंद पहले मैच खत्म

नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 23वें मैच में बुधवार (15 अप्रैल) को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लखनऊ सुपर जायंट्स (स्त्र) को 5 विकेट से हरा दिया। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। लखनऊ सुपर जायंट्स 146 रन पर आउट हुई। लखनऊ के लिए मिचेल मार्श, मुकुल चौधरी और आयुष बदोनी ही 30 का आंकड़ा पार कर पाए। 147 रन के लक्ष्य के जवाब में आरसीबी ने 15.1 ओवर में 5 विकेट पर 149 रन बना लिए। चोट के कारण इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर खेले विराट कोहली ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। आरसीबी इस जीत के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंची।

ऋषभ पंत चोटिल होकर रिटायर्ड हर्ट हुए। बाद में बल्लेबाजी के लिए आए, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए। आरसीबी के लिए रसिख सलाम डार और भुवनेश्वर कुमार

ने शानदार गेंदबाजी की। जोश हेजलवुड ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया।लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए मिचेल मार्श ने 32 गेंद 40 रन बनाए।

मकुल चौधरी ने 28 गेंद पर 39 रन बनाए। आयुष बदोनी ने 24 गेंद पर 38 रन बनाए। एडेन मार्कराम ने 8 गेंद पर 12 रन बनाए। जॉर्ज लिंडे 7, ऋषभ पंत, निकोलस पूरन और आवेश खान 1-1 रन बनाकर आउट हुए।

अब्दुल समद और मोहम्मद शमी खाता नहीं खोल पाए। दिग्वेश राठी बगैर खाता खोले नाबाद रहे। आरसीबी के लिए रसिख सलाम डार ने 4, भुवनेश्वर कुमार ने 3 और क्रुणाल पंड्या ने 2 विकेट लिए। जोश हेजलवुड को 1 विकेट मिला, लेकिन उन्होंने केवल 20 रन दिए। आरसीबी के लिए विराट कोहली ने 34 गेंद पर 49 रन बनाए। रजत पाटीदार ने 13 गेंद पर 27, जितेश शर्मा ने 9 गेंद पर 23 र बनाए। टिम डेविड और रोमारियो शेफर्ड ने 14-14 रन बनाए। देवदत्त पडिक्कल ने 10 और फिल साल्ट ने 7 रन बनाए।

व्यापार

भारत के बड़े शहरों में होटल के कमरे खाली

नई दिल्ली, एजेंसी। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध की वजह से भारत के कई सेक्टरों पर सीधा असर पड़ा है। होटल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर भी इससे अछूता नहीं है। बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे जीसीसी शहरों में होटलों की ऑक्यूपेंसी गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। कारण है कि भारत आने वाले ज्यादातर विदेशी यात्री दुबई, अबू धाबी और दोहा जैसे एविएशन हब से होकर आते हैं। जीसीसी यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर ऐसे केंद्र होते हैं जिन्हें बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां (एमएनसी) अपने देश से बाहर दूसरे देशों में स्थापित करती हैं। इनमें हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे, दिल्ली-एनसीआर जैसे शहर शामिल हैं। 28 फरवरी को अमेरिका-इजरायल ने ईरान पर हमले किए। ईरान ने भी पलटवार किया। उसने कई खाड़ी देशों में अमेरिकी अड्डे को निशाना बनाया। इससे यह संकट पूरे क्षेत्र में फैल गया। इसने हवाई यातायात को भी प्रभावित किया। शैले होटल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ श्वेतांक सिंह ने बिजनेस टुडे को बताया, 'पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध की वजह से होटल बिजनेस पर असर पड़ा है। विदेशी पर्यटकों के आने में कमी आई है। इसका असर बड़े शहरों के बड़े होटलों की ऑक्यूपेंसी पर पड़ा है।' सिंह ने कहा, 'मिडिल ईस्ट के रास्ते यात्रा करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। अगर मैं अपने पोर्टफोलियो को देखूं तो 40 प्रतिशत बिजनेस विदेशी पर्यटकों से आता है। बड़े शहरों के बड़े होटलों का हिस्सा हमारे पोर्टफोलियो में लगभग 60 प्रतिशत है। साफ तौर पर इसका असर दिख रहा है।' उन्होंने आगे कहा, 'ये यात्री होटल के अंदर ज्यादा खर्च करते हैं। ज्यादा समय तक रुकते हैं। वे अपने साथ एक पूरा ग्रुप लेकर चलते हैं।' सिंह ने बताया, 'हालांकि, लक्जरी रिजॉर्ट का बिजनेस अच्छा चल रहा है।

पीएफ खाते से विड्रॉल टीडीएस बचाने के लिए अब नहीं चलेंगे पुराने फॉर्म

नई दिल्ली, एजेंसी। पीएफ खाताधारकों के लिए टैक्स से जुड़े नियम बदल गए हैं। अब पीएफ से पैसा निकालते समय टीडीएस बचाने के लिए पुराने फॉर्म नहीं चलेंगे। इनकी जगह फॉर्म 121 शुरू किया है। नियम 1 अप्रैल से लागू है। फॉर्म भरने वाले को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी साल भर की टैक्स लायबिलिटी जीरो है। कंपनियां, फर्में और एनआरआई इस फॉर्म को भरने के पात्र नहीं हैं। 13 अप्रैल को जारी अपने सर्कुलर में ईपीएफओ ने बताया कि पहले 60 साल से कम उम्र के लोग फॉर्म 15त्र भरते थे और सीनियर सिटीजन फॉर्म 15॥ का इस्तेमाल करते थे। अब इन दोनों की जगह केवल फॉर्म 121 इस्तेमाल होगा। यह फॉर्म केवल उन लोगों के लिए है जिनकी पूरे साल की कुल अनुमानित कमाई पर टैक्स की देनदारी शून्य है। यानी अगर आपकी सालाना कमाई टैक्स छूट की सीमा से कम है, तो आप इस फॉर्म को भरकर अपनी इनकम बिना ञ्जष्ठस् कटे हासिल कर सकते हैं। ईपीएफओ ने साफ किया है कि यह फॉर्म सबके लिए जरूरी नहीं है। यह केवल उन लोगों के लिए है जो टीडीएस कटने से बचना चाहते हैं। ईपीएफओ ने कहा है कि 1 अप्रैल के बाद अगर किसी ने पुराने फॉर्म के साथ क्लेम फाइल कर दिया है, तो उसे रिजेक्ट करके वापस नहीं भेजा जाएगा। हालांकि, कर्मचारी से फॉर्म 121 लेने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए पीएफ एक अनिवार्य सरकारी बचत योजना है। इसमें कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 12 प्रतिशत हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है जबकि कंपनी भी इतना ही योगदान देती है।

100 करोड़ की डील ने बदली किस्मत! 16 प्रतिशत उछला रियल एस्टेट स्टॉक

नई दिल्ली, एजेंसी। रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनी सूरज एस्टेट डेवलपर्स के शेयरों में हाल ही में जबरदस्त तेजी देखने को मिली, जिसने निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कंपनी के शेयर एक

ही दिन में करीब 16 प्रतिशत तक उछल गए, जिसकी सबसे बड़ी वजह मुंबई के दादर (वेस्ट) इलाके में एक नई लैंड डील है। कंपनी ने इस जमीन को करीब 18 करोड़ की कुल लागत (कैश + एरिया) में हासिल किया है, जबकि इस प्रोजेक्ट से संभावित ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू करीब 100 करोड़ बताई जा रही है। आसान भाषा में समझें तो कंपनी इस जमीन पर नया प्रोजेक्ट बनाकर लगभग 100 करोड़ का बिजनेस करने की उम्मीद कर रही है, जो निवेशकों के लिए पॉजिटिव संकेत माना जाता है। यह जमीन मुंबई के दादर जैसे प्राइम लोकेशन में है, जहां रियल एस्टेट की डिमांड हमेशा बनी रहती है। कंपनी इस प्लॉट पर री-डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू करेगी, जिसमें करीब 0.18 लाख स्क्वॉयर फीट का सेलएबल एरिया तैयार किया जाएगा, यानी कंपनी पुराने स्ट्रक्चर को हटाकर नया प्रोजेक्ट बनाएगी और उसे बेचकर मुनाफा कमाएगी।

डायबिटीज के आंकड़ों ने दिया आइडिया, नौकरी को मारी लात, अब सालाना 2 करोड़ की कमाई

नई दिल्ली, एजेंसी। हर्षवर्धन एस बेंगलुरु के रहने वाले हैं। नौकरी छोड़कर उन्होंने सफल ब्रांड खड़ा कर दिया है। भारत में डायबिटीज के डरावने आंकड़ों और खान-पान की गलत आदतों ने उन्हें इसका आइडिया दिया। उनके ब्रांड का नाम लिल गुडनेस है। इसकी नींव उन्होंने अपने दोस्त दमनबीर सिंह के साथ डाली। यह ब्रांड हेल्दी स्नैक्स और पोषण से भरपूर फूड आइटम बेचता है। अब वे इससे सालाना 2 करोड़ की कमाई कर रहे हैं। आइए, यहां हर्षवर्धन एस की सफलता के सफर के बारे में जानते हैं। हर्षवर्धन एस पहले टाटा हेल्थ में नौकरी करते थे। जॉब के दौरान तेलंगाना सरकार के साथ मिलकर किए गए एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम ने उनकी आंखें खोल दीं। करीब 13 लाख लोगों की जांच में 2,600 लोग गंभीर डायबिटीज से पीड़ित पाए गए। बड़ी बात यह कि उन्हें अपनी बीमारी का अंदाजा तक नहीं था।

इस बात पर किया फोकस

हर्षवर्धन ने हेल्थ के साथ टेस्ट के कॉम्बिनेशन पर फोकस किया। 'प्रीबायोटिक डार्क चॉकलेट' पेश की। इसकी कीमत सिर्फ 20 रुपये रखी गई। मकसद था कि हर तबके तक यह पहुंचे। इसके अलावा उनके उत्पादों में क्विनोआ और टेफ जैसे सुपर ग्रेस से बने स्नैक्स और 40 प्रतिशत कम चीनी वाले मिल्क शेक शामिल हैं।

2020 में रखी ब्रांड की नींव

हर्षवर्धन के इस सफर में एक बड़ा मोड़ तब आया जब उसी साल वह एक बेटी के पिता बने। एक पिता के तौर पर वह चाहते थे कि उनकी बेटी को बचपन से ही बाजार में उपलब्ध मिलावटी और बहुत ज्यादा शुगर वाले स्नैक्स के बजाय हेल्दी ऑप्शन मिलें। उन्होंने महसूस किया कि बाजार में मिलने वाली सस्ती चॉकलेट्स में सिर्फ शुगर और वेजिटेबल फैट होता है। वहीं, हेल्दी ऑप्शन आम आदमी की जेब से बाहर हैं। इसी कमी को दूर करने के लिए उन्होंने 2020 में अपने साथी दमनबीर सिंह के साथ मिलकर लिल गुडनेस की शुरुआत की।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सैयद ज़की हैदर के लिए इरानीयन आर्ट प्रिंटर्स 1534 कासिमजान स्ट्रीट दरियागंज नई दिल्ली 11006 से मुद्रित कराकर, 2684 गली काले खां कूचा चलान दरियागंज नई दिल्ली 02 से प्रकाशित किया।
संपादक : सैयद ज़की हैदर- हैड ऑफिस :- एफ19/4 सेकेंड फ्लोर नफीश रोड जामिया नगर दिल्ली- 110025., सम्पर्क सूत्र :- 9911371802, 9810383593
जितेन्द्र कुमार बिस्वाल ब्यूरो चीफ उड़ीसा/ गोविंद कनोडिया/ पटना/ सैय्यद यूसुफ अली नक़वी-पॉलिटिकल एडिटर। ई-मेलः- (LOKTANTRAKISHAAN@GMAIL.COM

किसी भी प्रकार के विवाद हेतु निपटारे के लिए केवल दिल्ली न्यायालय ही मान्य होगी।
नोट- किसी भी समाचार/आलेख पर दावा प्रति दावा/आपत्ति समाचार प्रकाशन के 15 दिनों के अन्तराल तक ही मान्य होगा। समाचार पत्र में प्रकाशित आलेख से संपादक/प्रकाशक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

क्षेत्रीय कार्यालय अनवार मंजिल नया टोला गंज नंबर 01 बेतिया/ बिहार/ पिन नंबर 84 5438/>> संवाददाता, सना खान/(डॉ. अमानुल हक) स्थानीय संपादक/बिहार)